हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 02 मार्च, 2022 को माननीय अध्यक्ष, श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 10.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

02-03-2022/1000/एन.जी.-ए.जी. /1

अध्यक्ष : सर्वप्रथम सभी माननीय सदस्यों को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत-बहुत बधाई। मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि दिनांक 26-02-2022 को माननीय सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुरूप दिनांक 28-02-2022 व 02-03-2022 के लिए निर्धारित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे हुए समझें जाएं। अब माननीय मुख्य मंत्री जी इस माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगे।

मुख्य मंत्री.....श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

02.03.2022/1005/AG/JS/1

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री इस माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे अवगत करवाएंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जोकि इस प्रकार है :-

बुधवार, 02 मार्च, 2022 - 1. शासकीय/विधायी कार्य।
2. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण।

वीरवार, 03 मार्च, 2022 - 1. शासकीय/विधायी कार्य।
2. गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस।

शुक्रवार, 04 मार्च, 2022 - 1. बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2022-2023 - प्रस्तुतीकरण।

शनिवार, 05 मार्च, 2022 - 1. शासकीय/विधायी कार्य
2. बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2022-2023 -
सामान्य चर्चा।

02.03.2022/1005/AG/JS/2

अध्यक्षः अब माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी। आज ही मुख्य मंत्री जी के भाषण से चर्चा का समापन होगा। लगभग 10.45 बजे पूर्वाह्न माननीय मुख्य मंत्री जी माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का उत्तर देंगे। इसलिए मेरा माननीय सदन से निवेदन है कि कृपया जो आबंटित समय है, उसी में अपनी बात को संक्षेप में रखें ताकि मुझे बार-बार वाइंड अप न कहना पड़े या यहां से बैल न बजानी पड़े । अब इस चर्चा में श्री जगत सिंह, माननीय सदस्य भाग लेंगे।

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के तहत माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण इस माननीय सदन में दिया है, उसी पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का किस मुंह से धन्यवाद करूं और किस काम के लिए धन्यवाद करूं? क्या इसलिए धन्यवाद करूं कि आपने अच्छे दिन लाने के वायदे किए थे और बुरे दिन ला दिए? क्या मैं इसलिए आपका धन्यवाद करूं कि आपने मंहगाई डायन को अपनी मौसी बना दिया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो पैट्रोल 55 रुपये का था, उसको अपने 112 रुपये कर दिया। डीजल जो कभी 45 रुपये का था, उसको अपने 100 रुपये तक ला दिया। सीलेंडर जो कभी 400 रुपये का था, उसको आपने 1200 रुपये तक पहुंचा दिया। सरसों का तेल जो 70 रुपये था, वह 210 रुपये में पहुंचा दिया। दालें जो 70 रुपये प्रति किलो थी, उनको आपने 150 रुपये से ऊपर पहुंचा दिया। स्टील जो 3500-3600 रुपये क्विंटल मिलता था, उसको आपने 6000 रुपये क्विंटल से ऊपर कर दिया। हमारे

देश में जो कर्ज़ ढाई लाख करोड़ था, उसको 26 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। प्रदेश का कर्ज़ जो 25-30 हजार करोड़ के आसपास था, उसको आपने 75 हजार करोड़ के आसपास तक पहुंचा दिया, क्या मैं इन बातों के लिए आपका धन्यवाद करूं? क्या यह धन्यवाद करने की बात है, जो यहां इस अभिभाषण में बातें लाई गई हैं? इसी तरह से आपने

02.03.2022/1005/AG/JS/3

प्रदेश में 14 लाख से ऊपर तक बेरोजगारों की फौज़ खड़ी कर दी। क्या उस बात के लिए आपका धन्यवाद करूं? देश में 40 करोड़ गरीब थे अब यशस्वी प्रधान मंत्री, विश्व गुरू के राग में 80 करोड़ लोग गरीबी के रेखा के नीचे आ गए हैं, क्या इस बात के लिए आपका धन्यवाद करूं? मैं किस बात के लिए धन्यवाद करूं मुझे बहुत ही कठिन लग रहा है और इस धन्यवाद प्रस्ताव में किस तरह से अपने आपको सम्मिलित करूं? क्या मैं इसलिए आपका धन्यवाद करूं कि कोरोनाकाल में आपने हिन्दुस्तान के लाखों लोगों की जान गंवाई और हिमाचल प्रदेश में भी साढ़े चार हजार से ज्यादा लोगों की जान गई हैं?

श्री एस.एस. द्वारा जारी------

02.03.2022/1010/SS-AS/1

श्री जगत सिंह नेगी क्रमागत :

अब आप कह रहे हैं कि कोरोना के समय में बहुत बड़ा काम हुआ। यह ठीक है किसी को पता नहीं होता कि महामारी कब और कैसी आएगी। परन्तु जब महामारी आ गई, आपदा आ गई तो उसके लिए आपके पास आपदा प्रबंधन विभाग है। उसके लिए आपके पास पैसे हैं और किस तरह से आपने आपदा से निपटा है उस पर प्रश्नचिन्ह है। आप उस आपदा व कोरोना के समय निकम्मे साबित हुए। ---(***)---आपने हॉस्पिटल में बैड्स का इंतजाम नहीं किया। आपने एम्बुलैंस का इंतजाम नहीं किया। जो लॉकडाउन समय पर लगना चाहिए था उसको आप नमस्ते ट्रम्प और मध्यप्रदेश की सरकार को गिराने के चक्कर में

टालते रहे। ऐसे समय में आपने लॉकडाउन कर दिया कि लोगों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को बेरोज़गार होना पड़ा। लोगों को मजबूर होकर चिलचलाती धूप में नंगे पांव हजारों किलोमीटर पैदल चलकर गांव जाना पड़ा। क्या मैं आपका इन बातों के लिए धन्यवाद करूं। आपने कोरोनाकाल में वीडियो कॉंफ्रैंसिंग के सिवाय लोगों का कोई काम नहीं किया। क्या मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करूं कि आपने कोरोना के समय बहुत बड़ा घोटाला किया। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि आपदा में अवसर ढूंढो, आपने बहुत बढ़िया अवसर ढूंढ लिया। आपकी नाक के नीचे सचिवालय में जो मास्क 5 से 10 रुपये का आता था उसको 50-50 रुपये में खरीद लिया। जो सैनिटाइजर की छोटी शीशी 5 या 10 रुपये में मिलती थी उसको आपने 150 रुपये से ऊपर कर दिया। जब यह लॉकडाउन लगा तो आपने एक-दो हफ्ते के अंदर 10 करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला कर दिया। लोग मर रहे थे लेकिन उनको राहत देने के बजाय आप धन कमाने में लगे हुए थे। क्या आपको इस बात का धन्यवाद किया जाए? तो आपको धन्यवाद किस चीज़ का किया जाएगा? यह बात मेरी समझ से बाहर है। आपने माफियों को गले लगा लिया। शराब माफिया को गले लगा लिया। रेता माफिया को गले लगा लिया। आपने ट्रांसफर माफिया को गले लगा लिया। आपने अपने दृष्टिपत्र में बड़ी-बड़ी बातें कही थीं। लेकिन आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अपने दृष्टिपत्र को ही भूल गए। आप अपने

---(***)---अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

02.03.2022/1010/SS-AS/2

दृष्टिपत्र का ज़िक्र करना भूल गए। आपको बातें करना तो बहुत अच्छा लगता है। आपने स्वर्णिम हिमाचल दृष्टिपत्र का ज़िक्र किया लेकिन उस दृष्टिपत्र का क्या हुआ? वह तो अदृश्य हो गया है। उसका राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ही ज़िक्र नहीं था। वह दृष्टिहीन हो गया। मतलब यह कि मंदबुद्धि तो है ही, क्या अंधे हो गए कि वह दृष्टि ही नहीं रही? तो किस तरह से हम आपका धन्यवाद करें, यह हमारी समझ से बाहर है। अभी यहां पर बहुत सारी बातें कही गई हैं कि हिमाचल प्रदेश में बड़ा भारी विकास हुआ है। हम चार

सालों से आपके विकास का इंतजार करते रहे। हमने आपको समय दिया। हमने कहा कि चलो आपको थोड़ा समय दें, देखते हैं कि आप कैसा विकास करते हैं लेकिन चार साल बाद जो आपने विकास पैदा किया, एक तो वह अधमरा है और दूसरा कुपोषित है। वह हमारे किसी काम का नहीं है। विकास की बड़ी-बड़ी बातें हुई थीं। उल्टा जो हमारा बढ़िया विकास था, बलिष्ठ था, पूरे यौवन पर था; आपने उसको भी मार दिया। आपने हमारे विकास को भी खत्म कर दिया। आज हमें अफ़सोस इस बात का है कि जो आपने बड़ी-बड़ी बातें की थीं आप उस पर खरे नहीं उतरे। आपने कहा था कि सबका साथ सबका विकास होगा, आप बताइए कि उसका क्या हुआ? आपने पूरे हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्रों में से सिर्फ एक या दो निर्वाचन क्षेत्रों का विकास किया। सारी-की-सारी सोच, सारा-का-सारा बजट सिर्फ दो निर्वाचन क्षेत्रों तक सीमित रखा गया। यहां तक कि धन के आबंटन में भी आपने पक्षपात किया।

जारी श्रीमती के0एस0

02.03.2022/1015/केएस/एएस/1

श्री जगत सिंह नेगी जारी----

उसमें भी आपने छोटी सोच रखी। जहां मैं अपने जनजातीय क्षेत्र के विकास की बात करुं यह पहली सरकार है जिसने जनजातीय क्षेत्र के विकास का भट्टा फ्लैट कर दिया। मुख्य मंत्री जी हैलीकॉप्टर में उड़ते रहे। इनको जनजातीय क्षेत्रों में पैदल जाने का समय ही नहीं मिला। चुनाव के समय आए वह भी हैलीकॉप्टर से आए, यहां तक कि इनको वहां पर शिलान्यास करने का समय भी नहीं मिला और शिमला में बैठकर ऑनलाइन इन्होंने शिलान्यास किया। हमारे जनजातीय क्षेत्रों में तो आपके पांच साल का यह कार्यकाल काले इतिहास में लिखा जाएगा कि हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों का किस तरह से आपके

शासन काल में विनाश हुआ है। आपने जो 2200 करोड़ रुपये के सप्लीमेंट्री बजट का यहां पर प्रस्ताव रखा, आपने जनजातीय क्षेत्रों को कितना दिया?

अध्यक्षः माननीय सदस्य, वाइंड अप कर दें। आप सभी से मेरी इस बारे में चैम्बर में बैठकर बात हुई है। लीडर ऑफ अपोजीशन भी वहां पर थे । कृपया वाइंड अप कर दें।

श्री जगत सिंह नेगीः सर, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात करने पर 9 मिनट में ही आप मुझे रोके जा रहे हैं? 2200 करोड़ रुपये में से केवल 4000 रुपये जनजातीय क्षेत्रों के लिए दिए। वह भी चंबा पांगी में बांटना है, लाहौल-स्पिति व किन्नौर में बांटना है और उसमें भी 67 परसेंट आप ईयर मार्किंग करते हैं। हम तीनों के हिस्से में तो शायद 10-10 रुपये भी नहीं आए। यह है जनजातीय विकास । आपने जनजाति उप-योजना का नाम बदल दिया जिसमें आप माहिर हैं। आपने जनजातीय विकास कार्यक्रम नाम रख दिया और यह कैसा बढ़िया कार्यक्रम है जहां 2200 करोड़ रुपये में से 4000 भी हमारे हिस्से में न आए? यह आपका विकास है, इसकी मैं यहां पर चर्चा करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरा हिमाचल प्रदेश आपके शासन में आंदोलित है। लाखों सरकारी कर्मचारी सड़कों पर हैं। कर्मचारियों का एक वर्ग नहीं, सभी वर्ग आज सड़क पर हैं। ओल्ड पैंशन, आउटसोर्स, आंगनबाड़ी, जुनियर ऑफिस

02.03.2022/1015/केएस/एएस/2

असिस्टैंट्स,टीचर्ज़, डॉक्टर्ज़ आदि सारे कर्मचारी आज सड़कों पर हैं और आप उनकी बात नहीं सुनना चाहते। आपके पास उनकी बात सुनने को समय नहीं है लेकिन मुख्य मंत्री जी के पास माननीय यशस्वी प्रधान मंत्री जी के मन की बात सुनने के लिए समय ही समय है। रविवार को बड़ा टैलीविज़न लगाकर अखबारों व टैलीविज़न के माध्यम से प्रचार हो रहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी किस तरह से मन की बात सुन रहे हैं। ठीक है, आप मन की बात सुनिए परन्तु जनता के मन की बात भी सुनिए। काम की बात भी कीजिए। आप

काम की बात कब करेंगे? मुख्य मंत्री जी, आजकल तो आप बहुत ही गुस्सा कर रहे हैं। 70 साल से हम बी.जे.पी. का गुस्सा ही सहन करते आ रहे हैं और आपने इन 70 सालों में किया ही क्या है? बी.जे.पी. ने सिर्फ गुस्सा करना ही सीखा है और देश को एक झूठा विचार परोसने की कोशिश की है। आज आप कहते हैं कि आंदोलन नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान में शांतिपूर्वक तरीके से हमें आंदोलन करने का अधिकार है। आप हमें आंदोलन से नहीं रोक सकते और यह आंदोलन की ही ताकत है कि इस देश के विश्वगुरु प्रधान मंत्री को भी किसानों के आगे झुकना पड़ा। किसानों ने एक साल आंदोलन किया। 700 लोगों ने अपनी जान गंवाई और अंत में जा कर विश्व गुरू को माफी मांगनी पड़ी। यशस्वी प्रधान मंत्री को किसानों के काले कानून वापिस लेने पड़े। आज हिमाचल प्रदेश में भी पुलिस, होमगाड्र्ज़, किसान/बागवान आदि सारे आंदोलन कर रहे हैं। आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। जो धमकी देते हैं आप उनकी बात सुनते हैं। स्वर्णों ने धर्मशाला में धमकी दी कि फ्लां तारीख को अगर आप नोटिफिकेशन नहीं करेंगे तो हम आपका घेराव करेंगे। आपने उनकी बात मान ली और आपने भीड़ में कहा था कि हम नोटिफिकेशन कर रहे हैं। डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी, उन्होंने कहा कि अगर 26 तारीख तक नोटिफिकेशन नहीं हुई तो हम सेवाएं देना बिल्कुल बंद कर देंगे, आपने उनकी बात मान ली। इसका मतलब यह है कि आंदोलन नहीं करना है शांतिपूर्वक तरीके से आपको धमकी देनी पड़ेगी, तभी आप काम करेंगे यह आपने हमें सिखाया है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

02.03.2022/1020/av/dc/1

श्री जगत सिंह नेगी---------- जारी

इसका मतलब तो यह हुआ कि शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन नहीं करना बल्कि आपको धमकी देनी पड़ेगी और आपकी सरकार तभी काम करेगी; हमें आपने यह सिखाया है। यहां पर आपके पक्ष के लोग सर्जिकल स्ट्राइक की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थें। मैं कहता हूं कि

सर्जिकल स्ट्राइक होती थीं और हमारे बालाकोट में भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई मगर उसका क्या फायदा हुआ यानी उसमें 38 आतंकवादी मरे या 300 मरे; यह भी एक शोध का विषय है। उस सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान ने हमारा 700 करोड़ रुपये का लड़ाकू विमान मार गिराया। उन्होंने हमारे पायलट को जिंदा पकड़कर दुनिया को यह दिखा दिया कि हमने हिन्दुस्तान का विमान गिराकर उसके पायलट को जिंदा पकड़ कर छोड़ा है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि जिस दिन बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उसी दिन हमारे से एक बड़ी भारी चूक हुई थी और हमारे वायु सेना के 7 अधिकारियों को हेलीकॉप्टर में जान गंवानी पड़ी। उस सर्जिकल स्ट्राइक में हमें इतनी बड़ी कीमत देनी पड़ी। आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, अगर सर्जिकल स्ट्राइक करनी ही है तो आज यूक्रेन में जाकर कीजिए। वहां आज हमारे 18,000 से अधिक बच्चे गोला-बारूद के बीच में फंसे हुए हैं। वहां पर यूक्रेन की सेना उनके साथ मार-पिटाई के साथ-साथ बद्तमीजी भी कर रही है। ...व्यवधान... वे बच्चे वहां पर भूखे तड़प रहे हैं, आप उनको बचाइए। ...व्यवधान...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलिए। ...व्यवधान... आप अपनी बात समाप्त करें। ....घंटी....

श्री जगत सिंह नेगी : आपकी पार्टी के लोगों ने देश के अंदर झूठा प्रचार किया। आपने एक चाय वाले को यशस्वी बताकर उसे विश्व गुरू बना दिया। क्या विश्व गुरू इस प्रकार का होता है? देश में पूर्व सरकार के कार्यकाल में आरंभ की गईं योजनाओं का नाम बदलकर आप विश्व गुरू नहीं बन सकते। कांग्रेस पार्टी की सरकार में शुरू की गई 35 बड़ी-बड़ी योजनाओं जिनका श्रेय आप ले रहे हैं; क्या उनके नाम

02.03.2022/1020/av/dc/2

बदलकर आप विश्व गुरू बन जाएंगे? आप इसमें (कागज से पढ़ते हुए कहा।) पढ़िए; सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जिसका नाम आपने मिशन इंद्रधनुष रखा। कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में व्यापक फसल योजना था उसका नाम बदलकर आपने प्रधान मंत्री

फसल योजना रखा। इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना रखा। ...व्यवधान...राजीव गांधी खेल योजना बदलकर खेलो इंडिया योजना रखा। ...व्यवधान... अमृत मिशन ...व्यवधान... बुनियादी बचत योजना को जन-धन खाता, ...व्यवधान...

शहरी विकास मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और माननीय सदस्य पूरे हिन्दुस्तान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं। इनके द्वारा कही गई सारी-की-सारी बातें एक्सपंज की जानी चाहिए। ...व्यवधान...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए। आप अभिभाषण पर बोलिए। ...व्यवधान... आप बैठ जाइए, आपका समय समाप्त हो गया है। ...व्यवधान... माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए। ...व्यवधान... आप बैठ जाइए, आप जो बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी, आप बैठिए। ...व्यवधान...

टी सी द्वारा जारी

02/03/2022/1025/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

अध्यक्ष .. जारी

आप बैठिए ... व्यवधान... माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह जी आप बैठिए। ...व्यवधान... आप इस चेयर को डिक्टेट मत कीजिए। आप बैठिए। ...व्यवधान... माइक कब चालू करना है, यह चेयर को देखा है। अब चर्चा में माननीय सदस्य, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी भाग लेंगे।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, सभी ने 25-25 मिनट बोला है। इनको कनक्लूड करने दीजिए। यहां पर बाकी सदस्य आधा-आधा घण्टा भी बोले हैं। इनको कनक्लूड करने दीजिए। ...व्यवधान...

अध्यक्ष : आप बैठिए। परसों जब चैंम्बर में बैठे थे तो यही तय हुआ था और फिर जो तय हुआ है उसको यहां इम्प्लीमेंट भी करना है। ...व्यवधान... मैं इसमें मण्डी की बात नहीं जोड़ना चाहता हूं। लेकिन आपके साथ तय क्या हुआ था? श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ...व्यवधान... श्री जगत सिंह नेगी जी एक मिनट में कनक्लूड कर दीजिए।

श्री जगत सिंह नेगी : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे कनक्लूड करने के लिए कम-से-कम 5 मिनट दीजिए। ---(***)---यह सही है कि पहले हम लड़े थे अंग्रेजों से और अब हमें लड़ना पड़ेगा लुटेरों से। यहां पर इनके द्वारा शोर मचाने से यह लग रहा है कि हमारी बात में दम है इसलिए हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। ये हमारी आवाज को रोकना चाहते हैं। यहां पर चाटुकारिता दिखाई जा रही है और किसी को यशस्वी तो किसी को विश्व गुरु बना रहे हैं। मैं कहना चाहूगांः-

चाटुकारिता के बाजार में मैंने सौदे बदलते देखा है,
खरे सिक्कों से कहीं ज्यादा, मैंने खोटे सिक्कों को चलते हुए देखा है।

---(***)---अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

02/03/2022/1025/टी0सी0वी0/डी0सी0/2

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया। ये मण्डी की गली-गली में लोगों का दर्द पूछने नहीं गए बल्कि लोगों को निमंत्रण देने के लिए गए कि प्रधान मंत्री जी आ रहे हैं, आप वहां आइये। क्या आज तक हिन्दुस्तान में कभी ऐसा हुआ कि मुख्य मंत्री जी भीड़ जुटाने के लिए कभी गली-गली में गए हों? इन्होंने शिव का त्रिशुल

यशस्वी जी को दे दिया। अच्छा होता यदि डगरू भी साथ दे देते ताकि यशस्वी जी कैलाश पर्वत पर चले जाते।

एन0एस0 द्वारा .... जारी

02-03-2022/1030/NS/HK/1

श्री जगत सिंह नेगी .....जारी

जिनपिंग के साथ 18 बार गए। ...व्यवधान... एक गुफ़ा उनको मिल जाती और हम इस देश को कंगाली से बचाते। ...व्यवधान... यह करते, वहां यह करने की जरूरत थी। मुझे अफ़सोस है मैं जिन विषयों को यहां उठाना चाहता था, मुझे उठाने नहीं दे रहे हैं। आप मुझे मौका ही नहीं दे रहे हैं या मुझे कोई अलग से तरीका बताईए कि मैं अपनी बात रखूं। अध्यक्ष महोदय, जनजातीयों को तो आरक्षण है संविधान ने भी दिया है और आप भी मुझे आरक्षण दें। आप पांच मिनट समय को दस मिनट कीजिए, कुछ तो कीजिए, कुछ तो मेरी बात सुनिए। ...व्यवधान... नहीं तो यह सारा रह जाएगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, 20 मिनट का समय हो गया है। आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री जगत सिंह नेगी : अध्यक्ष महोदय, शहरी विकास मंत्री जी हर बात पर उछलते हैं। कहीं इनकी सीट के नीचे कोई करंट तो नहीं लगा हुआ है। शायद इनका जाने का समय आया है इसलिए उछलते हैं। इनके पास शहरी विकास विभाग है। मैंने प्रश्न लगाया था कि 'प्रधान मंत्री आवास योजना' के तहत हिमाचल प्रदेश के कितने रैन बसेरे बड़े/छोटे शहरों में बनाए गए हैं और कितने शौचालय बनाए गए हैं तथा कितने रैन बसेरों में खाने की व्यवस्था उपलब्ध है? शिमला शहर का यह हाल है और मैंने स्वयं इसकी फोटोज़ निकाली हैं। आज भी शिमला के अंदर बहुत सारे गरीब लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। मैंने इन फोटोज़ को हाउस में ले किया है। नंगे, भूखे और सिर के ऊपर छत नहीं है। मैं आपको किस चीज़ के लिए धन्यवाद करूं इसलिए कि लोग भूखे और नंगे मर रहे हैं। क्या इसके लिए धन्यवाद करूं?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कनक्लूड करें। आप बैठ जाइए। आपकी बात आ गई है कृपया बैठ जाइए।

श्री जगत सिंह नेगी : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह सरकार समझाए कि धन्यवाद कैसे करूं तभी मैं धन्यवाद करूंगा। आपने मुझे समय कम दिया उसके लिए धन्यवाद।

02-03-2022/1030/NS/HK/2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपको पूरे 22 मिनट बोलने के लिए दिए हैं। अब इस चर्चा में श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी भाग लेंगे। आप बैठिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष जी, हालांकि श्री जगत सिंह नेगी जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं लेकिन कुछेक बातें इन्होंने बहुत आपत्तिजनक बोली हैं। इनका पूरा भाषण ए से लेकर जेड तक झूठ का पुलिंदा है। कोविड प्रबंधन को ले करके इन्होंने कुछ प्रश्न उठाए हैं। **अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि आपने लोगों को मरने के लिए अस्पतालों में भेज दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इनके ये शब्द सदन की कार्यवाही से निकाले जाएं।** ...व्यवधान...

अध्यक्ष : मैं सारा रिकॉर्ड देखूंगा और असैंवाधानिक शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाएगा। ...व्यवधान... श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने बीच में कम टोकना है। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, किसी सरकार की कार्यप्रणाली किस चीज़ से आंकी जाती है? अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। गुड गवर्नमैंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। इस अभिभाषण में गवर्नेंस नाम का कहीं शब्द न तो हमें दिखाई देता है और न ही इस सरकार के पिछले साढ़े चार सालों में गवर्नेंस रही है। अगर गवर्नेंस होती तो इस शब्दकोष में जो इन्होंने सेवा और समृद्धि का शब्द लिखा है उसका स्वरूप कुछ और होता। पिछले साढ़े चार सालों से हिमाचल प्रदेश में माफ़ियों का विकास हुआ है। इसी माफ़िया विकास के कारण जो हिमाचल देव भूमि के नाम से जाना जाता है वहां शराब कांड हुआ। हिमाचल के माथे पर शराब के कारण आठ लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति अभी भी कोमा में है। हिमाचल में यह आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है और यहां पर सरकार किसकी,

भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अध्यक्ष महोदय, तकलीफ़ और परेशानी तो होगी, मैं यह बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो शराब कांड हुआ इसके लिए

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

02.03.2022/1035/RKS/HK-1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु... जारी

इस शराब के गोरखधंघे को बंद किया जाए। यह 16 अगस्त, 2021 से पहले यानी जहरीली शराब पीने से हुई मौतों से पहले की बात है। इसके लिए मैमोरेंडम भी दिया गया। जब सलापड़ पुलिस ने शराब की 6 पेटियां बरामद की तो उस समय पुलिस को किसी नेता ने फोन किया और कहा कि जो शराब की 6 पेटियां पकड़ी गई हैं उन्हें दोबारा उसी के पास छोड़ दिया जाए। फिर पुलिस वाले उन पेटियों को नाई की दुकान में छोड़ने जाते हैं। जब पूर्व विधायक, श्री सोहन लाल ठाकुर व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, सुन्दरनगर के पदाधिकारियों ने इसके बारे में मैमोरेंडम दिया तो भी सरकार के कान नहीं खुले। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो क्राइम रोकने वाली इम्प्लिमेंटिंग एजेंसी है, वह उस वक्त कहां थी? आपने एस.आई.टी. का गठन किया लेकिन एस.आई.टी. में आपने उसी क्षेत्र के डी.एस.पी. को तैनात कर दिया। आप एक अधिकारी का नाम बता दीजिए जिसके ख़िलाफ आपने शराब कांड के लिए कार्रवाई की हो? सात लोगों की मृत्यु हो गई, पैसा कमाने वाला व्यक्ति चला गया लेकिन सरकार अब भी सोई हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी मण्डी आपका गृह ज़िला है। आपने गौरव मिन्हास को पकड़ा है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि यह पुलिस की मिली-भगत और राजनीतिक संरक्षण द्वारा ही संभव हुआ है। पुलिस की मिली-भगत और राजनीतिक संरक्षण द्वारा ही शराब अवैध रूप से बेची जा सकती है। वर्ष 2019-20 में शराब कांड के किंगपिन, गौरव मिन्हास ऊर्फ गौरू से पालमपुर या धर्मशाल की पुलिस ने पांच स्प्रिट के ड्रम पकड़े थे। पुलिस की मिली-भगत के कारण तीन ड्रम का केस बनाया गया और दो ड्रम छोड़ दिए गए। जब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि क्या आप

अवैध काम करने से डरते नहीं तो उसने कहा कि डर किस बात का जब पुलिस हमारे साथ है। यह अवैध शराब बेचने वाला सबसे बड़ा किंगपिन है तो पुलिस ने उस पर नज़र क्यों नहीं रखी? पुलिस ने उस पर नज़र तो रखी थी परंतु उसके ऊपर जो राजनीतिक संरक्षण था, यह सरकार को बताना चाहिए। आप साढ़े चार वर्षों से सरकार चला रहे हैं।

02.03.2022/1035/RKS/HK-2

सात लोग मौत के मुंह में चले गए लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक भी अधिकारी को गिरफ्तार या सस्पेंड करने में नाकाम रही है। जब किसी अपराधी को पकड़ने के बाद उसकी बेल हो जाती है, जिस गाड़ी में शराब जाती है, वह गाड़ी छूट जाती है तो फिर इस एक्साइज एक्ट का क्या फायदा? अगर इस अभिभाषण में शराब कांड या पिछले चार वर्षों से जो माफिया राज पनप रहा है उसके विरुद्ध कड़े कानून बनाने की बात की होती तो हम आपका धन्यवाद करते। सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए ताकि अवैध काम करने वालों को कानून का डर हो। आज कानून का कोई डर नहीं है। जो अवैध शराब का धंधा करता है उसकी बेल हो जाती है और उसे कोई सजा नहीं मिलती। अगर सरकार बजट सत्र में एक्साइज एक्ट के तहत कड़ा कानून लाएगी तो हम उस बिल का समर्थन करेंगे। आपके शासन में माफिया राज सबसे ज्यादा पनपा है। शराब माफिया, खनन माफिया या फिर ड्रग्स माफिया हो, इन साढ़े चार वर्षों में सबसे ज्यादा माफिया राज पनपा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इन माफियाओं को पनपने में संरक्षण दिया है। माननीय उद्योग मंत्री जी हम सब जानते हैं कि खनन किस प्रकार होता है। रात को खनन बंद किया गया है लेकिन जब एस.पी., हमीरपुर ने रात को रेड डाली तो उस समय 18 टिपर और 7 जे.सी.बी. द्वारा ब्यास नदी के किनारे खनन किया जा रहा था। जब कार्रवाई हुई और गाड़ियां पकड़ी गई तो खनन करने वाले का क्रशर बंद नहीं किया गया।

श्री बी.एस.द्वारा.. जारी

02.03.2022/1040/बी.एस./वाई0के0/-1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जारी...

जिसकी खनन में गाड़ियां और टिप्पर थे, पुलिस ने सख्त कार्रवाई की और माननीय कोर्ट से उन्हें रिलीज करनी पड़ी। महोदय, इतनी मंशा तो उस क्रशर वाले की पता चल जाती है कि वह ब्यास नदी में गैर कानूनी ढंग से खनन कर रहा है, कम-से-कम उसका क्रशर तो बंद कर दिया जाता। सरकार ने ऐसा प्रावधान क्यों नहीं किया कि जो भी गाड़ी शाम को खनन के काम में लाई जाती है, उसको जब्त कर दिया जाएगा। प्रदेश में जब माफियों के साथ कानून लागू करने वाले लोग मिल जाएंगे और कानून का डर ही नहीं रहेगा, तो इस प्रदेश और समाज की चिंता कौन करेगा? नदियों और खड्डों का बुरा हाल हो रहा है और माननीय उद्योग मंत्री जी सोए हुए हैं। आप विधान सभा में सख्त कानून लाइए कि जो भी गैर कानूनी मांइनिंग करेगा और जिसकी जे0सी0बी0 पकड़ी जाएगी, वह छुटेगी नहीं। आज की तरीख में जो भी छोटा-मोटा जुर्माना लगाया जाता है, उसकी लोग परवाह नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि 5 हजार रुपए जुर्माना लगेगा, उसे हम दे देंगे। आज इसे 10 गुना करने की आवश्यकता है। परंतु सरकार की मंशा ही नही है कि हम इस पर रोग लगाएं। यही कारण है कि चार सालों में यह माफिया राज पनपा है।

आप ड्रग्ज की बात कर लीजिए, कौन सा ऐसा गांव और पंचायत है जहां पर नशा नहीं पहुंचा है। पहले जब ड्रग्ज की बात होती थी तो वह ऊना तक ही सीमित होती थी। आज लोग चिट्टे का सेवन कर रहे हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलें।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, मैं अभिभाषण पर ही बोल रहा हूं। महोदय आप उस तरफ के लोगों को भी बोला करें कि समय का ध्यान रखें। चिट्टा आज हर गांव तक पहुंच रहा है। मैं जुब्बल-कोटखाई का एक उदाहरण देना चाहता हूं। उस पंचायत ने यह

निर्णय किया, हिन्दुस्तान टाइम में वह खबर छपि है कि कोई भी बाहर की गाड़ी आएगी या जिस पर शक होगा, उसकी तलाशी ली जाएगी। पिछले साढ़े चार साल में चिट्टे के जितने भी केसिज हैं उनमें यह देखने में आ रहा है कि लड़कियां भी चिट्टे के केसिज में शामिल

02.03.2022/1040/बी.एस./वाई0के0/-2

हो चुकी हैं। परंतु इससे कैसे छुटकारा मिले, किस प्रकार से इससे बचा जा सके, इस सरकार के पास कोई डी-एडिक्शन नहीं हैं, यह सरकार विकास की बात करती है। यह सरकार मजे में चली हुई कि हमारा तो समय बीत चुका है। इन्हें पता लग गया है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट की होती है। यह सरकार मन से हार चुकी है, क्योंकि जो सरकार मन से हार चुकी हो और जो सरकार थक जाए वह सरकार समाज का भला नहीं कर सकती। आपने कहावत भी सुनि होगी कि "मन हारा तो सब हारा, मन जीता तो सब जीता"। आप सेवा करने के लायक नहीं है। ये जो प्रदेश में चार उप चुनाव हुए हैं, हिमाचल की जनता ने आपको बता दिया है कि जनता आपसे कितनी नाराज है और उन्हरोंने कहा कि अभी सरकार के छः महीने है, आप सुधर जाइए। यही नहीं इस सरकार को सफलता की सीढ़ियों में अगर किसी ने पंहुचाया है तो वह सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं। आपने छठा पे कमीशन लागू किया, उसमें आपने सरकारी कर्मचारियों को परेशन कर दिया। उसमें पहली ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन और तीसर ऑप्शन, सरकार ने परेशन ही नहीं किया बल्कि मैं तो कहूंगा कि सरकारी कर्मचारियों को खजल कर दिया है। सरकार भी खजल और मंत्रिमण्डल भी खजल है। इस माननीय सदन में जो भी विधायक बैंठे हैं, उन्हें भी खजल कर दिया है। सरकार यह नहीं समझ पा रही है कि करना क्या है? अध्यक्ष महोदय ,मैं कुछ कर्मचारियों की बात सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं, सरकारी कर्मचारियों ने प्रदेश के विकास के लिए कंधे-से-कंधा मिला करके योगदान दिया है और नेताओं ने भी योगदान दिया है। परंतु हुआ क्या, आपने छठा पे कमीशन लागू किया, उसमें आपने कहा कि हम सभी को देंगे। लेकिन आपने Subordinate Judicial Service जैसे District Attorney, District Court and JMIC Court है उनके लिए आपने छठा पे

कमीशन लागू नहीं किया। तो क्या सरकार खजल नहीं है। आपने छठा पे कमीशन लागू करने से पहले इस सरकार ने उन नेताओं से बात की आपकी पीटर ऑफ में मिटिंग हुई

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

02-03-2022/1045/वाई.के.-ए.जी. /1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु.....जारी

बड़ी-बड़ी बातें की गई कि हम सभी को 6th Pay Commission लागू करेंगे। लेकिन 5th Pay Commission के समय जो गलतियां हो गई थीं उन्हें सुधारा ही नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 01-10-2009 को अधिसूचना जारी हुई कि 5th Pay Commission दिनांक 01-01-2006 से दिया जाएगा, हमारे यहां पर Punjab Pay Commission लागू होता है और पंजाब ने दिनांक 01-10-2011 को एक अन्य अधिसूचना जारी दी कि हमारे यहां पर अब यह Pay Commission लागू होगा। हिमाचल प्रदेश में उस समय जो गलती हो गई थी अब उसे सुधारने की जरूरत है। उस समय हिमाचल प्रदेश में यह हुआ कि जो कर्मचारी रेगुलर या पदोन्नत होंगे उन्हें नया पे-स्केल दो साल बाद दिया जाएगा। कर्मचारी यही तो मांग रहे हैं कि जो विसंगतियां हो गई हैं उन्हें ठीक कर दीजिए और सरकार इसे ठीक करने से कतरा रही है। इसके अलावा कर्मचारी मांग रहे हैं कि 4-9-14 लागू कीजिए और सरकार वह भी लागू नहीं कर रही है। मेरा केवल इतना ही कहना है कि 5th Pay Commission में जो विसंगतियां रह गई थीं उन्हें 6th Pay Commission में ठीक करने की जरूरत है लेकिन सरकार खज्जल है और इन्हें ठीक नहीं कर रही है। हम इस माननीय सदन में ठोक बजा कर कहना चाहते हैं कि वर्ष 2003 के बाद चाहे कोई बेलदार, जलवाहक, कनिष्ठ सहायक, अधिक्षक लगा हो या अन्य बोर्डों व निगमों के कर्मचारी लगे हों, हिमाचल प्रदेश के हमारे घोषणा पत्र में भी यह होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार आने बाद उन सभी को पुरानी पैंशन योजना लागू की जाएगी। हमारी पार्टी की सरकार ने इसे राजस्थान में लागू कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, वह भी एक समय था जब प्रदेश में लगभग 2,50,000

कर्मचारी हुआ करते थे और उन्हें भी हम पैंशन देते थे लेकिन आज तो यह पैंशन लगभग 1,30,000 कर्मचारियों को ही देनी है। हम स्वयं सरकारी कर्मचारी के बच्चे हैं और हम जानते हैं कि आज के समाज व समय में बच्चे अपने घरों में नहीं रह रहे हैं और छोटे-छोटे परिवार हो गए हैं।

02-03-2022/1045/वाई.के.-ए.जी. /2

यदि एक कर्मचारी को यह आशा बंध जाती है कि सेवानिवृति के बाद मेरे घर में हर माह पैंशन का पैसा आएगा तो वह अपने परिवार का पालन-पोषण आराम से कर सकता है। वह सेवानिवृति के बाद मिलने वाली पैंशन से अपने बच्चों और पोते-पोतियों को भी पढ़ा सकता है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया वाइंडअप कर दें।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, अभी तो स्टार्ट ही हुआ हूं। मैं अच्छी चीजें बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश के आऊटसोर्स कर्मचारी भी परेशान है। जिला ऊना में एक महिला कर्मचारी आऊटसोर्स पर क्लर्क लगी हुई है। उसे लेबर इंस्पैक्टर ने कहा कि जो आपको खाते में सैलरी आती है उसमें से कुछ पैसे मुझे दे दीजिए। उसमें विजिलैंस ने केस दर्ज कर लिया है लेकिन उन कर्मियों के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी और कांग्रेस पाटी वर्ष 2022 में सत्ता में आएगी इसमें कोई दोराय नहीं है, तब हम आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नीति बनाएंगे। यह ठीक है कि हमारी पिछली सरकार ने इनके लिए कोई नीति नहीं बनाई और हमें उसका भुगतान करना पड़ा तथा आज हम विपक्ष में बैठे हैं लेकिन हम आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक ऐसी नीति बनाएंगे जिससे उनको लाभ मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि चतुर्थ श्रेणी में करूणामूलक आधार पर भर्तियां की जाएंगी लेकिन अभी तक उनकी भर्तियां नहीं हुई हैं। इसी प्रकार आशा वर्कर व आंगनबाड़ी कार्याकर्ताओं ने कोरोना काल में सबसे अच्छा काम किया। इस माननीय

सदन में मेरे साथी माननीय सदस्य श्री संजय अवस्थी ने ठीक कहा है कि कोरोना काल में यह देखना चाहिए था कि क्या सभी मोतें कोरोना के कारण हुई हैं? कुछ ऐसी मोतें भी हुई होंगी जिसे कोई अन्य बीमारी हुई हो। कोरोना काल में केवल यह हुआ कि चाहे वह हार्ट का पेशंट था, चाहे किडनी का पेशंट था या अन्य कोई बीमारी वाला था उसे कोरोना वार्ड में डाल दिया गया।

02-03-2022/1045/वाई.के.-ए.जी. /3

उसे वहां पर कोई डॉक्टर देखने तक नहीं गया। इसलिए मैं माननीय सदस्य श्री संजय अवस्थी जी की बात का समर्थन करता हूं कि कोरोना काल में हुई मोतों का death Audit करवाना चाहिए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया एक मिनट में अपनी बात को वाइंडअप करें।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, अभी 17 मिनट हुए हैं और उसमें से 2 मिनट माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने ले लिए। इसलिए मेरे तो केवल 15 मिनट ही हुए हैं।

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

02.03.2022/1050/AG/JS/1

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खुः------जारी-----

आप खुद भी जस्टिस करिए। आप हमारे भी,विपक्ष के भी अध्यक्ष महोदय हैं। आप थोड़ा जस्टिस करिए और 10 मिनट में मैं खत्म करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि कइयों की मौतें इसलिए हो गई कि उनको डॉक्टर्ज़ ने चैक ही नहीं किया। आज इस सरकार से किसान और बागवान परेशान हैं। किसान बन्दरों से परेशान हैं, आवारा गायों से परेशान हैं। आपने चार साल पहले कहा था कि जो नील गाय हैं, उनको रोकने के लिए नीति ला रहे हैं। अभी तक कोई नीति ही नहीं आई । यह ठीक है कि आपने एक जगह

अच्छा काम किया कि जो आवारा गाय थीं, उनके लिए आपने गौ सदन खोले हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।...(व्यवधान)... अध्यक्ष जी, जो सेब बैल्ट के बागवान हैं, जब वे अपना सेब बेचते हैं तो एच.पी.एम.सी. और हिम फैडरेशन के द्वारा बेचते हैं और उनको पैसा नहीं मिलता। उनको कहा जाता है कि यह केमिकल फर्टिलाइजर से तैयार हुआ है। वे कहते हैं कि यह केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है यह ऑर्गेनिक है, इसको खरीदिए। मैं बागवानी मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, उसमें क्या कोई स्टैम्प आदि होती है कि क्या ऑर्गेनिक है, कुछ नहीं है। सरकार तो सोई हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने पहले भाषण में कहा था,

अध्यक्षः माननीय सदस्य, वाइंड अप करिए।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि मण्डी में एक इन्टरनेशनल एअरपोर्ट बनें। टूरिज्म प्वाइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है। लेकिन एक इंच भी जगह आज तक उसकी एक्वायर नहीं की गई है। जब वर्ष 2017 का इलैक्शन था तो आप यहां पर नीतिन गडकरी जी को लाए। उनसे वर्ष 2016-17 में शिलान्यास करवाया कि शिमला से मटौर फोर लेन होगा, पठानकोट से जोगिन्द्रनगर फोर लेन होगा। आज तक एक इंच कंस्ट्रक्शन उसकी शुरू नहीं हुई है। अभी जून में फिर प्रधान मंत्री जी आ जाएंगे। हिमाचल के लोगों को सपने दिखाएंगे।

02.03.2022/1050/AG/JS/2

क्योंकि जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश की जनता को इंटरनेशनल एअर पोर्ट का सपना दिखाया, अब श्री नरेन्द्र मोदी जी भी दिखाएंगे। जो सपनों की दुनिया में रहने वाली पार्टियां होती हैं, ठीक है, कभी ये भी दो पर थे, आज हमारी 44 सीटे हैं। ...घंटी.... जो सपनों की दुनिया में रहती हैं, वह सपनों को दुनिया को बेचती है। अध्यक्ष महोदय, सपनों की दुनिया वालों को मैं यह कहना चाहूंगा कि सपने देखना आप लोग बन्द कीजिए। जो जुमले हैं, उनको बोलना बन्द कीजिए। अगर सही मायने में आप इस प्रदेश का

भला चाहते हैं तो शराब माफिया के खिलाफ कड़े कानून लाएं। माइनिंग वालों के खिलाफ कड़े कानून लाएं। लेकिन आप इन कड़े कानूनों को ला नहीं सकते हैं। क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति मर चुकी है। आप लोगों में इच्छा शक्ति ही नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आप बड़े शांत रहते हैं। आपको तनाव ही नहीं रहता। आपको पता नहीं कैसे हार्ट की प्राब्लम हो गई लेकिन भगवान ने अच्छा किया कि आप स्वस्थ हैं। जिस प्रकार का इंजैक्शन आपको लगाया तो आप अपने डॉक्टर का हाल तो देख ही रहे हैं। आपको एम्ज जाना पड़ा। माननीय मुख्य मंत्री जी एक मंत्री आपके ढाई साल बाद बनें और बड़े जोर-जोर से से चीखते हैं। बड़े हाइपर हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम के जो हमारे विधायक आते हैं उन पर बड़ी टिका-टिप्पणी करते हैं। जो मैटर सब-ज्युडिस है उस पर भी टिका-टिप्पणी करते हैं। लेकिन उनको यह पूछना चाहिए कि आपके विभाग ने फोरेस्ट डिपार्टमैंट में मटौर-शिमला की जो फाइल है, वह तीन महीने से आपके विभाग में साइन होने के लिए पड़ी है, वह अभी तक साइन क्यों नहीं की? आप क्या उसमें से कुछ चाहते हैं? अगर सत्ता में बैठे ऐसे मंत्री होंगे तो ठीक नहीं है। उसमें क्या कोई चाहत रखी है? इस तरह से कैसे उत्थान होगा? आप देखें कि बारूद से उन्ना सुलग गया। वहां पर बारूद की फेक्टरी लगी , एक्सप्लोसिव हुआ, इंसान पटाखों की तरह इन्सान उड़ते हुए चले गए। किसी की टांग कहीं पर गिरी और किसी की बाजू कहीं पर गिरी लेकिन हमारे उद्योग मंत्री जी जाक यह भी पता नहीं चला कि वह उद्योग कब लगा था? ये सरकार के हाल है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आपके मंत्री जब बोलते हैं और इंटरनेशनल व नेशनल की बात करने लग जाते हैं, कांग्रेस की विचारधारा का पाठ पढ़ाने लग जाते हैं और जवाहर लाल नेहरू जी पर टिप्पणी करने लग जाते हैं। ये वह कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया।

02.03.2022/1050/AG/JS/3

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप वाईंड अप करें। आपको बोलते हुए 22 मिनट हो गए हैं।

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खुः देश की जनता ने जब कांग्रेस के कार्यकत्ताओं से खून मांगा तब कांग्रेस के कार्यकत्ताओं ने खून दिया। इस देश के दो-दो प्रधान मंत्रियों ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

02.03.2022/1055/SS-AG/1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु क्रमागत :

अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दीजिए। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। जब कांग्रेस पर टिप्पणी करेंगे, कांग्रेस के नेताओं पर टिप्पणी करेंगे तो क्या हम चुप बैठे रहेंगे।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, 16 मिनट के आप कंक्लूड कर रहे हैं।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, सभागार में बैठे हमारे सत्तापक्ष के साथी जब बोलते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि जब यह देश बना था तो उस समय सूई तक नहीं बनती थी। ये कांग्रेस की नीतियां हैं, ये कांग्रेस के कार्यक्रम हैं जिसके कारण 130 करोड़ की आबादी आत्म-सम्मान से जी रही है। जिस देश के आम आदमी को भाषण देने और प्रधान मंत्री बनने का मौका मिला, वह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की लोकतंत्र के प्रति आस्था है। आज एक आम आदमी भी देश का प्रधान मंत्री बन सकता है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बलिदान की बात है, एक परिवार की बात करने वाले पहले यह सोचिए कि देश की एकता व अखंडता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने सीने में 36 गोलियां सहन की हैं। यही नहीं उनके बेटे ने भी 5 साल बाद इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। सरदार बयंत सिंह जी ने जब पंजाब सुलग रहा था तो अपने प्राणों की कुर्बानी दी। छतीसगढ़ में विद्याचरण शुक्ल जी, कांग्रेस विधायक दल के नेता और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उन सब इस देश की एकता और अखंडता के लिए नक्सलवादियों से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। अब ये हमको देशभक्ति की परिभाषा बताएंगे! एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और उसका गुणगान करते हैं, अरे हमने तो बंगलादेश जैसा नया देश बना दिया। उस पर फ़ख्र करना चाहिए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी बात आ गई। आप बैठिए, कंक्लूड हो गया।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : मुख्य मंत्री जी, अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि खारकीव में हिमाचल प्रदेश के तकरीबन 10 से 15 बच्चे फंसे हुए हैं।

अध्यक्ष : आपकी बात आ गई और यहां से उत्तर आएगा। आप बैठिए।

02.03.2022/1055/SS-AG/2

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अच्छी बात है अगर उनको वहां से ला रहे हैं। मुख्य मंत्री जी, हमें पता लगा है कि आपके सत्तापक्ष वाले ज्यादा हैं। तो जो 56 इंच का सीना रखते हैं, जो देश को सर्वोपरि मानते हैं वे कहां सोए रहे। जब युद्ध सातवें दिन पर पहुंच गया तब भी बच्चे वहां से नहीं आ रहे हैं। अम्बैसी बंद कर दी है। तब आप क्यों सोए रहे जब पूरे देशों की अम्बैसियों ने कहा कि हम अपने बच्चों व नागरिकों को वापिस बुला रहे हैं? उस वक्त प्रधान मंत्री जी कहां सोए हुए थे?

अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में मैं यह कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष : आप कंक्लूड कर दीजिए। आप एक मिनट की बात मत करिए।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, ये जो सत्तापक्ष है - मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, 6 महीने पहले ही इन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं। मैं यह कहूंगा कि यह सिर्फ 6 महीने की सरकार है। आप समाज का कुछ भला करके जाइए। कर्मचारियों का भला करके जाइए। लाखों बेरोज़गार युवा रोज़गार प्राप्त करने की कतार में खड़े हैं लेकिन कोई रोज़गार नीति नहीं आई है। इसका उदाहरण लोक सभा चुनाव में मिला कि कितने लोगों को सिराज में नौकरी मिली। तभी सिराज की लीड आई। सिराज और धर्मपुर की लीड आई। आप सब लोग जो यहां बैठे हैं, नौकरियां सारी सिराज और धर्मपुर के लिए हैं। आप लोगों के लिए नहीं हैं। आप में से कुछ लोग अगर चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं तो आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। आप सोच-विचार करके आइए।

इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है यह एक रूटीन का अभिभाषण है। इसमें कागज़ के कुछ पन्ने बढ़ गए हैं, अभिभाषण का कुछ भार बढ़ गया है लेकिन समाज का उत्थान नहीं हुआ। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना ज़रूरी है। जनता ने एक उदाहरण दे दिया है और दूसरे उदाहरण की तैयारी है। धन्यवाद, जयहिन्द, जय भारत।

02.03.2022/1055/SS-AG/3

अध्यक्ष : अब चर्चा का समापन हो चुका है। माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी, इसमें आपका नाम नहीं है और चार दिनों से चर्चा चल रही है।

श्री राकेश सिंघा (ठियोग) : अध्यक्ष महोदय, मैंने फर्स्ट डे ही अपना नाम दिया था और मैं लगातार आपके चेम्बर में भी आता रहा हूं। Please don't do such a thing. मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप ऐसा मत कीजिए। ...व्यवधान...

जारी श्रीमती के0एस0

02.03.2022/1100/केएस/एएस/1

अध्यक्षः ...(व्यवधान)...हमने तो आपको भी बोलने दिया है, जगत सिंह नेगी जी भी बोले हैं। चार दिन तक यह चर्चा चलती रही है। श्री राकेश सिंघा जी, आप बोलिए।

Shri Rakesh Singha (Theog): Speaker, Sir, pardon me for my critical postmortem of the Address made in this august House by the Hon'ble Governor of Himachal Pradesh, on the 23rd February, 2022. I outrightly reject the contents of the Address. The Address stands rejected because it has been drafted without the application of mind. It stands rejected because it is an illusionary document. It stands rejected because it is based upon half truth. It stands rejected because it is divorced from reality. It stands rejected because it is a bundle of contradiction. I qualify my presentation in this august House

with concrete evidence which is self-evident. The essence of the Address is incorporated in Para-5 of the document rest is descriptive note of the intention of the Government with passing references what you believe to have been achieved; excuse me, the ground realities are far different. Let me quote Para No.-5. The Para No.-5 of the Hon'ble Governor's Address says: 'In these four years, my Government has implemented many ambitious schemes and programmes to take the State to new heights, create a robust economy, create avenues for employment and self-reliance for the youth, for the socio-economic upliftment of the women and welfare of farmers and to bring the backward and weaker sections of the society into the mainstream of development'. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो रॉबस्ट इकोनॉमी की बात कही जा रही है, मैं आपके इस सरकार के फाइनेंस डिपार्टमैंट का दस्तावेज जो इसी हाउस में 6 मार्च, 2021 में आपने पेश किया, उसके कुछ पहलू आपके सामने रखता हूं। मैं अपनी तरफ से कोई बनावटी बात नहीं करुंगा, आपके दस्तावेज से, आपकी सरकार को मैं आज बिल्कुल negate करके छोड़ूंगा, यह क्या लिखता है,''The growth rate of the GSDP witnessed a slide of about 6 per cent 2020-2021. यह 2021 और 2022 की बात नहीं है, पहले की बात कर रहा है on account of nationwide lockdown. Due to Covid-19 pandemic. आगे क्या बोलता है, हमारे क्या हाल है: 'Receipt for sale of power has

not shown desired growth in view of the Covid-19 impact. रॉबस्ट इकोनॉमी, यह है वह छलांग मारती हुई अर्थव्यवस्था। आप खुद देख लो कि आपकी अर्थव्यवस्था कितना छलांग लगा रही है? आगे क्या बोलता है?आगे यह बोलता है: 'Covid-19 inflicted adverse shock to the economy in 2020-2021, due to which finances of the State Government were in stress now the impact of Covid-19 cannot be negated in a short term State tax pace is very slow and the Central Grant flows in the coming years will be important. यह है वह रॉबस्ट इकोनॉमी। After 2022-2023 Revenue Deficit Grant is also showing tapering trend which will further deteriorate the Revenue Receipts of the State यह है वह छलांग मारती हुई

अर्थव्यवस्था। हम काल्पनिक बात न करें। जो ग्राउंड स्तर पर सच्चाई है, उसका हमें ज़िक्र करना चाहिए और हकीकत के आधार पर हमें यह करना है। मैं क्यों कहता हूं, it is a bundle of contradiction अगर हमारी अर्थव्यवस्था वह है जो हमने पैरा 5 में दी है तो फिर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे विनती करना चाहता हूं। दो बातें नहीं हो सकती। that we blow hot and cold in the same breath. अगर हमारी इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था है तो मैं आपसे हाथजोड़ कर विनती करता हूं। फिर हमें क्या करना चाहिए,जो न्यू पैंशन स्कीम है,
श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी..

02.03.2022/1105/av/as/1

श्री राकेश सिंघा---------- जारी

तो मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि ओल्ड पैंशन स्कीम को तुरंत लागू किया जाए। उसके बाद आशा वर्कर्ज, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील वर्कर्ज, एन0एच0एम0 के कर्मचारी, सिलाई-कढ़ाई के कर्मचारी, जल वाहक, जल रक्षक और मल्टी टास्क वर्कर्ज को कितना वेतन देना चाहिए; उस बारे में मैं नहीं बोल रहा है। उस बारे में हिमाचल प्रदेश के माननीय हाई कोर्ट ने कब क्या कहा; माननीय मुख्य मंत्री, मैं आपकी उसमें मदद कर रहा हूं। दिनांक 8 जनवरी, 2020 को Court on its own motion versus State of HP & others इस केस में मैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को कोट कर रहा हूं। माननीय हाई कोर्ट ने इस जजमैंट के पैरा 16 में यह कहा है किः 'Thus we can say that with this meager amount, it is very difficult for a person to survive and to feed, to take care of his family and to educate his children. मैं दोबारा कोट कर रहा हूं। In this era of unemployment, these employees are forced to work on a meager take home salary of around Rs. 10,000/- only. If this salary is divided amongst all the family members, each member would get only around Rs. 100 per day with which it is very difficult to survive. Thus we are of the view that in this meager

amount, it is very difficult for a person to take care of a sick old parents, to feed his family or to send his children to school and take care of his wife and bear the day-to-day expenses. यह हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय का कहना है। आगे यह भी कहा गया है कि कितना होना चाहिए और उस बारे में मैं पैरा 19 को कोट कर रहा हूं : ' In view of the fact and circumstances of the case, we direct the respondent No.-10 वह कंपनी है to enhance the take home salary of each employee to the tune of Rs. 15000/- per month w.e.f. 20th January, 2020'. यही नहीं कहा बल्कि जो आगे कहा है; हम उसको भी समझें क्योंकि माननीय जल शक्ति मंत्री श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए गठित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी के चेयरमैन है। माननीय न्यायालय ने आउटसोर्स कर्मचारियों के पक्ष में यह फैसला

02.03.2022/1105/av/as/2

दिया है कि Respondent No. 10 is further directed to pay salary to its employees only by cheque by remitting the same to their bank accounts. In case, there are not bank accounts of the employees, the same be opened at the earliest and thereafter, their salaries be remitted to their bank accounts. माननीय कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? वह इसलिए क्योंकि आज ये कंपनियां अपनी बातें कह देती हैं कि इतना-इतना दे रहे हैं परंतु सबूत तो वही होगा जो बैंक के खाते में जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी यह रोबस्ट इकोनॉमी नहीं है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत संकट में जा रही है। इसमें इंप्लॉयमैंट के पक्ष में यह भी कहा गया है कि हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को बहुत बढ़िया रोजगार दिया जा रहा है। इसलिए मैं यहां सी0एम0आई0ई0 को कोट कर रहा हूं और उनका हिमाचल प्रदेश के बारे में यह कहना है कि Unemployment rate in May 2020 increase 26.0 per cent point increased to 28.2 in Himachal Pradesh उस समय राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी की प्रतिशतता 23 थी जबकि फरवरी, 2021 और जनवरी, 2022 के बारे में सी0एम0आई0ई0 का यह कहना है

कि हिमाचल प्रदेश में अनइंप्लाइमैंट रेट 13.86 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 6.57 प्रतिशत है। सिचुएशन की ग्रेविटी इस बात से पता चलती है कि प्रदेश में 1195 रिक्त पड़े पटवारियों के लिए लगभग 3 लाख बेरोजगारों ने अप्लाई किया जिसमें पी0एच0डी0 व दूसरे टैक्निकल युवा भी शामिल थें। आप इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या कितनी गंभीर हो गई है।

टी सी द्वारा जारी

02/03/2022/1110/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

श्री राकेश सिंघा... जारी

अध्यक्ष महोदय, आप मुझे दो मिनट दें, मैं अपनी बात को दो मिनट में समाप्त करने की कोशिश करता हूं। वर्ष 2022 में सरकार ने किसानों के बारे में कहा कि आपकी आमदनी दोगुनी की जाएगी। आज वह दोगुणी आमदनी कहां है? आज हिमाचल प्रदेश में हालात संकटग्रस्त है। ये जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था, क्या इसको लिखने के लिए ऑउटसोर्स किया गया था या फिर जो लिखने वाला था, वह इसको अफीम खाकर लिख रहा था। आप इसमें क्या लिख रहे हैं? इसके पैरा-11 में लिखा है कि in order apple to ensure remunerative price to the cultivators, 73,217 metric tonnes of 'C-grade' apple worth about Rs. 69.56 crores has been procured under 'Market Intervention Scheme'. प्रोक्योरमैंट प्राइस कुछ और है और स्पोर्ट प्राइस कुछ और है। यदि 9.50 रुपये में सेब खरीदोगे और सेब उत्पादकों को कहोगे कि आपको हम लाभ दे रहे हैं तो कोई आपकी बात नहीं मानेगा। इसलिए जब आगे कभी इस तरह का दस्तावेज लिखें तो सोच-समझकर लिखें, दिमाग की नसों को खोलकर लिखें। दिमाग की नसों को बंद कर लिखोगे तो उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। अंत में, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय समय आ गया है और आप मेरी बात का बुरा न माने, यह बहुत बड़ा इम्तहान है। दुनिया में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसको 'Battle of Waterloo' कहा जाता है। मेरी आप से विनती है, आप यकीन करें as an individual I have highest respect for

you, विचारधारा अलग-अलग हो सकती है। आप एक साधारण परिवार से उठकर इस कुर्सी पर आए हैं। आपकी मानसिकता व चेतना जो बड़े घरों में पैदा होते हैं, महलों में पैदा होते हैं और जो पूंजी की हिफाजत करते हैं, उनसे अलग होनी चाहिए। लेकिन चेतना अलग तब होगी अगर आप इसका जवाब दे पाओगे। जैसा अभी श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने भी कहा है कि जो ये पे-कमीशन के मसले को लेकर राइडर लगा दिया है, ये राइडर क्या है? ये राइडर आपने 2012 में इन्सर्ट किया। ये राइडर क्या बीमारी है और इसका क्या पेच है? यह ऐसा पेच है जो कहीं भी फिट हो जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम विधान सभा के 68 विधायक चुने गए और

02/03/2022/1110/टी0सी0वी0/डी0सी0/2

हम सबका वेतन एक समान था। आपमें से कुछ मंत्री बन गए और उनका वेतन बढ़ गया। आप मुख्य मंत्री बन गए और आपका वेतन और अधिक हो गया। राइडर का मतलब यह है कि जो मंत्री बने वे भी वही वेतन लेंगे जो एक विधायक का वेतन है। जो मंत्री से मुख्य मंत्री बनेगा वह दो साल तक मुख्य मंत्री का वेतन नहीं लेगा और वह वही वेतन लेता रहेगा जो मंत्री का वेतन है। ऐसी नीति यदि आप अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते हैं तो हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम दूसरों को कहे कि इसको आप पर लागू करेंगे। मैं महात्मा गांधी जी को सलाम करता हूं। वे एक बात कहते थे कि 'only preach that which you can practice'.

एन0एस0 द्वारा .... जारी

02-03-2022/1115/NS/DC/1

श्री राकेश सिंघा .....जारी

हम दुनिया को तो ज्ञान देते रहेंगे लेकिन जब अपनी वारी आएगी तब कहेंगे नहीं, यह तो कठिन है। दो किस्म की नीति नहीं होनी चाहिए बल्कि एक किस्म की नीति होनी चाहिए। इसलिए इस राइडर को उड़ा दो। यह राइडर सिर्फ़ नर्म उदारवाद का एक पेच है और मान लो कि नर्म उदारवाद की नीतियां ध्वस्त हो गई हैं, ये टिकने वाली नहीं हैं। आज जन एक

तरफ़ खड़ा हो गया है और दूसरी तरफ़ आपकी नर्म उदारवाद की नीतियां खड़ी हैं। इनके बीच तीखा संघर्ष शुरू हो गया है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आप इस सरकार को सदबुद्धि दो और मैं समझता हूं कि आप निश्चित रूप से देंगे। प्लीज़, मैं सीरियस हूं। मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूं। मैं कहना नहीं चाहता हूं, ऐसे डॉक्यूमैंट, मुझे माफ़ करें, just because the Hon'ble Governor has placed this Address in the House, otherwise it's place was in the dustbin. इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूं। नहीं तो मेरा भाषण आज वहां से होना था लेकिन आपने यह परिस्थिति रोक दी है तो मैं समझता हूं कि हर अध्यक्ष, विधान सभा को ऐसा काम करना चाहिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।

02-03-2022/1115/NS/DC/2

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव इस माननीय सदन में सदन के वरिष्ठ नेता डॉ0 राजीव बिन्दल जी ने रखा था और श्री बलबीर सिंह जी ने इसका समर्थन किया था। इस सदन में जो प्रश्न, शंकाएं और बातें यहां पर चर्चा के माध्यम से आई हैं, मैं उनका उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कुल 41 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और इनमें से 20 सदस्य सत्ता पक्षा, 19 सदस्य प्रतिपक्ष और एक सदस्य सी.पी.आई.एम. तथा एक सदस्य निर्दलीय हैं। कुल मिला करके यह चर्चा साढ़े पन्द्रह घंटें की इस माननीय सदन में हुई है। मैं इसलिए इस बात का ज़िक्र कर रहा हूं कि बहुत अच्छे पार्टिसिपेशन के साथ सभी सदस्यों को खुल करके बात कहने का अवसर अध्यक्ष महोदय ने दिया है और मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए और खुली होनी चाहिए तथा मुक्त होकर होनी चाहिए। आज इस माननीय सदन में कुछ व्यवस्थाओं को ले करके थोड़ा परिवर्तन किया गया है। सदन 10 बजे शुरू करने का निर्णय हुआ और प्रश्नकाल भी स्थगित किया गया क्योंकि मेरा अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि, मंडी का एक कार्यक्रम आधारित है

और वहां पर मेले का उद्घाटन होना है तथा उसे आगे-पीछे नहीं किया जा सकता है। इस कारण से सदन के समय में परिवर्तन किया गया।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

02.03.2022/1120/RKS/HK-1

मुख्य मंत्री... जारी

इसके लिए मैं विपक्ष के साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। सबकी सहमति थी कि सदन में चर्चा करने के बाद चर्चा का उत्तर दिया जाए। जो सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं उनका भी पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इसलिए किसी को कोई उलझन नहीं रहना चाहिए कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में क्या होता है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के कार्यकाल में चलाई जा रही योजनाओं व अन्य कार्यों का उल्लेख होता है। स्वाभाविक रूप से इस अभिभाषण में सरकार की कारगुजारियों का ज़िक्र होता है। अगर इन कारगुजारियों में कोई कमी रह जाए तो विपक्ष का दायित्व बनता है कि आप इसमें सुधार लाने के लिए अपने सुझाव दें। सत्तापक्ष वाले स्वाभाविक रूप से सरकार की नीतियों का स्वागत करेंगे। महामहिम राज्यपाल एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। जब महामहिम राज्यपाल यहां पर अभिभाषण पढ़ने आते हैं तो उनकी गरिमा के प्रति हमारा सदैव आदर का भाव रहना चाहिए। चाहे पिछली बार की घटना हो या अभी की, मैं इन बातों में जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि अबकी बार आपने थोड़ा सुधार किया है। कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं लेकिन उन गलतियों से हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। आप सीखने की दिशा में एक कदम आगे बढ़े हैं। अच्छा होता अगर आप महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण पूरा सुनकर जाते। मुझे बहुत विचित्र लगा जब आप बीच में ही महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को छोड़कर चले गए। आज पता नहीं आप कितनी देर बैठे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप वाकआउट नहीं करेंगे। ...व्यवधान... हम नहीं उकसाते। लेकिन आप

बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। जब कोई बच्चा अपनी मां के साथ बाज़ार जाता है तो वह बाज़ार में खिलौने की दुकान देखकर खिलौना लेने की जिद करता है। लेकिन वह बच्चा है और हम इस बात को समझ सकते हैं। जब मां उसे खिलौना नहीं देती तो वह रोना शुरू कर देता है। जब मां बच्चे को थोड़ा गुस्सा होती है तो वह सड़क पर लेट जाता है। आप भी इस तरह

02.03.2022/1120/RKS/HK-2

लेटने की स्थिति में आ गए हैं। खिलौना चाहिए, इसी वक्त चाहिए, आप रोना शुरू कर देते हैं और फिर सड़क पर लेट जाते हैं। मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चे के प्रति मां का भाव स्नेह का होता है और कई बार उसे खिलौना मिल जाता है। लेकिन हर बार यदि बच्चा खिलौने की जिद करे तो मां वहां से रास्ता बदलकर दूसरी जगह से जाना शुरू कर देती है। आपके साथ भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। मैं यह देख रहा था कि पूर्व की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की थीं। मैंने स्मरण करने की कोशिश की लेकिन मुझे योजनाएं याद नहीं आई।

श्री बी.एस.द्वारा.. जारी

02.03.2022/1125/बी.एस./एच0के0/-1

मुख्य मंत्री जारी...

आखें बंद करके भी मैंने थोड़ा और कोशिश की कि शायद याद आ जाए और मैं चाह रहा था कि हम उनका अध्ययन करेंगे ताकि उन अच्छी चीजों को हम ग्रहरण कर सकें, क्योंकि योजनाएं इसी मकसद के साथ शुरू की जाती हैं कि उससे समाज का भला हो सके और समाज का लाभ हो सके। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूर्व में पांच साल के कार्याकाल में एक भी योजना ऐसी नहीं बनी जिसे वर्तमान में स्मरण किया जा सकता है और न ही जिसका जिक्र किया जा सकता है। सत्ता पपक्ष की तो बात छोड़िए परंतु विपक्ष के लोग भी नहीं बता सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि आप यहां से बाहर चले गए कि

अभिभाषण छूठ का पुलिंदा है, मैं हिमाचल प्रदेश में इस दायित्व में पहली बार आया हूं लेकिन आने के पश्चात हमारी सरकार ने सत्ता में आने के तुरंत बाद नए इनिशिएटिव के साथ कार्य करना शुरू किया और समाज के अलग-अलग वर्गों के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर कार्य आरंभ किया। सत्ता किसी एक व्यक्ति और एक पार्टी की नहीं रहती। हमें यह मान करके चलना चाहिए और न हमारे में इस तरह की गलत फहमी है और आप भी गलत फहमी में मत रहिए, यह आना और जाना चला रहता है, कभी हम होंगे, कभी आप होंगे, कभी आप होंगे, कभी हम होंगे, यह चलता रहेगा। परंतु किस सरकार ने नए इनिशिएटिव लिए हैं, यह हमेशा याद रखा जाता है। आज में इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद क्या किया, वह इस दस्तावेज में दिया है। आदरणीय सिंघा जी कह रहे थे कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला। ये भी सच्चे हैं, अकेले हैं, इसलिए इन्हें अपनी बात कुछ जोर से कहनी पड़ती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि जिसे आप छूठ का पुलिंदा बोल रहे हैं, हमारी सरकार ने सत्ता में आने के पश्चात नए इनिशिएटिव के साथ कार्य करना शुरू किया है? हमारी कैबिनेट की पहली बैठक में मनुष्य के लिए तो हमने सोचा-ही-सोचा परंतु हमने आते ही उस गो-माता के लिए भी सोचा, गो-वंश के लिए भी सोचा जो बेजुबान है, जिसके लिए आवारा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। आवारा तो वे लोग हैं जिन्होंने उन्हें छोड़ा है। हमारी पहली कैबिनेट

के दो बड़े निर्णय थे, एक बुजुर्गों को पेंशन के कागज ले करके खड़ा न होना पड़े इसके लिए हमने निर्णय लिया और दूसरा निर्णय, जो बेजुबान हैं, कुछ नहीं कह सकते उनकी संख्या उस वक्त गाय अभयारण और गो-सदनों में छः हजार थी और आज उनकी संख्या 20 हजार पहुंच चुकी है। आप वे गो-सदनों और गाय अभयारणों में सुरक्षित हैं। काश, आपने इस तरह से पहले सोचा होता, तो कितना अच्छा होता, आज एक भी गाय चौक और चौराहे पर नहीं होती। हम कहा कि बदले की भावना से कार्य नहीं करेंगे। चार वर्ष का कार्य

काल पूर्ण हो चुका है, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एक उदाहरण दीजिए, जहां पर हमने किसी नेता और पार्टी के विरुद्ध बदले की भावना से कार्य किया हो।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

02-03-2022/1130/वाई.के.-ए.जी. /1

मुख्य मंत्री ..... जारी

हमने बदले की भावना से किसी नेता के ऊपर या किसी पार्टी के ऊपर कोई कार्यवाही की हो। जो गलत करते हैं या कानून का उलंघन करते हैं उनके ख़िलाफ अवश्य कार्रवाई की है। इन सबके बावजूद हमने वह दौर समाप्त कर दिया और उसे दफन कर दिया जो कई सालों से इस प्रदेश में चला हुआ था। हमें भी इस माननीय सदन में 25 साल होने जा रहे हैं और हमें यही सुनाई देता था कि इसके ख़िलाफ ये करो, उसके ख़िलाफ ये करो, सत्ता में चाहे कोई भी आए यही काम चलता था। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं कि यह सब चीजें पूर्व में होती रही हैं लेकिन हमारी सरकार में इस अंतर को आप जरूर समझेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने अनेक इनिशिएटिव लिए हैं और विपक्ष के लोग उसे जितना मर्जी भूलना या मिटाना चाहें लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिल-दिमाग में वे अपनी छाप छोड़ चुके हैं। लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हमने जनमंच की शुरूआत की है। विपक्ष के लोग उसे जिस मर्ची रूप में बोलें लेकिन लोगों को उसके बारे में पूरा मालूम है कि जनमंच में क्या होता है। जनमंच में लोगों की समस्याओं का समाधान उनके घर-आंगण में होता है। हमने प्रदेश में अभी तक कुल 242 जनमंच आयोजित किए हैं, कोविड के कारण इसमें थोड़ी बाधा अवश्य आई लेकिन हमने जनमंच के माध्यम से 48,478 समस्याओं का मौके पर समाधान किया है। प्रदेश में इस प्रकार का एक नया इनिशिएटिव हमारी सरकार द्वारा लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, एक अमीर आदमी होगा तो उसके घर में गैस का चुल्हा होगा लेकिन एक गरीब आदमी इस बारे में सोच भी नहीं सकता था। उस गरीब व्यक्ति के सपने को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे देश में उज्जवला योजना की शुरूआत की

02-03-2022/1130/वाई.के.-ए.जी. /2

हिमाचल प्रदेश में जो परिवार उज्जवला योजना में शामिल नहीं हो पाए ऐसे परिवारों को हमने हिमाचल गृहणी सुविधा योजना के माध्यम से लगभग 3.25 मुफ्त गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाएं हैं और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि यह झूठ का पुलिंदा है तथा प्रदेश में कुछ नहीं हुआ है। पुरे देश में हिमाचल ऐसा पहला राज्य है जहां पर हर घर में गैस का चुल्हा है।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जो भी सरकार सत्ता में होती है उनके लिए अलग-अलग परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। मेरा यह मानना है कि कौन कितने समय तक सत्ता में रहता है वह ज्यादा महत्व का विषय नहीं है बल्की किसने समाज के लिए बेहतर काम किया है वह महत्व का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, इस सरकार में जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे तब हमने सरकार में आते ही अधिकारियों से बात करी कि गरीब आदमी के उपचार के लिए हमारे पास ऐसी कौन सी योजना है जिससे उसका उपचार मुफ्त में किया जा सके। गरीब आदमी जब पैसे की कमी के कारण अपना उपचार नहीं करवा पाता है तब चींख-पुकार के वह इस दुनिया से चला जाता है। हमने अधिकारियों से पूछा कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए तब अधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में ऐसी कोई योजना नहीं है। हमने उनसे कहा कि क्या ऐसी कोई योजना बनाई जा सकती है तो उन्होंने कहा कि कठिन है क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगेगा। हमने उनसे कहा कि आदमी की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है और हमें उनके लिए आगे बढ़ कर कुछ करना चाहिए। पुरे देश में हमारी सरकार पहली ऐसी

सरकार है जिसने मुख्य मंत्री हिमकेयर योजना की शुरूआत की और इस योजना के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश के गरीब आदमी का उपचार करने में सफल हुए। अध्यक्ष महोदय, इस योजना के माध्यम से अभी तक लगभग 2,27,000 गरीब लोगों का मुफ्त में उपचार किया गया है जिसमें लगभग 201 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

02-03-2022/1130/वाई.के.-ए.जी. /3

इस सबके बावजूद भी विपक्ष के लोग बोलते हैं कि यह झूठ का पुलिंदा है।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में ऐसे बहुत से बेबस लोग हैं जिन्हें चलने-उठने-बैठने में भी दिक्कत होती है और सरकार के स्तर पर उनकी मदद करने की आवश्यकता है। इसलिए हमने मुख्य मंत्री सहारा योजना की शुरूआत की और पूरे देश में इस प्रकार की यह पहली योजना है। इस योजना के माध्यम से हमने प्रदेश के 18,218 गरीब लोगों का मदद करने का रास्ता ढूंढ़ा है तथा यह आंकड़ा अभी और भी बढ़ेगा। इस योजना के माध्यम से हमने इन गरीब लोगों के खाते में 3,000 रुपये प्रति माह डाला है। यह एक पुण्य का कार्य है और हमने इसी भावना के साथ यह कार्य किया है।

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

02.03.2022/1135/YK/JS/1

मुख्य मंत्रीः-----जारी------

आप अन्तर देखिए, हमारी सरकार और पूर्व की सरकार में बेसिक अन्तर यह है कि हम उस गरीब आदमी व बेबस आदमी के साथ खड़े हुए हैं, उसकी मदद के लिए खड़े हैं। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए यह भी कहते हैं कि सभी नौजवानों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार देना किसी भी सरकार के लिए सम्भव नहीं है। चाहे सत्ता में आप हों, हम हों या कोई और हो। आप पूरे देश में स्थिति देख रहे हैं कि बेरोजगार हर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमारा नौज़वान अपने पांव पर खड़ा हो, वह अपनी आजीविका के

लिए कुछ कर सकता है, उसके लिए मदद का रास्ता ढूंढना चाहिए। हमने मदद का रास्ता ढूंढा। "मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना"के नाम से हमने एक नई योजना की शुरूआत की और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक इस योजना के अन्तर्गत लगभग 2,231 लोगों ने लाभ लिया है और उन्होंने सैंकड़ों लोगों को रोजगार दिया। जिन्होंने अपना कारोबार शुरू किया उन्होंने अपने पास से बेरोजगारों को रोजगार दिया। इसमें हमने 100 करोड़ रुपये के करीब खर्च भी किया। उसके बावजूद भी हमारे मित्र कहते हैं कि यह झूठ का पुलिन्दा है। इसमें कुछ नहीं है। हमने कहा कि जनमंच के माध्यम से गांवों में जाना पड़ता है और उसके बावजूद भी घर बैठे लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, उसमें हमने 1100 पर कम्पलेंट डायल करने का प्रावधान किया। यह बहुत आसान काम था और इसको किया जा सकता था। आपकी सरकार ने इस पर भी सोचा नहीं। हमने घर बैठे ही लोगों की समस्याओं का रास्ता निकाला और 1100 के माध्यम से मुख्य मंत्री हैल्पलाइन की शुरूआत कर लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने अलग-अलग इनिशिएटिव्ज़ लिए हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं सारी योजनाओं का यहां पर जिक्र करूंगा तो उसमें बहुत समय लग जाएगा लेकिन हमारा इनिशिएटिव प्राकृतिक खेती का है जिसकी पूरे देश भर में सराहना हो रही है। हिमाचल पहला प्रदेश है जहां उस दिशा में हम प्रदेश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर

02.03.2022/1135/YK/JS/2

ज़हर मुक्त फल या कृषि का जो उत्पाद है, उसको हम हासिल कर सकें उस दिशा में हमने प्रयत्न किया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया। बी0पी0एल0 परिवार की किसी भी जाति की जो गरीब बेटी है, उसकी शादी के लिए हमने "मुख्य मंत्री शगुन योजना" की शुरूआत की। उसके माध्यम से 31000 रुपये की उसमें मदद कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया। इसके अतिरिक्त जहां पर बात आई थी प्राइवेट सेक्टर में इन्वैस्टमैंट की तो उनका योगदान काफी रहता है और मैं भी इस बात से सहमत हूं। मुझे मालूम था कि आप लोगों ने बहुत कुछ बोलना है और बहुत शोर मचाना है। उसके बावजूद भी हमने तय किया कि जब पूरे देश में सभी प्रांत कर रहे हैं तो यहां पर हमें क्यों रुकना

चाहिए, हमको भी करना चाहिए। मैं एक बात यहां पर कह रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वैस्टमैंट हिमाचल के विकास में योगदान दें, उस दृष्टि से हमने शुरूआत की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उसमें हम काफी हद तक सफल हुए। धर्मशाला में आदरणीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी आए। उन्होंने शुरूआत की, हिमाचल वासियों को शुभकामनाएं दीं। जो इन्वैस्टर्ज़ वहां पर आए थे उनको भी कहा था कि हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ कर काम करें, आप लोग अपना कारोबार भी चलाएं और उसके साथ-साथ हिमाचल विकास में भी अपना योगदान दीजिए। उस कार्यक्रम के पश्चात एक दिन पहले हमने हिमाचल प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग का जहां बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह हमारे विपक्ष के मित्रों ने खड़ा किया था कि यह हो नहीं सकता है, हम नहीं कर पाए और कोई और भी नहीं कर पाया तो जय राम कैसे कर पाएगा? साढ़े 13 हजार करोड़ रुपये की ग्राउंड ब्रेकिंग हमने एक महीने के अन्दर कर दी। आदरणीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह जी आए, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी यहां पर आए। उसके माध्यम से हमने प्रोजैक्ट्स स्थापित किए हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश में कोविड का दौर आया और इस बात को हमें मानना भी पड़ेगा। लेकिन यह सच्चाई है कि जो हमने साढ़े 13 करोड़ रुपये की फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग की थी, उसमें से 95 प्रतिशत से ज्यादा काम जमीन पर खड़ा हुआ है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

02.03.2022/1140/SS-AG/1

मुख्य मंत्री क्रमागत :

और अभी आदरणीय प्रधान मंत्री जी हमारा चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर हिमाचल प्रदेश आए तो हमने 28 हजार करोड़ रुपये की और ग्राउंड ब्रेकिंग की है। यह उस दिशा में कदम है जो आज से चार साल पहले इनके शासनकाल में की जा सकती थी, do able थीं लेकिन इनके पास यह सोचने का विषय नहीं था; काम करने का विषय नहीं था। आपके काम करने का तरीका जोरदार होता है। मज़ा करो, मस्ती में रहो, खूब ऐश करो और उसके बाद जब विदाई का दौर आता था तो कॉलेज, स्कूल व हॉस्पिटल खोलो। लोगों को बोलो कि आपको हॉस्पिटल दे दिया। इस कारण से आप वोट मांगने के लिए जाते थे।

लेकिन लोगों ने उसको नकारा है। हमने पहले दिन से काम शुरू किया। आप तो जब विदाई की शहनाई बजती थी तब काम शुरू करते थे। हम आज से ही काम नहीं कर रहे बल्कि मैं पहले दिन से ज़िक्र कर रहा हूं।

हमारे विपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी और बहुत सारे साथी कहते हैं कि प्रदेश को कर्ज में डूबो दिया। कर्ज में डाल दिया जैसे कि इन्होंने बिना कर्ज के ही सरकारें चलाई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर फैक्ट्स रखना चाहता हूं। मुझे यह बताना पड़ेगा क्योंकि आपका झूठा प्रचार चल रहा है। बाद में आप उसका फोलो अप करते हैं कि इस प्रकार की खबर लगनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 2012-13 से 2017-18 तक हिमाचल प्रदेश पर लगभग 48 हजार करोड़ रुपये का ऋण था। आपने अपने पांच साल के कार्यकाल में 28707 करोड़ रुपये का ऋण लिया। आपके पांच साल के ऋण की ग्रोथ देखिए, वह 67 परसैंट है। वर्तमान में जो हमारी सरकार है, 48000 करोड़ रुपये के ऋण के बाद आज हमारा ऋण 63200 करोड़ रुपये पहुंचा है। ...व्यवधान... अगर गलत फिगर होगी तो हम बात करेंगे। ...व्यवधान...जब बजट आएगा तो उस पर बात करेंगे। मैं भी इसी बात पर बोल रहा हूं। दो दिन के बाद बजट आएगा तो उसमें भी यही आएगा। अध्यक्ष महोदय, आप अंदाजा लगाइए कि हमारे ऋण की ग्रोथ 32 परसैंट है और इनकी 67 परसैंट है, कितना अंतर है। इनको शर्म

02.03.2022/1140/SS-AG/2

नहीं आ रही। हम रोज़ाना आपकी राम कहानी सुनते हैं कि यह हो गया, कर्ज में डूबो दिया, ऐसा कर दिया या वैसा कर दिया लेकिन आज तो हमारी थोड़ी-सी बात सुन लो।

अध्यक्ष महोदय, मैं आगे कहना चाहता हूं कि अब यहां पर बातें आती हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि जब हमारा डेढ़-दो साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो कोविड का भयंकर दौर आया जिसने पूरी दुनिया को तहस-नहस किया। दुनिया की इकोनोमी को

प्रभावित किया। आपके दौर में कोविड ही नहीं था। फिर भी आपके ऋण की ग्रोथ 67 परसैंट है। ऐसी परिस्थिति में आप इन सारी बातों का जवाब कैसे देंगे, इसको सोच लीजिए।

अध्यक्ष महोदय, कोविड को लेकर यहां पर बहुत बातचीत हुई है। मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि उस पर बहुत चर्चा हो गई है। लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार आने से पहले अगर ऑक्सीजन प्लांट की संख्या गिनते थे तो सिर्फ दो ऑक्सीजन प्लांट थे और वे भी बड़ी छोटी कैपेसिटी के थे

जारी श्रीमती के0एस0

02.03.2022/1145/केएस/एजी/1

मुख्य मंत्री जारी---

आई.जी.एम.सी., शिमला और टांडा मैडिकल कॉलेज में दो ऑक्सीजन प्लांट थे वे भी बहुत कम केपेसिटी के थे और आज हमारे प्रदेश में 48 पी.एस.ए. प्लांट हैं,। इसका कम्पेरिज़न है क्या? फिर भी ये कहते हैं कि कुछ नहीं है। ...(व्यवधान)...वेंटिलेटर्ज़ की ज़रूरत तो थी ...(व्यवधान)...

अध्यक्षः माननीय सदस्य सुन लीजिए। बैठे-बैठे बात न करें।

मुख्य मंत्रीः हमने देखा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी ही सरकार के समय मेरे एक रिश्तेदार का एक्सिडेंट हो गया था। उसको एडमिट करने के लिए जैसे-तैसे आई.जी.एम.सी. पहुंचाया, डॉक्टर्ज़ ने कहा कि इसको तुरंत वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा नहीं तो यह बच नहीं पाएगा। उसके सिर पर चोट लगी थी। उस समय वहां सारे के सारे वेंटिलेटर्ज़ लगे हुए थे, उसको वहां पर वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं हो पाया। ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, ये लोग इतने लम्बे समय तक सत्ता में रहे। यह सच्चाई है कि उस समय 52 में से 30 वेंटिलेटर्ज़ ही चलते थे बाकी डब्बे थे, चलते ही नहीं थे। आज हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर्ज़ की संख्या 1014 है। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी का खासतौर से धन्यवाद

करना चाहूंगा, जब उस दौरान सभी मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिज़ चली तो हमने कहा कि बाकी सारी चीजें हो जाएंगी लेकिन हमारे पास सबसे ज्यादा कमी वेंटिलेटर्ज़ की है और 500 वेंटिलेटर्ज़ प्रधान मंत्री जी ने थोड़े ही दिनो बाद हिमाचल प्रदेश में भेजे, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जब कोविड के सैकिण्ड फेज़ का दौर आया, जब पूरे देश और दुनिया में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी क्योंकि वह वायरस उस तरह का था, उस दौरान हम ऑक्सीजन प्रक्योर करने की स्थिति में तो थे लेकिन उसके बावजूद हमारे पास सिलेंडर नहीं थे। हमने गुज़रात, मुम्बई,कर्नाटक और दिल्ली, जहां से भी मिल

02.03.2022/1145/केएस/एजी/2

सकते थे, हमने लाए। हमारे पास सिलेंडर की बहुत मुश्किल थी। गैस को ट्रांस्पोर्ट करके हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं था। लगभग ढाई-तीन हजार के बीच में ऑक्सीजन सिलेंडर थे। उनमें से भी बहुत सारे फंक्शनल नहीं थे, खराब थे और आज 17000 ऑक्सीजन के सिलेंडर हिमाचल सरकार के पास हैं। ...(व्यवधान)... आप वेंटिलेटर्ज़ की बात कर रहे हैं। 982 वेंटिलेटर्ज़ आज की तारीख में फंक्शनल हैं। जिनको उपयोग में लाया जा रहा है। ...(व्यवधान)... अगर आपको वेंटिलेटर पर जाने की ज़रूरत होगी तो हम आपको बता देंगे कि कहां-कहां पर हैं।

अध्यक्ष महोदय,यहां शराब की बात आती है, मैं उस पर ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं क्योंकि उस पर काफी बात हो गई है। हमने उस पर ऐसी कार्रवाई की है जिसके आधार पर आने वाले समय में कोई भी आसानी से इस बारे में सोच भी नहीं सकता, यह स्थिति होगी। ...(व्यवधान)... हम मध्य प्रदेश से आदमी उठाकर लाए हैं, जो-जो भागे थे। जो गुनाहगार होता है, इस तरह का काम करता है। मैं मोटे तौर पर ऐसा मानता हूं कि उसके लिए बाकी पार्टियां बाद की बातें होती हैं, अपना धंधा पहले होता है और अपने धंधे के मुताबिक वह सोचता है लेकिन धंधे के माध्यम से वह आगे रास्ता ढूंढता है कि मेरा धंधा चल पड़ेगा तो मैं

फिर कोई सुरक्षित जगह तलाश करुंगा और इसके लिए ज़िक्र वे समाज सेवा का करते हैं। ऐसी स्थिति में, यह घटना दुखद है, मैं इस बात से सहमत हूं और उसमें जो मृत्यु हुई है वह दुखद है, इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

02.03.2022/1150/av/as/1

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली) : आपने अपनी बजट स्पीच 2018 के पैरा न0 5 में कहा है कि वर्ष 2008 से 2012 तक 7,621 करोड़ रुपये अतिरिक्त लोन लिया गया। जबकि वर्ष 2013 से 2017 तक 18,787 करोड़ रुपये अतिरिक्त लोन लिया गया है जो कि पिछले 5 वर्षों में लिए गए ऋण से 246 प्रतिशत ज्यादा है। आज आप 63 हजार करोड़ रुपये बोल रहे हैं जबकि दो दिन बाद जब बजट आएगा तो यह कुल मिलाकर 74,000-75,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप ऐसे बीच में खड़े होकर नहीं बोल सकते, आप बैठिए। मुख्य मंत्री जी, आप बोलिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पता नहीं, इनको ऐसी शंकाएं क्यों रहती है। ...व्यवधान... आप एपरिहैंशन पर मत जाइए, बजट आने दीजिए। ...व्यवधान... बजट की बात बजट के समय में करेंगे। लेकिन मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि जिस शराब वाली घटना का जिक्र आप लोग यहां पर कर रहे हैं ऐसी घटना पहले भी हुई है। यह घटना सच में दुःखदायी है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, मगर यह हुई है तो हमने इसमें बहुत सख्त कार्रवाई भी की है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि वर्ष 1997 में इस प्रकार की घटना ऊना के पालका और भदौरी में हुई थी जिसमें 9 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसमें एफ0आई0आर0 दर्ज हुई थी मगर कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन हमने कार्रवाई की है और उसके दोषी आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 4 एक्साईज के इंस्पैक्टर भी सस्पेंड किए गए हैं और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ...व्यवधान...

आप प्लीज, सुन लीजिए। ...व्यवधान... इसमें पुलिस ने भी कार्रवाई की है। इसमें यदि आप चाहें तो हम पूरी डिटेल में जवाब देंगे। ...व्यवधान... अगर आप इसमें शंका जाहिर

02.03.2022/1150/av/as/2

करेंगे तो आपको हमारी बात बैठकर सुननी पड़ेगी। ...व्यवधान... इस सारे धंधे का जो नेतृत्व कर रहे थे वह श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु के जिले से ही थे और आपके दल से वे टिकट की दावेदारी करते हैं। इससे आगे यदि ऊना विस्फोट की बात की जाए तो वह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है जिसमें 11 लोगों की जान गई हैं। लेकिन मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि ऊना विस्फोट का मुख्य अभियुक्त श्री रोहित पुरी जोकि भागा हुआ था; आज उसको हमारी एस0आई0टी0 ने मुम्बई में गिरफ्तार कर लिया है। हम यह कहना चाहते हैं कि कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनेगी उसको हम निश्चित रूप से करेंगे। मैं अपने विपक्ष के मित्रों को यह भी बताना चाहता हूं कि यदि एक्साईज की बात की जाए तो वर्ष 2013 से 2017 तक 5 वर्ष के कार्यकाल में एक्साईज के माध्यम से 27,623 करोड़ रुपये इकट्ठा हुआ जबकि हमने हमारे 4 वर्ष के कार्यकाल में फरवरी माह तक 27,925 करोड़ रुपये इकट्ठे किए हैं। ...व्यवधान... मुझे पता था कि आप लोग हट-फिरकर ठेके पर आ जाएंगे। ...व्यवधान...

श्री मुकेश अग्निहोत्री : मुख्य मंत्री जी, आपने अभी जो हमीरपुर के व्यक्ति को पकड़ने की बात कही है तो उसके पास 56-57 लाख रुपये के ठेके थे।

टी सी द्वारा जारी

02/03/2022/1155/टी0सी0वी0/ए0एस0/1

श्री अग्निहोत्री ... जारी

...व्यवधान... और आपको दो करोड़ रुपये आ गया। आप देखो कितना फ़र्क है? ...व्यवधान...

मुख्य मंत्री : आपने सुझाव दिया, ठीक बात है लेकिन यह कहने में क्यों लगे हैं कि ये करो या वो करो? ... व्यवधान... इस बार हम एक्साइज में मु0 8200 करोड़ रुपये एकत्रित कर रहे हैं जोकि लगभग 35 प्रतिशत अधिक है। यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हुए है जिसका सभी माननीय सदस्य भी जिक्र कर रहे हैं। यह हमारे लिए एक चिंता का विषय है। मैंने परसों एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और जो हमारे पास डॉटा था, उन सबको कनैक्ट करने की कोशिश की। जो बच्चे यूक्रेन में हैं उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। कुछ अभिभावक भी उसमें जुड़े थे, हमने उनकी बात भी सुनी। मैं कुछ तथ्य माननीय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यूक्रेन की राजधानी कीव से हिमाचल प्रदेश के सभी बच्चों को निकाल दिया गया है। यह हमारे लिए संतोष की बात है। अभी तक हम कुल 108 छात्रों को वहां से वापिस लाने में सफल हुए हैं। बाकी छात्रों को वापिस लाने में थोड़ी कठिनाई आ रही है। विशेषतौर से खारकीव में स्थिति काफी गंभीर है और वहां पर कर्नाटक के एक छात्र की मृत्यु भी हुई है। वहां मूवमेंट को लेकर बहुत कठिनाई है और वहां अभी और भी छात्र फंसे हुए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्ता है कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने वहां से बच्चों को निकालने के लिए लगातार बहुत गंभीर प्रयत्न किए हैं। उन्होंने दोनों सरकारों के साथ बातचीत भी की है और कहा है कि हमें वहां से भारत का एक-एक बच्चा सुरक्षित वापिस चाहिए। इसमें 4 केन्द्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है जो इस कार्य को देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रयास के सार्थक परिणाम सामने आएंगे। जो वीडियो वहां से आए हैं वे निश्चित रूप से विचलित करने वाले हैं। मेरी बहुत-सारे अभिभावकों और जो बच्चे वहां फंसे हुए हैं उनसे बातचीत हुई हैं। उन बच्चों ने भी कुछ रास्ते बताए हैं कि किस प्रकार से वहां से आसानी से निकला

02/03/2022/1155/टी0सी0वी0/ए0एस0/2

जा सकता है? उन्होंने कहा है कि पोलैंड जाने का रास्ता ज्यादा दूर है और हंगरी का रास्ता नजदीक पड़ेगा। इस तरह से वे अपने कुलीग्ज को भी गाइड कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक कृषि के क्षेत्र की बात है, हम इस बात से सहमत है कि हम इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य नहीं कर पाए लेकिन कोविड के समय में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर ने हमारी इकोनोकी को बहुत बड़ा सहयोग दिया है। प्राकृतिक खेती को लेकर हम आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास रहे हैं, आने वाले दिनों में हम उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे और पूरे देशभर में हिमाचल प्रदेश की की एक अलग पहचान होगी। खनन एक ऐसा विषय है जो पूर्व की सरकार के समय में भी काफी चर्चा में रहता था और वर्तमान सरकार में भी चर्चा का विषय है। सचमुच में यह एक पीड़ा का विषय है। यह नहीं होना चाहिए था लेकिन इसके बावजूद भी हो रहा है। विपक्ष के नेता और श्री सुखिविन्द्र सुक्खु जी ने के अलावा और भी बहुत सारे साथियों ने इस बात का जिक्र किया है।

एन0एस0 द्वारा .... जारी

02-03-2022/1200/NS/DC/1

मुख्य मंत्री .....जारी

मैं इस पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इसमें हमने कोशिश की है कि इसका कोई रास्ता निकाला जाए। हमारे पास इसके लिए एक सुझाव आया कि वहां पर सरकार को माइनिंग पोस्ट लगानी चाहिए। यह व्यावहारिक कैसे होगा और कितना होगा, हमने इन सब विषयों पर बहुत सोचा। इसमें आगे बढ़ कर काम करना चाहिए और उस दृष्टि से काम करने की कोशिश की। हमने वहां पर पांच माइनिंग पोस्ट एस्टेबलिश कीं लेकिन यह सच्चाई है कि आशा के अनुरूप इनका परिणाम नहीं आया। ...व्यवधान... हम इस बारे में भी विचार कर रहे हैं कि इसका क्या तरीका निकाला जा सकता है? वहां पर रास्ते अलग-अलग हैं। यह धंधा बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चल रहा है। ...व्यवधान...

श्री मुकेश अग्निहोत्री : ...व्यवधान... मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने हिमाचल प्रदेश पुलिस या प्रशासन को यह आदेश दिए हैं कि अवैध माइनिंग के खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी? ...व्यवधान... ऊना में डी.जी.पी. साहब का बयान था कि यह पुलिस के अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है तो इसमें कौन कार्रवाई करेगा? ...व्यवधान... वहां पर अगर

माइनिंग हो रही है तो क्या आप पुलिस विभाग को डायरैक्ट करेंगे कि वे अवैध खनन को रोकें? कोई एम-फार्म नहीं है तथा उसके बावजूद भी माइनिंग हो रही है। ...व्यवधान...

मुख्य मंत्री : हमने आदेश दिए हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ठीक है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि अवैध खनन के लिए सजा का प्रावधान एक वर्ष से बढ़ा करके दो वर्ष कर दिया गया है और 25,000 रुपये जुर्माना राशि को बढ़ा करके 5 लाख रुपये कर दिया है। ...व्यवधान... पकड़ रहे हैं। आप इस बात को सुन लीजिए। वहां पर अवैध क्रशर हैं और उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। ऊना जिला में पांच माइनिंग चैक पोस्ट स्थापित करने के बाद जिसका मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि आशा के अनुरूप जितना परिणाम आना चाहिए था वह नहीं आया है। हमने इस दिशा में एक प्रयत्न किया है। ...व्यवधान... मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस ने कार्रवाई की है। हमने इसमें यह तय किया है कि जो ऐसे माफ़िया पकड़े जाएंगे उनकी संपत्ति को अटैच करेंगे और ई0डी0 के माध्यम से जांच करेंगे। इस दिशा में काम चल रहा है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपको इसके परिणाम देखने को

02-03-2022/1200/NS/DC/2

मिलेंगे। इसी प्रकार से हमने आबकारी एवं कराधान मामले में भी तय किया है कि बड़े लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए जिस दिशा में जाना पड़ेगा हम जाएंगे और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। ...व्यवधान... इसमें काम करने की हमारी मंशा है। ...व्यवधान...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिए। मुख्य मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। ...व्यवधान...

मुख्य मंत्री : श्री अग्निहोत्री जी, जाने की जल्दी मुझे है लेकिन आप मेरे से भी जल्दी में हैं। ...व्यवधान... मैं कहीं पर भी झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं हरेक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। बजट तो अभी पेश होना है। ...व्यवधान... मुझे मालूम था कि यही होना है। ...व्यवधान... आप सुन लीजिए। ...व्यवधान...

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

(कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य और सी.पी.आई. (एम) के श्री राकेश सिंघा अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे।)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठिए।

(कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य और सी.पी.आई. (एम) के श्री राकेश सिंघा नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए।)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जाना तो मुझे था लेकिन मुझसे ज्यादा जल्दी इनको लगी हुई है। हमने इनकी तुलना में 110 एफ.आई.आर्ज. ज्यादा दर्ज़ की हैं। खनन के मामलों में 6,036 चालान किए गए हैं। हमने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की है लेकिन इनके कार्यकाल में कार्रवाई करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। क्योंकि खनन और शराब के धंधे से जुड़े हुए लोगों के साथ इनके बड़े-बड़े लोग भी शामिल थे। इन लोगों को कौन संरक्षण दे रहा था अगर इन बातों का पर्दा खुल गया तो उसमें सब मालूम पड़ जाएगा। स्वाभाविक रूप से इनके समय में बड़े-बड़े लोगों को संरक्षण दिया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 18 फरवरी, 2022 तक 9,74,379 किसानों को लाभ मिला है जिसमें प्रदेश के लोगों 1733 करोड़ रुपये की मदद प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत 42.89 करोड़ रुपये खर्च किए गए जिसमें 4,057 किसान लाभान्वित हुए हैं। हमने हर क्षेत्र में बेहतर काम करने का प्रयास किया है। हमने किसानों की फसल को ओलावृष्टि और मौसम के प्रभाव से बचाने के लिए प्रयत्न किए हैं। 'जल से कृषि को बल' एक नई योजना किसानों के लिए समर्पित की गई है। एंटी हेलनेट स्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए नया इनिशिएटिव लिया है। आज से पहले चावल और गेहूं खरीदने के लिए हमारे पास मंडियों की व्यवस्था नहीं थी। पहले प्रदेश के लोगों को अपना अनाज मंडियों तक पहुंचाने में बहुत मुश्किल आती थी। लेकिन अब हमने सात मंडियां

हिमाचल प्रदेश में स्थापित की हैं। यह सब हिमाचल प्रदेश में पहली बार हुआ है। नई राहें नई मंजिलें योजना के अंतर्गत नये टूरिस्ट

02.03.2022/1205/RKS/DC-2

डैस्टिनेशन विकसित किए गए हैं और वहां काफी हद तक टूरिस्ट भी पहुंच रहे हैं। यह ठीक है कि कोविड-19 के कारण पर्यटन क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ। चाहे होटलियर्ज़ हों या पर्यटन से जुड़े छोटे-छोटे व्यवसाय करने वाले व्यक्ति हों, उन सबको इस कोविड काल में बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी हम नये कंसैप्ट के साथ कुछ नई डेस्टिनेशन्ज डिवेलप करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री बी.एस.द्वारा.. जारी

02.03.2022/1210/बी.एस./एच0के0/-1

मुख्य मंत्री जारी...

जैसे हमने तत्तापानी में उस दिशा में प्रयत्न किया है, पौंग डैम में डेस्टिनेशन डवलप करने के लिए हम काम कर रहे हैं। इसी तरह बीड़-बिलिंग में हम प्रोजैक्ट को ए0डी0बी0 के अन्तर्गत ला करके वहां पर मई-जून में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की पैराग्लाइडिंग की डेस्टिनेशन डवलप कर रहे हैं। उसी तरह से ईको टूरिज्म में हम जंजैहली को लाने का प्रयत्नकर रहे हैं। उसमें भी हमें सफलता मिली है। लारजी और पंडोह डैम दोनों जगह पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयत्न किए हैं। हम धर्मशला में रोपवे की बातें सुनते थे, लेकिन रोपवे की कहानी सुनते-सुनते हमें उस पर हमें बोलना ही मुश्किल हो गया था। रोजवे का जब कार्य चला हुआ था, तो एक परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि कंपनी छोड़ कर ही जाने वाली थी। हमने कहा कि हम सरकार की ओर से जो भी सहयोग दे सकते हैं, उसे आपको देंगे। हमने उनकी मदद की और मुझे आज यह बताते हुए प्रशंन्नता हो रही है कि धर्मशाला में पौने दो किलोमीटर का हमारा रोपवे बन करके तैयार हुआ है और उसमें 207 करोड़ रुपए की लागत आई है और उसका उद्घाटन कर हमने उसे जनता को समर्पित कर

दिया है। इससे पर्यटन को एक नई पहचान मिली है। उसी तरह से लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से मण्डी में नेशनल हाइवे पर पंडोह से सीधा बगलामुखी माता के मंदिर तक का है, वहां पर हम इको टूरिज्म का पार्क डवलप कर रहे हैं। उसे कनेक्ट करने के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से एक नया प्राजैक्ट रोपवे का है, उसका हमने शिलान्यास कर दिया है और बहुत जल्द उसका कार्य भी आरंभ हो जाएगा। अटल टनल, रोहतांग अपने आप एक पर्यटन के लिए नई डेस्टिनेशन बन गई है। उसके नॉर्थ और साउथ पोर्टल के लिए कंसैप्ट तैयार किया गया है और वहां के लिए एक चीज की आवश्यकता है वह फोरेस्ट कलीयरेंस है। अगर यह होती है तो वहां पर भी हम प्रयत्न कर रहे है कि ज्यादा-से-ज्यादा पर्यटक आ सकें। उसी तरह से अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हर आदमी का अपना घर हो। हर बार जब भी बजट पेश होता था तो उनमें 3-4 हजार मकानों का लक्ष्य रखा जाता था, उस लक्ष्य को हमने बढ़ा करके 10 हजार किया और

उसके बाद हमने उसे 12 हजार किया है। हम अभी भी देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग मकानों की मांग करते हैं। हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा-से-ज्यादा लोगों की मदद कर सकें जिनका घर कहीं टूटे हैं, वे भी घर बना सकें और जिनका घर नहीं है, वे भी घर बना सकें। हालांकि हिमाचल ऐसा प्रदेश है, जहां पर सबके अपने-अपने घर हैं, चाहे वह कैसे भी हैं, हिमाचल प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां पर लोग फुटपाथ पर नहीं सोते हैं। हमने इसमें भी प्रयत्न किया है और हम इसमें काफी हद तक सफल भी हुए हैं।

जहां तक कोविड वेक्सीनेशन की यहां पर बात हुई, हमारे मित्रों ने बहुत सारी टिप्पिणयां इसमें की हैं। उसमें बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है जो कहने वाले थे, वे यहां नहीं बैठे हैं, वे कोविड के साथ अन्य बीमारियों की तुलना कर रहे थे। वे कह रहे थे कि हमने भी पोलियो और टी0बी0 का टीका हमने लगाया था। यहां पर आदरणीय राजेन्द्र राणा जी ने कहा कि जो आपकी बाजू में निशान है वह हमारा दिया हुआ है। आपके

निशान तो बहुत दिए हुए हैं, हम कौन-कौन से निशान दिखाएं? मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप कोविड की स्थिति की तुलना इस तरह से कर ही नहीं सकते। क्या पहले कोई ऐसी महामारी आई, जिसमें लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हुए? नहीं और यह स्थिति पूरी दुनिया में आई है। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस कोविड की स्थिति को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए जिस प्रकार के गंभीरतापूर्वक प्रयत्न किए गए।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

02-03-2022/1215/एच.के.-ए.जी. /1

मुख्य मंत्री..... जारी

डॉक्टर्ज़ ने कहा कि वैक्सीन के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है और वैक्सीन ही चाहिए। वैक्सीन को तैयार करने के लिए जब बात चली तो वे कहने लगे कि बहुत कठिन काम है और हम अपने देश में शायद ही कर पाएं। लेकिन आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि अपने देश के अंदर क्या कमी है और जो कमी है उसके बारे में बताओ हम सरकार की ओर से उसे दूर करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा है कि भारत का साइंटिस्ट इस देश के अंदर वैक्सीन बना कर तैयार करे और आज कोरोना की वैक्सीन हमारे देश में ही बन कर तैयार हुई। उसके बाद आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीन लगाने का अभियान भारत में चल रहा है। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस वैक्सीन के अभियान में हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है, चाहे वह पहली डोज़ में हो या दूसरी डोज़ में और तीसरी डोज़ जोकि 15 से 18 साल के बच्चों को लगाई जा रही है उसमें भी हिमाचल प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। विपक्ष के लोग उसको भी उपलब्धि नहीं मानते हैं। यह वही लोग हैं जो कहते थे कि यह मोदी वैक्सीन है, बी.जे.पी. वैक्सीन है, इसके कारण आने वाली जनरेशन बर्बाद हो जाएगी और यही लोग

मास्क पहन कर के वैक्सीन सैंटर में जाकर कह रहे हैं कि हमारी दो डोज़ तो लग गई हैं अब बूस्टर डोज़ लगाइए। विपक्ष की स्थिति बहुत विचित्र व हास्यास्पद है।

अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे विषयों पर बहुत सारी बातों को बोलने का मन था लेकिन विपक्ष के लोग यहां से चले गए। मैं उम्मीद करता हूं कि जब हमारा बजट प्रस्तुत होगा और उसके पश्चात उस पर सामान्य चर्चा होगी तब हम उसमें कुछ बातों का जिक्र करे लेंगे। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि महामहीम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया वह सरकार की उपलब्धियों का बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है।

02-03-2022/1215/एच.के.-ए.जी. /2

इसमें लिखी एक-एक योजना के माध्यम से हमने प्रदेश की जनता को राहत देने की कोशिश की, प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने की कोशिश की और प्रदेश के हर वर्ग को मदद करने के रास्ते तलाशे हैं। विपक्ष के लोग यहां से चले गए क्योंकि वे अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए। हमने उनसे कहा था कि पूर्व में पांच साल जब कांग्रेस की सरकार थी तबकी एक ऐसी योजना का जिक्र यहां पर करो जिसको लोग आज भी याद करते हों। उस समय ऐसी कोई योजना थी ही नहीं और उनके कार्यकाल में तो इस माननीय सदन में क्या-क्या चीचें गूंजती रही उस बारे में मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि आप सभी को वह अच्छी तरह से मालूम हैं। पूरा पांच साल का कार्यकाल उन्होंने ऐसे ही निकाल दिया और जब अंतिम वर्ष आया तब केवल घोषणाएं कर दी गईं। लेकिन हमारी सरकार ने पहले दिन से ही प्रदेश में काम किया और मनुष्य के जीवन को बेहतर करने का प्रयत्न तो किया ही बल्की बेजुबान जानवर के लिए भी कार्य करने की हमारी मंशा रही। पिछले पांच वर्षों में इस देवभूमि की संस्कृति के अनुरूप सरकार चलाने का हमारा एक अलग तरह का प्रयास रहा है। मैं विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस माननीय सदन से वॉकआऊट तो कर दिया लेकिन उनके पास इसका कोई तर्क नहीं था। वे लोग यहां से उठकर चले जाना चाह रहे थे क्योंकि उनकी मजबूरी थी लेकिन उनके पास इसके लिए कोई ठोस बात नहीं

थी। उन्होंने बीच-बीच में जिन मुद्दों को उठाया हम उनका जवाब देते रहे लेकिन फिर भी वे यहां से चले गए। वे लोग विपक्ष में हैं, उन्होंने सरकार का विरोध करना है और हम उनसे किसी प्रकार के सहयोग की बात करते हैं तो हमें भी उनसे सहयोग की ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। किसी सरकार का जब पांचवां साल आता है तब स्वभाविक रूप से विपक्ष के लोग हर बात को लेकर इसी प्रकार से करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग कर्मचारियों के अलग-अलग वर्ग को भड़काने का गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं। यह सब किसी भी प्रकार से प्रदेश के हित में नहीं है।

02-03-2022/1215/एच.के.-ए.जी. /3

यह हमारी ही सरकार है जिसमें कर्मचारियों के हर वर्ग के सभी ड्यूज़ को दिया गया है। कर्मचारी वर्ग इस बात से सहमत भी है कि वर्तमान सरकार ने कोविड काल में भी कर्मचारियों की सैलरी व पैंशन देने के लिए एक दिन की भी देर नहीं की। बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां पर कर्मचारियों की सैलरी काटी या रोक दी गई। मैं अभी कुछ समय पहले एक प्रदेश में गया था तो उसमें ओवर ड्राफ्ट चल रहा है और 20 या 25 तारीख के बाद कर्मचारियों को सैलरी मिलती है। यह सही है कि कर्मचारियों की कुछ वास्तविक समस्याएं हैं और हम उन्हें खुले मन से हल करने के लिए तैयार हैं। मेरा मानना है कि कर्मचारी वर्ग सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है और उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। लेकिन अपनी बात कहने के लिए आंदोलन ही कोई रास्ता होगा और कोई आंदोलित हो करके अपनी बात कहेगा, उस बात को हम स्वीकार करेंगे तो यह

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

02.03.2022/1220/DC/JS/1

मुख्य मंत्रीः------जारी------

जरूरी नहीं है। वे अपनी बात कहें, शांति पूर्वक ढंग से कहें और सारी बात समझने के बाद कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, उस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, हम ईमानदार प्रयत्न पहले भी करते रहे हैं और अब भी करेंगे इसलिए जो कर्मचारी कुछ लोगों के कहने पर आंदोलन करने जा रहे हैं, मैं उनसे विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि वे आंदोलन की राह छोड़ करके हमारे पास आएं और चर्चा करें। आप लोग अपना सुझाव दीजिए। हम रास्ता निकालने का प्रयत्न करेंगे। अगर रास्ता निकलता है तो प्रयास करेंगे। कुछ राजनीतिक नेताओं की कठपुतली मत बनिए, यह मैं यहां पर जरूर कहना चाहूंगा। हमने हमेशा कर्मचारियों के हित की रक्षा की है। आज भी हम उसके पक्षधर हैं, चाहे कर्मचारियों का कोई भी वर्ग है। पी.टी.ए. वाले कहां तक लड़ते रहे लेकिन राहत उनको तब मिली जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई। एस.एम.सी. को बाहर कर दिया गया था। हम उनकी मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट तक खड़े हुए। आज एस.एम.सी. उस स्थान पर नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी मदद की है। यहां पर जो ओ.पी.एस. और एन.पी.एस. का इशू खड़ा किया गया है, उसमें हम प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या रास्ता निकलता है। हमने उसके लिए तय किया है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करके वे इस सारे मामले का अध्ययन करेंगे और उससे जो रास्ता निकलेगा उसमें आने वाले समय में विचार करेंगे। मेरा उन सभी भाइयो और बहनों से निवेदन है कि आंदोलन का रास्ता छोड़ करके अपने सुझाव हमें दें। उस दिशा में क्या रास्ता निकलता है, क्या किया जा सकता है उस पर हम विचार करेंगे।

इसके अलावा करूणामुलक आधार का जो एक वर्ग धरने पर बैठा है, उनसे भी मेरा निवेदन है, हमने उनकी पहले भी मदद की है और अब भी करेंगे। कांग्रेस

02.03.2022/1220/DC/JS/2

सरकार के समय में यदि कोई कर्मचारी 50 साल की उम्र के बाद मरता था उसके आश्रितों के लिए नौकरी का कोई प्रावधान नहीं होता था। हमने कहा कि यह आदमी के हाथ में नहीं है। अगर कोई आदमी नौकरी करते-करते रिटायरमैंट से दो दिन पहले भी मरता है तो

हमने कहा कि उसके परिवार के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। हमने दो बार उनके लिए प्रयास किया है उनकी इन्कम का जो स्लैब था उसको दो बार बढ़ाया है। हम उसमें और भी खुले मन से मदद कर रहे हैं। हमने उनको एक ऑफर दिया है और उसके तहत हमने तय किया है कि अगर चतुर्थ श्रेणी के जो एक हजार तक रिक्त पद पड़े हुए हैं, यदि उनमें कोई अपनी ऑप्शन देना चाहे तो वह दें, उनको हम तुरन्त नौकरी देंगे। बहुत सारे बच्चों ने अपनी ऑप्शन दी भी है। आगे भी चतुर्थ श्रेणी के लिए यदि कोई अपनी ऑप्शन देता है तो तुरन्त उसको नौकरी देंगे। इसके बाद जो रिमेनिंग पोस्टें हैं, उनके लिए क्या रास्ता निकलता है, उन सारी बातों को ले करके हम खुले मन से विचार करने के लिए तैयार हैं। मेरा उनसे यह कहना है, वे किसी के कहने पर धरने पर बैठ गए लेकिन उनको अपना धरना समाप्त करना चाहिए और सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। हमसे बेहतर उनके लिए कोई रास्ता नहीं दिखा पाया था। जो मदद हमने उनकी की है वह आज से पहले कांग्रेस की सरकार ने नहीं की है। जितने भी हमारे कर्मचारी वर्ग हैं, सभी से मेरा विनम्र आग्रह रहेगा कि अपने सुझाव दें चाहे पे कमिशन से संबंधित बाते करते हैं, चाहे दूसरे इशूज़ के ऊपर अपनी बातें करते हैं, उनका सिलसिलेवार समाधान की दृष्टि से प्रयत्न करेंगे ताकि कर्मचारी जो महत्वपूर्ण भूमिका हिमाचल प्रदेश के काम में निभाते हैं, विकास में निभाते हैं, उनकी हम मदद कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण इस माननीय सदन में दिया, मैं इस सदन की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस धन्यवाद प्रस्ताव के लिए डॉ0 राजीव बिन्दल जी, जिन्होंने इसको मूव किया और श्री बलबीर सिंह जी ने इसका अनुसमर्थन किया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मैं इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करता हूं

श्री एस.एस. द्वारा जारी--------

02.03.2022/1225/SS-YK/1

मुख्य मंत्री क्रमागत :

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान हेतु प्रस्तुत करता हूं। तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्न शब्दों में उनकी सेवा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाए :-

च्इस सदन में एकत्रित सदस्य राज्यपाल महोदय का दिनांक 23 फरवरी, 2022 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए ह्दय से आभार प्रकट करते हैं।छ

प्रस्ताव स्वीकार

02.03.2022/1225/SS-YK/2

नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

अब नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव होंगे। अब श्री सुभाष ठाकुर जी नियम-130 के अंतर्गत अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री सुभाष ठाकुर (बिलासपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना के कार्यालय को चंडीगढ़ से बिलासपुर में स्थापित करने पर यह सदन विचार करे।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया बैठिए। तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना के कार्यालय को बिलासपुर में स्थापित करने पर यह सदन विचार करे।

अब माननीय सदस्य श्री सुभाष ठाकुर जी अपनी बात रखेंगे।

श्री सुभाष ठाकुर : अध्यक्ष जी, आपने मुझे मेरे चुनाव क्षेत्र से गुजरने वाली रेल लाइन, जिसका हिमाचल प्रदेश के लिए और सामरिक दृष्टि से भी एक विशेष महत्व है, पर नियम-130 के अंतर्गत बोलने के लिए अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा।

अध्यक्ष जी, भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी ब्रॉडगेज रेल लाइन जो भारत सरकार व हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयासों व अनुकम्पा से स्वीकृत हुई है, वह श्री नैना देवीजी निर्वाचन क्षेत्र और मेरे सदर बिलासपुर चुनाव क्षेत्र के बेरी-बरमाणा तक 55 गांवों से होकर गुजरेगी। इसमें 20 सुरंगे, 20 पुल, 23 सम्पर्क मार्ग, 4 रेलवे स्टेशन और 2 घाटी पुल बनेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत-सी उपजाऊ भूमि, लोगों के मकान और गऊशालाएं आती हैं। मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि इससे पूर्व भी बी0बी0एम0बी0 के माध्यम से बिलासपुर की जमीन एक्वायर की गई थी। यह सतलुज नदी के किनारे और खड्डों के किनारे की भूमि थी। हमें उसमें बड़ा कम मुआवजा मिला है।

02.03.2022/1225/SS-YK/3

(माननीय सदस्य, श्री विक्रमादित्य सिंह, श्री रोहित ठाकुर और श्री संजय अवस्थी माननीय सदन में पुनः उपस्थित हुए।)

उसमें हमारे अधिकार भी सुरक्षित थे कि जब यह डैम नीचे उतरेगा तो उसके बाद जमीन को कल्टीवेट कर पाएंगे। लेकिन वर्तमान में सिल्ट के कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और आज भी जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए थीं वे नहीं मिल पाई हैं। इसलिए जो लोग ऑस्टीज हुए हैं वे आज भी उसका दंश झेल रहे हैं।

(श्री नरेन्द्र ठाकुर, माननीय सभापति पीठासीन हुए।)

लेकिन दोबारा जो ऑस्टीज हो रहे हैं उनको यह आशंका है कि कहीं उनके साथ पुनः ऐसा न हो जिससे उनको रोजी-रोटी के भी लाले पड़ें। इसी संदर्भ में मैं इस प्रस्ताव को लाया हूं और जो यह नई ब्रॉडगेज रेललाइन है इसमें

जारी श्रीमती के0एस0

02.03.2022/1230/केएस/एजी/1

श्री सुभाष ठाकुर जारी---

हमारा एक बध्यात गांव है। यहां तक 99 मकान और 48 पशुशालाएं इसकी जद में आएंगी। इसके अलावा इसके आगे भी इसका अधिग्रहण हो रहा है जो कि नोग से गांव बरमाणा तक होगा। इसमें भी 238 मकान और 54 पशुशालाएं अधिग्रहण की जाएंगी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी बतलाना चाहूंगा कि हमारे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में जो अति उपजाऊ भूमि थी वह पहले ही बी.बी.एम.बी., ए.सी.सी., कोल डैम, नेशनल हाईवे और टावर लाइन निर्माण की बलि चढ़ चुकी है। अब इस रेल लाइन के कारण जो हमारे गांव इसमें आ रहे हैं, जहां लोग बेघर हो रहे हैं, उनमें पडगल, भराड़ी, मंडी माणवा,खनसरा, रघुनाथपुरा, कोहलवीं, बलोह, बामटा, बैहल कंडेला, बध्यात, खैरियां, लूहणू, नोग बगड़ी, ऊपरली भटेड, डियारा, बिलासपुर, खतेड बरमाणा के लोग इससे पहले भी दो से चार बार विस्थापन का दंश झेल चुके हैं।

सभापति महोदय, गत दिवस मैं बरमाणा गया था। वहां पर लोगों को यह आशंका है, उनका कहना है कि हम दो-दो बार यहां से उजड़ चुके हैं अब यह भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन बरमाणा गांव से इस प्रकार गुजरती है कि वहां पर एक तरफ ए.सी.सी. सीमेंट फैक्टरी का कोयला, पत्थर, स्क्रैप यार्ड है और दूसरी तरफ नई रेलवे लाइन गुज़रने का प्रस्ताव है जिससे सीधा-सीधा लाभ ए.सी.सी., अम्बुजा, अल्ट्राटैक सीमेंट, फैक्ट्रियों को होगा जबकि जो वहां के लोग हैं, उनको दोनों तरफ से प्रदूषण और वाइब्रेशन झेलनी पड़ेगी। मेरा निवेदन है कि इसे कहीं और जगह पर शिफ्ट किया जाए ताकि कम से कम लोगों का विस्थापन हो। कई परिवारों की स्थिति तो ऐसी भी हो गई है कि रेवले परियोजना के माध्यम से उनकी जमीन और रिहायशी मकान, सारा कुछ उसमें आ रहा है तो उनको आने वाले दिनों में हिमाचली सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पाएगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति भूमिहीन नहीं होना चाहिए और हमारे रेलवे स्टेशन और याड्र्ज़ कल्टिवेटिड जमीन और रिहायशी मकानों से हटकर हों ताकि स्टेशन भी

02.03.2022/1230/केएस/एजी/2

बनें, रेल लाइन भी आए। इससे हिमाचल प्रदेश में औद्योगीकरण भी होगा, यहां पर टूरिस्ट भी आएगा और यहां के बागवानों का फ्रूट भी अनेकों प्रदेश में जाएगा लेकिन जो तीन-तीन, चार-चार बार विस्थापित हो रहे हैं, उनके बारे में भी सदन विचार करें। जिनके पास मकान और रिहायशी भूमि नहीं बच रही है, उनके बारे में भी सरकार चिंता करें और उनको उचित मुआवजा भी दिया जाए।

सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि इस परियोजना का निर्माण कार्य रेलवे विकास निगम के माध्यम से हो रहा है। इस काम के लिए जो इसका कार्यालय खोला गया है वह चंडीगढ़ में है। उसको बिलासपुर में स्थानांतरित किया जाए ताकि वहां के लोग और अन्य जनप्रतिनिधि रेल विकास निगम से अपनी समस्याओं और कठिनाइयों के बारे में आसानी से बातचीत कर सके। हालांकि मैंने इस मामले को उच्च स्तर भी उठाया था लेकिन रेलवे विकास निगम के अधिकारी बिलासपुर से 150 किलोमीटर दूर हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

02.03.2022/1235/av/ag/1

श्री सुभाष ठाकुर---------- जारी

ये अधिकारी इस राष्ट्रीय महत्व की परियोजना को चंडीगढ़ से रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चला रहे हैं। ये रेलवे विकास निगम के अधिकारी तथा कर्मचारी चंडीगढ़ में बैठकर मुफ्त में हार्डशिप प्रोजैक्ट अलाउंस ले रहे हैं जोकि नियमों के खिलाफ है। रेलवे विकास निगम के अधिकारियों से आम लोगों द्वारा अपनी समस्याओं को उठाना तो दूर की बात है परंतु यदि

हमारे उपायुक्त, बिलासपुर को भी उनसे बातचीत करनी हो तो उन्हें 150 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ जाना पड़ता है। यदि रेलवे के अधिकारी व कर्मचारी बिलासपुर का दौरा करते हैं तो वे उसके लिए बिलासपुर से टी0ए0/डी0ए0 लेते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि यदि रेलवे विकास निगम के अधिकारी का कार्यालय बिलासपुर में स्थापित होगा तो इस परियोजना का कार्य तीव्र गति से चलने के साथ-साथ इसका स्थानीय लोगों को भी लाभ मिलेगा। ऐसा करने से वहां के स्थानीय लोगों को सहूलियत ही नहीं मिलेगी बल्कि उनके मूल वेतन के अलावा जो उसका 10 प्रतिशत हार्डशिप अलाउंस वे चंडीगढ़ में बैठकर ले रहे हैं; उसकी बचत भी होगी। अभी तो चंडीगढ़ में बैठकर वे अपने वेतन के साथ जो हार्डशिप अलाउंस भी ले रहे हैं; एक धोखा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कार्यालय बिलासपुर शिफ्ट होना चाहिए और आज दिन तक जो इन्होंने अलाउंसिज लिए हैं उसकी भी रिकवरी होनी चाहिए। मैंने इसी संदर्भ में केंद्रीय रेल मंत्रलाय से भी पत्राचार किया था और रेलवे विकास निगम जो केवल इसी एक प्रोजैक्ट के लिए काम कर रहा है; उसका कार्यालय बिलासपुर लाना जनहित में ठीक रहेगा। लेकिन जब हमने पत्राचार के माध्यम से इस सारे मुद्दे को केंद्रीय रेल मंत्रालय से उठाया तो रेलवे विकास निगम ने चालाकी से भटिंडा रेल लाईन का चार्ज भी इनको दे दिया। इस प्रकार से चंडीगढ़ कार्यालय को बचाने के लिए लीपापोती की गई है ताकि वे यह बहाना लगा सकें कि चीफ प्रोजैक्ट मेनेजर के पास भटिंडा का चार्ज भी है। परंतु इस प्रकार की सारी कार्रवाई हमारे केंद्रीय रेल मंत्रालय से पत्राचार के बाद की गई है और उनको भटिंडा रेल लाईन का

02.03.2022/1235/av/ag/2

एडिशनल चार्ज दिया गया है ताकि इस आड़ में कार्यालय को बिलासपुर शिफ्ट न करना पड़े। जब यह कार्यालय भानुपल्ली–बिलासपुर–बेरी रेल लाइन के उद्देश्य से खोला गया है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यह कार्यालय बिलासपुर में स्थापित होना चाहिए ताकि यहां के लोगों के समक्ष आ रही दिक्कतों का समाधान हो और जल्दी से अधिग्रहण का कार्य

भी पूरा हो। अभी भी बहुत जगह पर नेगोसिएशन न होने के कारण भूमि अधिग्रहरण का कार्य पूरा नहीं हुआ है। अगर इस विषय में उपायुक्त, बिलासपुर से बातचीत की जाती है तो उन्हें भी इन मामलों को लेकर चंडीगढ़ जाना पड़ता है। कभी अगर रेलवे विकास निगम के अधिकारी या कर्मचारी बिलासपुर आते भी हैं तो उनको इस बात की जानकारी नहीं होती जिसके कारण उनसे बातचीत नहीं हो पाती। इसलिए यदि यह कार्यालय बिलासपुर शिफ्ट होता है तो इससे लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रेलवे स्टेशन और यार्ड इत्यादि ऐसे क्षेत्रों में बनाए जाएं जहां पर आबादी कम हो और कृषि योग्य भूमि का कम-से-कम अधिग्रहण हो। कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण से उनके परिवारों को बाद में रोजी-रोटी का संकट भी पैदा हो सकता है। इसलिए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जब तक इसमें विस्थापित हुए लोगों को उचित मुआवजा न मिले या उनका बसाव न हो तब तक उनकी भूमि का अधिग्रहण न किया जाए। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चीफ प्रोजैक्ट मेनेजर के कार्यालय को स्थाई तौर पर चंडीगढ़ से बिलासपुर शिफ्ट करने बारे मजबूती से कदम उठाए जाएं क्योंकि यह परियोजना राष्ट्रीय हित से जुड़ी है।

टी सी द्वारा जारी

02/03/2022/1240/टी0सी0वी0/ए0एस0/1

श्री सुभाष ठाकुर... जारी

जिससे न केवल यह परियोजना समय पर पूरी होगी अपितु लागत भी कम होगी। सभापति महोदय, बिलासपुर के जिन लोगों की भूमि और मकान इसमें आ रहे हैं या जो लोग भूमिहीन हो रहे हैं उनको हिमाचली प्रमाण-पत्र भी नहीं मिलेंगे। मेरा अनुरोध है कि जो भूमिहीन होंगे उनको जगह दी जाए ताकि यह विस्थापन का दंश जो बिलासपुर के लोगों को बार-बार झेलना पड़ रहा है, उससे निजात मिले क्योंकि बी0बी0एम0बी0 से जो लोग उजड़े हैं, उनको जो सहुलियतें मिलनी चाहिए थी वे आज भी नहीं मिल ही हैं। बल्कि

जिनकी 5 या 10-15 बीघा जमीन गई हैं उनको 1800 वर्ग मीटर का एक प्लॉट दिया गया है। यह हालत शहर के साथ-साथ गांव की भी है। जो लोग हिसार में बसे थे, उनको आज भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनको आज भी आउट साइडर माना जा रहा है। उनको जमीनों के बदले न तो भूमि मिली है और न ही मकान मिले हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब हम दोबारा रेलवे के कारण उजड़ जाएंगे। जहां तक भरमाणा का संबंध है, उसका ए0सी0सी0 फैक्टरी द्वारा अधिग्रहण किया गया है। जब दूसरा प्लांट लगा तो दोबारा वे लोग उजड़े और उनको तीसरी जगह मकान डालने पड़े। इसलिए इस ए0सी0सी0 फैक्टरी का भी पता किया जाए। मेरी जानकारी के मुताबिक इसका काम सिर्फ 15-20 साल तक ही है। उसके बाद इनके पास सीमेंट का पत्थर नहीं है। इसलिए 15 सालों के लिए इन लोगों को वहां से उजाड़ना ठीक नहीं है। ब्रांस की धार में जहां इनकी यह सुरंग निकलती है, वहां पर रेलवे स्टेशन बनाया जा सकता है। वहां जो ए0सी0सी0 की कॉलोनी है उसमें बहुत कम लोग रह रहे हैं। उनके काफी लोग सेवानिवृत्त हो गए है और इन्होंने कुछ स्टॉफ भी कम कर दिया है। उनका ग्राउंड भी खाली है। यदि यह रेलवे स्टेशन वहां बनता है तो ये लोग भी उजड़ने से बचते हैं और फैक्टरी को भी फायदा होगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे बहुत कम गांव हैं जिनकी नेगोशिएशन हुई है और अब उनको एक्ट के माध्यम से क्वायर करने की योजना है। इनमें कोलवी, बलोह, दयारा, रोडा, कोसनिया, लुणू, बाम्टा, बैहल, भध्यात,

02/03/2022/1240/टी0सी0वी0/ए0एस0/2

मंडी, बाणवा, रामपुर, खंसरा, रघुनाथपुरा, कोठीपुरा, बडगल, भराड़ी इत्यादि बहुत से ऐसे गांव हैं जिनके साथ नेगोशिएशन नहीं हुई है। इनको एक्ट के माध्यम से एक्वायर करने के लिए कहा जा रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हर जगह क्रो-फ्लाई के तहत जमीनों अधिग्रहण किया जाता है और बहुत-सी स्कीमें हैं जिनको लांच भी किया जाता है। नेशनल हाइवे में जहां से रेलवे जा रही है, अगर इसको

क्रो-फ्लाई के हिसाब से उनका अधिग्रहण हो तो यह रेलवे लाइन जहां से जाएगी इसकी दूरी सभी के लिए एक समान होगी।

एन0एस0 द्वारा .... जारी

02-03-2022/1245/NS/AS/1

श्री सुभाष ठाकुर .....जारी

लोगों को जो लगता है कि मेरे गांव को कम मिला है और दूसरे गांव को ज्यादा मिला है तो यह समानता भी उसमें आएगी। अगर इसको क्रो फ्लाइ से लेते हैं, नेशनल हाइवे से यह रेलवे लाइन इन गांवों से या सतलुल के किनारे से गई है तो सभी को एक समान मुआवज़ा मिलेगा। इसलिए इनको ज्यादा-से-ज्यादा मुआवज़ा दिया जाए। निश्चित तौर पर इस कार्यालय में लगे कर्मचारियों को भत्ते भी मिल रहे हैं और मूल वेतन का 10 प्रतिशत भी मिल रहा है लेकिन वे चंडीगढ़ से ही आपरेट कर रहे हैं। वहीं से अपना टूअर प्रोग्राम बना रहे हैं। सभापति महोदय, इसको बिलासपुर में स्थानांतरित किया जाए क्योंकि यह सिर्फ़ भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी ब्रॉड गेज रेल लाइन के लिए है। इससे पैसा भी बचेगा और जल्दी तैयार होगी। मैं आपसे ऐसा निवेदन करता हूं। सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय हिमाचल।

02-03-2022/1245/NS/AS/2

सभापति : अब इस चर्चा में श्री जीत राम कटवाल जी भाग लेंगे।

श्री जीत राम कटवाल : सभापति महोदय, नियम-130 के अंतर्गत श्री सुभाष ठाकुर जी ने जो प्रस्ताव 'भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी ब्रॉड गेज रेल लाइन परियोजना के कार्यालय को बिलासपुर में स्थापित करने पर यह सदन विचार करे।' लाया है; आपने इस पर बोलने के लिए समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। रेलवे विकास निगम लिमिटिड का दफ्तर चंडीगढ़ में काम करता है। जिला बिलासपुर इस तरीके की गतिविधियों से बहुत भुगता है। राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय प्रयास की बात होती है। बिलासपुर व कांगड़ा के जब बांध बने थे तो उसमें भी राष्ट्रीय हित की बात थी और आज दिन तक लोग सफर कर रहे हैं तथा उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसका एक ही कारण है कि अधिकारी हुक्मरान

इतने दूर बैठते हैं और उनका काम करने का तरीका ऐसा है जैसे अंग्रेजों के जमाने में हुआ करता था कि 'Order is order'. केंद्र सरकार के अधिकारियों का ज्यादातर यही मत है। वे कहते हैं कि हम इस बारे में सरकार से बात करेंगे।

मेरा भी अनुभव है और मेरे चुनाव क्षेत्र में फोरलेन का काम चला हुआ है। लोगों के घरों को और उनके Access Easement Rghts को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं और कहते हैं कि National Highways Authority of India को प्रपोजल भेजेंगे। अगर प्रपोजल भेजना ही है तो पहले भेज लो। फिर काम करवा के गरीब आदमी को क्यों मार रहे हैं? गरीब आदमी को परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है और फिर बोलेंगे कि पेपर भेज देंगे। वर्ष 2013-14 से फोरलेन का काम चला हुआ है और इसमें भी कोताही है।

सभापति महोदय, श्री सुभाष ठाकुर जी ने ठीक कहा कि प्रदेश में यह चौथी रेलवे लाइन है। दो रेलवे लाइनें अंग्रेजों के वक्त की बनी हुई हैं। पहली पठानकोट-जोगिन्द्रनगर रेलवे लाइन की लंबाई 164 किलोमीटर है और दूसरी शिमला-कालका रेलवे लाइन की लंबाई 96 किलोमीटर है। तीसरी नंगल-ऊना-तलवाड़ा रेलवे लाइन भारतीय जनता पार्टी के टाइम में शुरू हुई और इसमें ज्यादा काम हुआ है, बजट का आबंटन हुआ और इसका भी काम चला हुआ है तथा वहां पर भी कुछ इश्यूज आए होंगे। अगर इन सारे इश्यूज को देखा जाए तो हमने देखा है कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी 63 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनने जा रही है और इसमें अंतर्विरोध हो रहा है। यह लगभग 2748 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है और इसमें 25 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश सरकार ने देना है और 75 प्रतिशत केंद्र सरकार दे रही है। प्रदेश सरकार के लगभग 490 करोड़ रुपये लगने हैं और 2258 करोड़

02-03-2022/1245/NS/AS/3

रुपये केंद्र सरकार के लगने हैं तथा इसके अलावा Balance of convenience केंद्र सरकार की है। उसमें यह लिखा गया है कि 70 करोड़ रुपये से अगर लैंड एक्विजिशन एक्सीड करेगी तो वह पैसा भी राज्य सरकार को देना पड़ेगा।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी

02.03.2022/1250/RKS/DC-1

श्री जीत राम कटवाल...जारी

इसके साथ सामाजिक प्रभाव आकलन का मसला भी जुड़ा हुआ है। माननीय सदस्य, श्री सुभाष ठाकुर जी ने सामाजिक प्रभाव आकलन की बात की है। इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा यह सब देखने की चीज है। अगर हम दूरदर्शिता से काम लें तो इससे हमारे गरीब आदमियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ सकता। लैंड एक्विजिशन विंग में 21 पद स्वीकृत हैं लेकिन वहां अभी 13 ही लोग काम कर रहे हैं। शायद वहां रिटायर्ड व्यक्ति कार्य कर रहे होंगे। 20 किलोमीटर तक लैंड एक्वायर हो गई है। 52 किलोमीटर तक काम चला हुआ है। इसमें 80-90 या 100 किलोमीटर तक लैंड एक्वायर की जाएगी और कुछ सरकारी भूमि भी दी जाएगी। यह अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश में इस तरह के प्रोजैक्ट आ रहे हैं। लेकिन इन प्रोजैक्टों का बूरा प्रभाव न पड़े यह भी देखने की बात है। बिलासपुर में एक छोटा-सा दफ्तर जहां एक या दो लिपिक और एक चपरासी कार्यरत है, स्थापित किया गया है। असली रेलवे विकास निगम लिमिटिड चंडीगढ़ से काम करती है। माननीय सदस्य, श्री सुभाष ठाकुर जी ने कहा कि वह हार्ड एरिया है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि सही काम प्रोजैक्ट एरिया में बैठकर ही किया जा सकता है। जब बी.बी.एम.बी. ने लैंड एक्वायर की तो सन् 1971 तक कोई पोलिसी नहीं बनाई गई। वहां आज भी कुछ लोग जंगलों में रह रहे हैं। फोरलेन व रेलवे प्राजैक्ट से इसी तरह का हाल यहां भी होने जा रहा है। जैसा माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि इस योजना के तहत 36 पुल और कुछ सुरंगे बनाई जाएंगी। इस प्रोजैक्ट को केंद्रीय मद के अंतर्गत डील किया जा रहा है और इसके कार्यान्वयन में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग है। मैं यह चाहूंगा कि मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की जो रोड कनैक्टिविटिज रेलवे को टच कर रही है वहां विशेष तौर पर रेलवे स्टेशन स्थापित किए जाएं ताकि झण्डूता चुनाव क्षेत्र के लोगों को वहां से आने-जाने की सुविधा मिल सके। उन्हें फोरलेन या बी.बी.एम.बी. की तरह ठगा न जाए। वे बी.बी.एम.बी. के कारण आज तक अपने आपको स्थिर नहीं कर पाए। वे आज भी बिजली व पानी के कनैक्शन्ज

02.03.2022/1250/RKS/DC-2

से वंचित हैं। भानुपल्ली-बिलासपुर रेलवे लाइन 63 किलोमीटर की चौथी रेलवे लाइन है। हमें इन प्राजैक्टों की गतिविधियों को देखते-देखते अच्छे अनुभव होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को आंदोलनों में जाना पड़े या विधान सभा में चर्चा करके इसका कोई हल न निकले। बी.बी.एम.बी. और पौंग बांध का मुद्दा आजतक हल नहीं हुआ है। पिछले अनुभवों से सीखकर हमें रेलवे लाइन की इम्प्लिमेंटशन के लिए ज़िला बिलासपुर के चुने हुए प्रतिनिधियों की एक कमेटी का गठन करना चाहिए ताकि जो सामाजिक प्रभाव आकलन किया जाता है उस पर नज़र रखी जा सके। सामाजिक प्रभाव आकलन के नाम पर वे अपना टारगेट्स पूरा करने की कोशिश करते हैं। टारगेट्स पूरे होने चाहिए लेकिन आम जनमानस की सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए। जो वहां पर एक छोटा-सा दफ्तर स्थापित किया है मैंने उसके बारे में उपायुक्त महोदय से बात की थी। उन्होंने मुझे बताया कि वहां पर एस्टाब्लिशमेंट के आदमी बैठे हैं। वहां पर कोई इंजीनियर या अधिकारी नहीं हैं जो कोई निर्णय ले सके। जब किसी आम-आदमी को दिक्कत आती है तो उसे चंडीगढ़ जाने की नोबत नहीं आनी चाहिए।

श्री बी.एस.द्वारा.. जारी

02.03.2022/1255/बी.एस./डी0सी0/-1

श्री जीत राम कटवाल जारी...

आम आदमी को जो दिक्कत हाती है, तो उसे चण्डीगढ़ नहीं धकेलना चाहिए। उसकी सुनवाई उपायुक्त के कार्यालय, जो आसपास होगा उसमें होनी चाहिए। इसिलिए जो भी उसे उचित लगेगा या उपायुक्त से या किसी रेलवे की ऑथोरिटी से बात करनी होगी तो उसे वहां पर ही मौका मिलना चाहिए। यह सारी चीजें हैं। हालांकि यह काबिले तारीफ काम

है, इसमें काफी काम हुआ है और इसमें 22-23 सौ करोड़ रुपया रिलीज भी हुआ है। परंतु उसे रिलीज करने के साथ-साथ जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो इस क्षेत्र को देख रही है, वह यहां कार्यालय स्थापित करें और यहां काम करें और काम करके हमारे लोगों की जो समस्या हैं उनके ऊपर भी गौर होनी चाहिए। मैं ज्यादा न कहते हुए, ये जो दो बातें कही हैं, फोरलेन के पास भी रेलवे स्टेशन और बाघछाल पुल के पास भी रेलवे स्टेशन होना चाहिए। वहां से भी एक हाइवे की योजना चल रही है। झंडुता चुनाव क्षेत्र को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदय, आपने मुझे बोलना का समय दिया, आपका धन्यवाद, आभार, जय हिन्द॥

02.03.2022/1255/बी.एस./डी0सी0/-2

सभापति : अब इस चर्चा में श्री होशयार सिंह जी भाग लेंगे।

श्री होशयार सिंह, देहरा : सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया आपका धन्यवाद, "भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना के कार्यालय को बिलासपुर में स्थापित करने हेतु जो आदरणीय सुभाष ठाकुर जी ने नियम-130 के अन्तर्गत पस्ताव रखा है, इस पर मैं भी शामिल होना चाहता हूं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कुछ बातें जरूर रखूंगा, मुझे हमारे इलाके में जो अनुभव हुआ है और रेलवे एक ऐसा विभाग है, जो हमारे लोकल प्रशासन को बिल्कुल नहीं मानता है। हमें खुशी है कि रेलवे लाइन आ रही है, इस इलाके में बहुत बड़ी डवलपमेंट हो रही है। लेकिन जो गलतियां पिछली पठानकोट-जोगिन्दर नगर रेल बिछी थीं, वे गलतियां यहां न हों। पहला प्वाइंट तो यह है कि हर किसी को कंपनसेशन मिलना चाहिए। पोंग डैम विस्थापितों को आज भी कंपनसेशन नहीं मिला है, पिछले 55 सालो से आज भी वे न्यायालय और दफ्तरों में भटक रहे हैं परंतु आज भी उन्हें कंपनसेशन नहीं मिला है। जो एग्रीमेंट बी0बी0एम0बी के साथ वर्ष 1970 में बनाया था उसे मान्यता नहीं दी गई। हमारी जनता के साथ फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि अंडर पास या ओवर ब्रिज बनाना बहुत जरूरी है। आज मेरे क्षेत्र में नगरोटा-सुरिंया से ले करके रानी ताल तक केवल एक क्रोसिंग है। आज भी बीमार

आदमी को मंजे पर उठा करके ले जाना पड़ता है। क्योंकि वहां न काई ओवर ब्रिज नहीं है, न अंडर ब्रिज है और न ही क्रोसिंग है। वहां के एरियाज को दो भागों में बांट दिया गया। एक तरफ सड़क है और दूसरी तरफ सड़क नहीं है। वहां जंगलात का एरिया भी है और एक तरफ रेलवे लाइन है। आज भी मकान बनाने के लिए खचरों पर रेत, बजरी और इंटें ढोने पड़ती हैं। वहां 40 किलोमीटर के क्षेत्र में सिर्फ एक लेवल क्रोसिंग है। जब यह परियोजना बन रही है तो हर कार्य के लिए पाथ होना बहुत जरूरी है। अन्यथा जैसे हम रो रहे हैं वैसे ही बिलासपुर की जनता भी रोएगी। दूसरी बात आज रेलवे विभाग अंडर ब्रिज एक पानी की पाइप डालने के लिए 75 लाख रुपए लेता है। मैं परसों ही एक पाइप डाल करके आया हूं। 35 लाख रुपए भारने के बावजूद एक साल रेलवे ने वह पाइप नहीं डाली और चार करोड़ रुपए की मेरी पानी की स्कीम बंद पड़ी है। हमने जबदस्ती पानी की पाइप डाल दी है मैंने कहा कि आपने एफ0आई0आर0 करनी है कर दो, आपने अरेस्ट करना है कर दो

02.03.2022/1255/बी.एस./डी0सी0/-3

परंतु में अपने 10 हजारा लोगों को गर्मियों में प्यासा नहीं मार सकता। रेलवे लाइन के नीचे से जो भी पाइप लाइन जाएगी उसका एक भी पैसा नहीं दिया जाए। यह अच्छा होगा कि आप एडवांस में इन पाइपों को डाल दें। जो सच्चाई है उसे मैं यहां रखना चाहता हूं।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

02-03-2022/1300/एच.के.-ए.जी. /1

श्री होशयार सिंह ..... जारी

रेलवे विभाग का कोई भी जे.ई., एस.डी.ओ. या अन्य अधिकारी हमारे अधिकारियों से बात नहीं करता है। वह बोलता है कि डी.एम. फिरोजपुर में बात करो या बड़े अधिकारियों से बात करो और वह हमारे किसी भी अधिकारी से बात नहीं करेगा। उनके कानून ही अलग हैं और मेरी इस बात को आप ध्यान में रखना क्योंकि कल को पछताना न पड़े। आज मैंने यहां

पर उन्हीं बातों को रखा है जिसका मुझे स्वयं अनुभव हुआ और रेलवे लाइन बनने के समय इन बातों का पूरा ध्यान रखा जाए। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : धन्यवाद जी। इस चर्चा का उत्तर माननीय उद्योग मंत्री जी दोपहर के भोजन अवकाश के उपरांत देंगे। अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए अपराह्न 02:00 बजे तक स्थगित की जाती है।

02.03.2022/1405/JK/YK/1

(दोपहर के भोजनोपरान्त माननीय सदन की बैठक अपराह्न 14.05 बजे पुनः आरम्भ हुई)

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर।

अध्यक्षः माननीय वन मंत्री जी, आप क्या बोलना चाहते हैं?

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो यहां पर भाषण दिए जा रहे थे, उसमें श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने कहा कि सड़कों की अप्रूवल नहीं हो रही है। मण्डी-पठानकोट फोरलेन का काम शुरू नहीं हो रहा है।, मंत्री जी फाइलें नहीं निकालते हैं, वे पता नहीं क्या चाहते हैं, वे क्या ढूंढ रहे हैं ? पता नहीं अभी वे क्यों यहां नहीं बैठे हैं अभी तो नूरपुर बाई पास का काम भी लगा हुआ है। मण्डी-पठानकोट के नेशनल हाइवे की फाइल अप्रूव हुए तीन महीने हो गए हैं। वहां पर आजकल फुल स्ट्रीम में काम चला हुआ है। रही बात मटौर-शिमला हाइवे-88 की, उसकी अप्रूवल हमारे से गए हुए दो महीने हो गए हैं। उनके रीजनल ऑफिस की कोई इन्क्वायरी लगी हुई है which is being attended by the Regional Office and the National Highways. My Department has nothing to do in it. सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी, आइए,आपका स्वागत है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हाउस में कुछ बोलें, यह कोई रामलीला का मैदान नहीं है। यह हिमाचल प्रदेश का माननीय सदन है। यहां पर जब

भी आप कुछ बोलते हैं तो पढ़ कर बोलें। आप बिना पढ़े मत बोला करें। ...(व्यवधान)... पहले आप मुझे सुन लो। आप तो प्वाइंट ऑफ ऑर्डर पहले ही करने लग पड़े। मैं अपने साथ डेट्स लाया हूं जब-जब हमारे रोड्ज़ की अप्रूवल हुई है। हमारे ऑफिस में कोई फाइल पैंडिंग नहीं है। मंत्री क्या ढूंढता है? आप अपनी भाषा को कंट्रोल करके बोलना सीखिए।। also know how to speak in the same language कि मंत्री क्या ढूंढता है? आप क्या ढूंढ रहे हैं, उसका मुझे भी पता है। This is not the Congress Party, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप मेरी बात समझे। जिस तरीके की असभ्य भाषा में आपने मिनिस्टर को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया this is not fair. I will not tolerate this. मैं यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ...व्यवधान... आप फिर बोलने लग पड़े।

02.03.2022/1405/JK/YK/2

...व्यवधान... आपकी तसल्ली नहीं हुई। ...व्यवधान... अध्यक्ष महोदय, I take a very strong notice of this. मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि and I want your permission to file a privilege against Sh. Sukhvinder Singh Sukhuji who tried to mislead the House. ...व्यवधान... मैं तो अपनी बात अध्यक्ष महोदय के पास रख रहा हूं। श्री जगत सिंह नेगी जी, मैंने आपसे राय नहीं मांगी है। You have no right to speak anything that comes in your mouth. आपके पास यह राइट नहीं है कि आप जो मर्ज़ी झूठ बोलते रहें। ...व्यवधान... यह तो मैं आपके ऊपर लागू कर सकता हूं। Sh. Jagat Singh Negiji, this goes for you, यह आपके ऊपर जाता है। अध्यक्ष महोदय, I take a strong exception to the language which he used.

अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, बैठिए। श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी बोलिए।

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खुः माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बड़े हाइपर हैं। आप प्रिविलेज़ तो क्या किसी भी कोर्ट में चले जाएंगे, हम वहां पर भी लड़ेंगे। आप पिछली बार

का इनका भाषण सुनिए। ...व्यवधान...ये तू-तड़ाक के सिवाय कभी भी बात नहीं करते। ...व्यवधान...शिमला-मटौर की फाइल...व्यवधान...

श्री एस.एस. द्वारा जारी------

02.03.2022/1410/SS-YK/1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु क्रमागत :

देखिए, पीड़ा होती है। मैं मानता हूं कि मंत्री जी को बोला है, पीड़ा होती है। अब सच की पीड़ा सुन लीजिए। झूठ के लिए भी यह हाउस है और कोर्ट भी है। मैं इस माननीय सदन के माध्यम से कह रहा हूं कि शिमला-मटौर और जोगिन्द्रनगर-पठानकोट की फाइल मंत्री जी यह बताइए कि आपके ऑफिस में कब आई और कितने दिन रुकी? अगर आप यह बात कह रहे हैं तो अभी भी मैं पूछ रहा हूं तथा आपके सामने कह रहा हूं कि गुस्सा मत कीजिए। ठीक है, आप सरकार के पार्ट हैं और मंत्री हैं, आप पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की गई है। सुनिए, हमने ये कहा कि जहां प्रदेश के विकास की फाइल रुकेगी तो विधान सभा के सभी सदस्यों का यह दायित्व बनता है कि वे उसे सदन के ध्यान में लाएं। मैं किसी प्रिवीलेज से डरने वाला नहीं हूं, ऐसे प्रिवीलेज और जितने मर्जी कोर्ट केस कर लीजिए। लेकिन मंत्री जी की भाषा देखिए। सदन की एक मर्यादा और गरिमा होती है। जिस पद पर आप बैठे हैं उसकी एक मर्यादा और गरिमा है। इनके भाषण सुनिए। अभी देखिए, ये कह रहे थे कि ये लाएगा, तूं लाएगा। यह कोई मोहल्ला नहीं है। एक लाख लोगों ने इनको भी चुनकर भेजा है और हमको भी चुनकर भेजा है। हम आपका आदर करते हैं, हम सबका आदर करते हैं। सदन की गरिमा बनाना हम सबका दायित्व है। अगर विक्रमादित्य जी पहली बार हैं तो क्या इनसे तूं-तड़ाक से बात करेंगे? मैं मंत्री जी का भाषण सुन रहा था तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। हमने तो सिर्फ फाइल की बात की है और आपको एक और चीज़ बता दें कि अगर इनको इतना ही शौक है तो हम तथ्यों के साथ अन्य बातें भी लाएंगे तथा उन्हें रखना हमारा दायित्व है। अध्यक्ष महोदय, आपने हमें उन्हें रखने का मौका भी दिया। अगर कुछ गलत

होगा तो इनके ध्यान में लाएंगे। इनको मैंने दो बार बोला कि आप विकास की फाइलों को क्यों रोक रहे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। हम कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। अगर आपको व्यक्तिगत लगा है कि हमने व्यक्तिगत बोला है तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम व्यक्तिगत नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो फाइल आपके पास रुकी है हमने सिर्फ उस मामले में बोला है, यही मैंने कहना था। धन्यवाद, जयहिन्द।

02.03.2022/1410/SS-YK/2

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथ कॉपी लाया हूं। जो प्रोसिजर है मैं इनको थोड़ा समझा दूं। हमारे से फाइल निकलकर रीजनल ऑफिस जाती है। रीजनल ऑफिस उसके ऊपर क्वैरीज लगाता है that I got nothing to do with my Office. यह जो शिमला-मटौर वाला मामला है उसके ऊपर रीजनल ऑफिस की जो क्वैरीज लगी हैं ...व्यवधान... मैं वे भी कागज़ साथ लाया हूं कि क्या-क्या क्वैरीज लगी हैं। Why it has been installed? जोगिन्द्रनगर-मंडी-पठानकोट वाली जो फाइल थी उसमें एक-डेढ़ महीना ज़रूर डिले हुई थी क्योंकि वहां पर रेट्स सैटल नहीं हो रहे थे और संघर्ष समिति के साथ मीटिंग्स चल रही थीं। संघर्ष समिति के साथ मीटिंग के बाद कुछ प्वाइंट्स ऐसे आ गए थे उदाहरणार्थ जैसे, A to B the rate was Rs. 1 Crore canal and B to C the rate was Rs. 18,000/- a canal which needed to be settled, which was settled and after month and half times it was moved. सुन लीजिए। आज के दिन में उस हाईवे का विधिवत रूप से काम लगा हुआ है। The work is on. यह जो मटौर वाली फाइल है इसके ऊपर जो क्वैरी है, I think that will also be settled in the day or two days time and the work will start in coming days**. I want to assure the House and you that in the work any file pending for the development of the State has never been stopped by me and it will never be stopped by me.** But the language used कि मंत्री क्या ढूंढ रहा है is objectionable and I object to it. Thank you.

अध्यक्ष : वैसे सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी, ये शब्द तो बड़े असंसदीय लग रहे हैं। मैं भी सुन रहा था और उस समय मंत्री जी यहां पर नहीं थे कि क्यों फाइल रोकी गई, मंत्री जी क्या ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये शब्द असंसदीय हैं। मैं इन शब्दों को देख लूंगा और एक्सपंज कर दूंगा। ठीक है, माननीय सदस्य, आपकी बात आ गई।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अगर मैंने कहा है कि मंत्री जी क्या ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऑब्जैक्शन ढूंढ रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये शब्द असंसदीय हैं तो इनको कार्यवाही से निकाल दीजिए।

02.03.2022/1410/SS-YK/3

अध्यक्ष : चलो अब छोड़ो, आपकी बात आ गई है।

अब माननीय उद्योग मंत्री जी, नियम-130 के अंतर्गत जो चर्चा हुई है उसका उत्तर देंगे।

जारी श्रीमती के0एस0

02.03.2022/1315/केएस/एजी/1

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नियम 130 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री सुभाष ठाकुर जी ने जो प्रस्ताव लाया है कि भानुपल्ली-बिलासपुर बेरी ब्रॉड गेज रेल लाइन परियोजना से जुड़ा कोई भी कार्यालय इस समय बिलासपुर में स्थापित नहीं है। इस परियोजना से जुड़े मसलों को हल करने के लिए कलेक्टर जिला बिलासपुर को बार-बार चंडीगढ़ जाना प़डता है जिससे जहाँ जिले के कार्य प्रभावित हो रहे हैं वहीं परियोजना से प्रभावित लोगों की कठिनाइयों को दूर करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। सरकार जनहित में इस बारे में आवश्यक निर्णय ले या वांछित नीति बनाएं ताकि इस परियोजना का कार्य लगभग 150 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ में स्थापित कार्यालय से नियंत्रित न होकर, नजदीक से इसकी देखरेख हो।छ

अध्यक्ष महोदय,

भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन परियोजना के लिए आर.वी.एन.एल. का कार्यालय बिलासपुर में व्यास सदन बिलासपुर नजदीक उपायुक्त कार्यालय में पहले से मौजूद है तो ये कहना गलत होगा कि जिला अधिकारी बार-बार चंडीगढ़ में आर.वी.एन.एल. कार्यालय जाते हैं जबकि जिला कर्मचारियों को कभी-कभार ही आर.वी.एन.एल. के कार्यालय चंडीगढ़ जाना प़डता है। वर्तमान में, परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जिला राजस्व विभाग द्वारा निपटाई जा रही है। जिसे प्रधान सचिव (परिवहन) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समन्वित किया जा रहा है।

इस कार्य के निष्पादन हेतु वर्तमान में भू-अर्जन अधिकारी (रेलवे), बिलासपुर के कार्यालय में कार्यरत्त अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा
02.03.2022/1315/केएस/एजी/2

निम्न हैः-

क्र0स0	**पदनाम**	**स्वीकृत पद**	**भरे हुए पद**	**रिक्त पद**
1	भू-अर्जन अधिकारी	1	1	--
2	नायब तहसीलदार	1	-	1
3	कानूनगो	2	3	नायब तहसीलदार के उपरोक्त पद के विरूद्ध एक अतिरिक्त कानूनगो कार्यरत है
4	पटवारी	5	5	-

5	वरिष्ठ सहायक	1	1	-
6	लिपिक/ कम्पयूटर ऑपरेटर	1	1	-
7	सेवादार	2	2	-
8	चेनमेन	10	2	आवश्यकता के अनुसार केवल 2 ही चेनमेन कार्यरत्त हैं।

02.03.2022/1315/केएस/एजी/3

इसके अतिरिक्त रेल विकास निगम लिमिटेड बिलासपुर के कार्यालय में रेल विकास निगम द्वारा नियुक्त अधिकारियों का ब्यौरा निम्न हैः-

1. श्री अनुराग रत्न, एस.एस.ई.
2. श्री सन्तोश कुमार, एस.एस.ई.
3. श्री विकास, एस.ई.

इसके अतिरिक्त प्रदेश में जहां पर रेल निर्माण के कार्य चल रहें हैं, में क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत्त है।

भानुपल्ली-बिलासपुर बेरी रेल लाइन (63.1 किलोमीटर लम्बाई) की लागत में 75 प्रतिशत भारत सरकार तथा 25 प्रतिशत प्रदेश सरकार वहन करेगी परन्तु यदि भूमि की लागत मु0 70 करो़ड रुपये से अधिक होगी तो उसे भी राज्य सरकार द्वारा वहन करना होगा। दिनांक 20.02.2022 तक भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेल लाइन के लिए कुल मु0 2738.05 करो़ड रुपये की राशि जारी की जा चुकी है, जिसमें मु0 2247.95 करोड़ रुपये रेलवे द्वारा तथा मु0 490.10 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 में भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के लिए मु0 1868 करो़ड रुपये आबंटित किये हैं।

<u>भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन भूमि अधिग्रहण की स्थिति</u>

- कि.मी. 0 से कि.मी. 20 तक पूरी जमीन का कब्जा आर.वी.एन.एल. को सौंप दिया गया है।

- कि.मी. 20 से कि.मी. 52 तक कुल 82.887 हेक्टेयर निजी भूमि में से बातचीत से 39.177 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण 7 गांवों में किया गया है। 23 गांवों में 43.71 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन की रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ समूह की सिफारिश और भूमि अधिग्रहण की सिफारिश करने के लिए अधिनियम की धारा 8(2) के अंतर्गत सरकार द्वारा दिनांक 02/02/2022 को अधिसूचना जारी की गई है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा दिनांक 19/02/2022 को इस भूमि के अधिग्रहण के लिए धारा 11 (1) के तहत भी अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

- श्रीमती अ0व0 द्वरा जारी..

02.03.2022/1420/av/ag/1

उद्योग मंत्री---------- **जारी**

इस भूमि के अधिग्रहण के लिए धारा 11 के तहत भी अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 86.03 हैक्टेयर सरकारी भूमि का कब्जा आर0बी0एन0एल0 को सौंप दिया गया है।

किमी 52 से कि0मी0 63 तक सरकार द्वारा दिनांक 31/1/2022 को 10 गांवों में 40.54 हैक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु एस.आई.ए. के अध्ययन करने की अधिसूचना जारी की गई है और अध्ययन शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त एफ.सी.ए. के तहत 12 हैक्टेयर सरकारी भूमि के डायवर्शन का प्रस्ताव नोडल अधिकारी को दिनांक 31-02-2022 को प्रस्तुत किया गया है। वैसे तो माननीय सदस्य ने अपने प्रस्ताव में केवल यह कहा है कि दफ्तर को बिलासपुर शिफ्ट किया जाए परंतु कुछ बातें बीच में ऐसी थीं जिनका मैंने यहां पर ब्यौरा देना जरूरी समझा। 7 सुरंगों और 36 पुलों का निर्माण शुरू हो गया है और कार्य प्रगति पर है तथा 3 सुरंगों के निर्माण का काम नवंबर, 2021 में आबंटित किया गया है। मैं

माननीय सदस्य के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा प्रगति पोर्टल पर इस रेल लाइन के जमीन के अधिग्रहण की प्रगति रिपोर्ट भी ली जाती है। इसके आर0बी0एन0एल0 का हैड ऑफिस चंडीगढ़ में है और ब्रांच ऑफिस बिलासपुर में है। प्रोजैक्ट ऑफिस प्रोजैक्ट साइट्स के ऊपर हैं। पहली प्रोजैक्ट साइट डब्ट में, दूसरी धरोट तथा तीसरी प्रोजैक्ट साइट लखाला में है। इन्होंने यहां यह भी कहा कि उपायुक्त द्वारा चंडीगढ़ का दौरा करने की वजह से वहां का कार्य प्रभावित होता है तो मेरी सूचना के अनुसार वर्ष 2021 और 2022 में आपके उपायुक्त, बिलासपुर को केवल दो बार चंडीगढ़ जाना पड़ा है। एक बार उनको दिनांक 28.8.2021 और दूसरी बार 3.2.2022 को जाना पड़ा है। भारत के संविधान के अनुसार रेलवे केन्द्रीय सरकार का विषय है जिस विषय पर कोई कानून अथवा नीति बनाया जाना केवल केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। यद्यपि केन्द्रीय सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में राज्यों की सरकारों के परामर्श एवं प्राथमिकताओं को अधिमान दिया जाता है।

02.03.2022/1420/av/ag/2

इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपने इस प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुकम्पा करें। आपके मन के अंदर जो शंकाएं थीं मैंने उनके बारे में भी जानकारी देने की कोशिश की है। वहां पर जिस तरीके से काम होना चाहिए और वहां पर जिन-जिन एजैंसीज की हर समय मौजूदगी चाहिए; वह मुझे लगता है कि बिलासपुर में है। यह मसला सीधे तौर पर केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है और यदि इसमें सैद्धांतिक रूप से कोई बदलाव लाना होगा तो वह वहीं से हो सकता है। लेकिन मुझे मेरे विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि वहां काम में किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है। वहां पर जिस प्रकार से दफ्तर और स्टाफ की जरूरत है; वह वहां पर सारे-का-सारा मौजूद है। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें क्या कोई स्पष्टीकरण है? इसमें कोई मतदान नहीं होता तो इसको वापिस लेना या लेने के बारे में कुछ नहीं पूछा जाता। अगर स्पष्टीकरण है तो आप बोल सकते हैं।

श्री सुभाष ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर के लोग भी चाहते हैं और हिमाचल के लोग भी चाहते हैं कि यह रेलवे लाइन आनी चाहिए। लेकिन हम इस संदर्भ में यही जोड़ना चाहते थे कि इनका हैड ऑफिस चंडीगढ़ में है और लोगों को उनसे अपनी समस्याओं के संदर्भ में बातचीत करने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता है। चंडीगढ़ का ऑफिस केवल इसी रेलवे लाइन परियोजना के लिए खोला गया है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री जी ने बड़े विस्तार से उत्तर दे दिया है और इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। मंत्री जी के उत्तर के साथ ही यह चर्चा समाप्त होती है। ...व्यवधान... आप पहले ही अपनी बात विस्तार से रख चुके हैं। इस पर दोबारा बोलने का कोई प्रावधान नहीं है। ...व्यवधान... चलो, आप बोलिए।

टी सी द्वारा जारी

02/03/2022/1425/टी0सी0वी0/ए0एस0/1

श्री सुभाष ठाकुर : मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग चंडीगढ़ में बैठे हैं, वे अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत हार्डशिप अलाउंस ले रहे हैं। यह भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेलवे लाइन का हैड ऑफिस है। लेकिन जो बिलासपुर का ऑफिस है, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। वहां सभी रिटायर्ड लोग बैठते हैं। जब यह ऑफिस इसी रेलवे लाइन के लिए है तो यह बिलासपुर में होना चाहिए था। जो लोग बिल्कुल भूमिहीन हो रहे हैं, जिनका मकान भी जा रहा है और जिनका हिमाचली प्रमाण-पत्र तक नहीं बनेगा उनकी सुविधा के लिए यह विषय प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार के साथ उठाना चाहिए। मैंने भी उनके साथ पत्राचार किया है लेकिन उसमें उन्होंने बटिंडा को भी जोड़ दिया है ताकि उनको यह ऑफिस चण्डीगढ़ से बिलासपुर न ले जाना पड़े।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही बता दिया है कि यह केन्द्रीय सरकार का मसला है। अगर केन्द्र में कोई विषय लेकर जाना है और वहां किसी के साथ कोई बात रखनी है तो मैं इनके साथ जाने के लिए तैयार हूं। हम वहां जाएंगे और इस विषय पर अपना पक्ष रखेंगे।

02/03/2022/1425/टी0सी0वी0/ए0एस0/2

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी क्या कोई विशेष बात है? ठीक है, आप बोलिए।

श्री जगत सिंह नेगी : अध्यक्ष महोदय, हमने नियम-130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव यहां पर चर्चा हेतु दिया है उसमें हम 3-4 लोगों का नाम है। इस प्रस्ताव का मूल टैक्स्ट था "The House may discuss the irregularities in the implementation of Smart City Project in Shimla city" और इसको बदल कर"शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत हो रहे विकासात्मक कार्यों पर यह सदन विचार करे" कर दिया है। हम इसमें हुई अनियमितताओं के बारे में बात करना चाह रहे हैं और आप कर रहे हैं विकास की बात। हम गरीबी की रेखा की बात कर रहे हैं लेकिन आप रेखा की गरीबी के बारे में बात कर रहे हैं। यह कैसे संभव है। यह हमारे साथ बेइंसाफी है और नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह मंत्री जी ने ही करवाया होगा। हमने विकास की बात नहीं करनी है। आपने उसमें जो धांधलियां की हैं, हमें उस पर चर्चा करनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और हमने जो मूल प्रस्ताव दिया है, उसी को इसमें चलने दिया जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यदि विकास में कोई कमी है तो आप उनको बता दें और मंत्री जी उसका उत्तर दे देंगे।

श्री जगत सिंह नेगी : अध्यक्ष महोदय, हम विकास की बात नहीं कर रहे हैं उसमें जो अनियमितताएं हुईं हैं, उनकी बात कर रहे हैं। इनकी मंशा ठीक नहीं है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है। प्रस्ताव को किसने चेंज किया है, उसकी जिम्मेवारी फिक्स की जाएं। हमें आपका संरक्षण चाहिए। हमने प्रस्ताव आपके पास भेजा है और हम आप पर बहुत विश्वास करते हैं। प्रस्ताव को कौन चेंज कर रहा है, यह गौर करने का विषय है।

अध्यक्ष : आपका यह जो विश्वास है, यह बना रहेगा। आप चिंता न करें। मुझे यह लगता है कि हमारे सचिवालय की मंशा बिल्कुल सही है। माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी ने

जो बात कही है, यदि जो विकास हुआ है, उसमें आपको कुछ सुझाव देने हैं या चर्चा करनी है तो आप उन बातों को मंत्री जी को बता सकते हैं। इसलिए इस सचिवालय और इस कुर्सी की मंशा सही है। माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी आपको हमारा पूरा संरक्षण है।

एन0एस0 द्वारा .... जारी

02-03-2022/1430/NS/AS/1

श्री जगत सिंह नेगी : अध्यक्ष महोदय, इससे मूल भावना खत्म हो जाती है। गरीबी रेखा की हम बात कर रहे हैं आप यहां पर रेखा की गरीबी की बात ला रहे हैं।

अध्यक्ष : नेगी जी, आप तो चर्चा कर ही लेते हैं। ...व्यवधान... बैठिए। नेगी जी, मेरे साथ प्यार से ही बात करते हैं।

02-03-2022/1430/NS/AS/2

नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब श्री विक्रमादित्य सिंह जी नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इसी विषय पर सर्व श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, श्री जगत सिंह नेगी, श्री संजय अवस्थी और श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी से भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और ये सभी माननीय सदस्य चर्चा में भाग ले सकते हैं। अब श्री विक्रमादित्य सिंह जी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री विक्रमादित्य सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि "शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत हो रहे विकासात्मक कार्यों पर यह सदन विचार करे।"

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत हो रहे विकासात्मक कार्यों पर यह सदन विचार करे।" श्री विक्रमादित्य सिंह जी अब इस पर आगे चर्चा करें।

श्री विक्रमादित्य सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज नियम-130 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी से जुड़ा हुआ है और उस मसले पर बोलने के लिए हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं। पहली बात हमारे वरिष्ठ विधायक श्री जगत सिंह नेगी जी ने कही और उस बात को मैं भी दोहराना चाहूंगा क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले मुख्य मंत्री जी ने हाउस को संबोधित किया। इस सदन में हिमाचल प्रदेश की गरिमा के बारे में कहा गया,

इसकी पवित्रता और उच्च सिंद्धांतों के बारे बात की गई and on the contrary जिस विषय को हम मूल विचार के लिए लाना चाह रहे हैं, सरकार उसको टविस्ट करके या बदल करके पेश करने की कोशिश कर रही है तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विरूद्ध है तथा हम इसका विरोध और आलोचना करते हैं। सरकार, मंत्री और मंत्रालय केवल दो-तीन शब्द के पीछे छुपने का प्रयास तथा अपनी नकारात्मकता को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं this is not going to go a long way in hiding your inefficiencies and the failure of this Smart City project in Himachal Pradesh. जहां तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात है तो मैं, अध्यक्ष महोदय शुरूआत से ही शुरू करना चाहूंगा। वर्ष 2015 में देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट शुरू किया उसमें पहले धर्मशाला को लाया गया और उसके बाद शिमला शहर को भी स्मार्ट सिटी से जोड़ा गया। इसका मैं स्वागत करता हूं क्योंकि यह निश्चित तौर से प्रदेश की राजधानी है और यहां पर बहुत से इंपेडिमैंट्स थे, चाहे वे ट्रांसपोर्ट, पार्किंग और सीवेज़ तथा स्मार्ट मूवेलिटी से

02-03-2022/1430/NS/AS/3

रिलेटिड थे, it was a welcome step and we believe कि कोई अच्छा कार्य सरकार करने की कोशिश कर रही है तो हम विपक्ष में रहते हुए भी उसमें समर्थन देने का प्रयास करते हैं। मगर आज मुझे दु:ख है कि जो यह तथाकथित लगभग 2905 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट शिमला के लिए अप्रूव करवाया गया। इसमें हम जानते हैं कि शिमला में तकरीबन

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी

02.03.2022/1435/RKS/DC-1

श्री विक्रमादित्य सिंह ...जारी

20 से 25 लाख फ्लोटिंग पोपूलेशन यानी जो टूरिस्ट का आना-जाना है उससे भी प्रदेश की राजधानी को काफी भार पड़ रहा है। इनको मद्देनज़र रखते हुए यह प्रोजैक्ट शिमला शहर के लिए लाया गया।

(माननीय सभापति, श्री नरेन्द्र ठाकुर पदासीन हुए।)

मैं वर्ष 2017 की एन.जी.टी. की जजमैंट को कोट करना चाहूंगा which was taken into consideration after the so called faulty implementation of this project. I would like to quote: 'Shimla Smart City is nothing but building castles in the air'. इसमें जिस तरह से इसके बारे में बातें की गई और जो ग्राउंड लैवल पर इम्प्लिमेंटेशन है, उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क देखने को मिलता है। Primarily जब यह प्रोजैक्टल लाया गया तो इसमें 53 प्रोजैक्ट्स एनविसेज किए गए। यह कहा गया कि वर्ष 2022 के अंत में इन प्रोजैक्ट्स का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। We must not forget that this Project is a time bound project. समय बीतता जा रहा है और अगर हम इन प्राजैक्ट्स का कार्य वर्ष 2022 के अंत तक पूर्ण नहीं कर पाए तो पैसा लैप्स होना शुरू हो जाएगा। हर चीज़ में सरकार की ओर से यह हवाला दिया जाता है कि एन.जी.टी. या फोरेस्ट क्लीयरैंस नहीं हो पा रही है। इसके बारे में सदन में चर्चा हुई है कि there is no seriousness to take up this matter either with the Hon'ble Supreme Court or with the Hon'ble High Court, चाहे वह एन.जी.टी. का मसला हो लेकिन आप जानते हैं कि यह मसला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। एफ.सी.ए. के केसिज अलग-अलग प्लैटफॉर्म में फंसे हैं और इनकी क्लीयरैंस लेने के लिए सरकार को जिस गंभीरता से कार्य करना चाहिए था, वह नहीं हो पा रहा है। केवल यह कहना कि प्रोजैक्ट्स स्थापित हो चुके हैं, इस सदन की आंखों में पट्टी बांधने की बात है। जैसा मैंने कहा कि these 53 projects were categorized as high priority, medium priority and low priority. इसमें मेरी लिमिटिड अंडरस्टेंडिंग हो सकती है। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उसके अनुसार इन प्रोजैक्ट्स को दो

02.03.2022/1435/RKS/DC-2

भागों में बांटा गया है। एक एरिया बेस्ड डवैलपमेंट प्रोग्राम है और दूसरा एस.सी.पी. यानी जो पूरे एरिया को देखता है। मैं इसे faulty implementation क्यों कह रहा हूं? Why it is a castle in the air ? हमारी सरकार के समय जो JNURM का प्रोजैक्ट लाया गया था उसमें 90:10 फंडिंग हुआ करती थी। इस प्रोजैक्ट की फंडिंग 50: 50 में की जा रही है। आज प्रदेश सरकार और नगर निगम, शिमला की खस्ताहाल है। स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट में जितने

भी यूजर फी हैं उसमें यह इनविज़न किया गया है कि यूजर फी को यहां के लोग वहन करेंगे, which I don't think is practical at all. न तो प्रदेश सरकार 50 प्रतिशत की फंडिंग करवा सकती है और न ही नगर निगम, शिमला। इसके लिए कहां से पैसा आएगा, अब तक कितना पैसा आया है, 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी में प्रदेश सरकार और नगर निगम, शिमला ने कितना पैसा दिया है,उसके बारे में सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। दूसरा, कितना हाई कैटेगराइजेशन में है, कितना लॉ और मीडियम कैटेगराइजेशन में है with the NGT ban, which prevents any new construction in the core area of Shimla. जो कोर एरिया में बैन लगा हुआ है। The old town which compromises one third of the composite Shimla Municipality. इसमें शिमला शहर का एक तिहाई हिस्सा है जिसे रिव्यू करने के लिए यह सरकार पूरी तरह विफल हुई है। दूसरी री-बिल्डिंग की बात है। जैसे लोअर बाजार, मिडिल बाजार और कृष्णा नगर है, which happens to be the biggest slum in Shimla. आपने कहा कि हम इनको री-डिवैलप करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि ये क्षेत्र कोर एरिया में आते हैं और यहां कोई काम नहीं हो रहा है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि Shimla happens to be in seismic fore of the earthquake prone areas.

श्री बी.एस.द्वारा.. जारी

02.03.2022/1440/बी.एस./डी0सी0/-1

श्री विक्रमादित्य सिंह जारी...

अर्थक्विक प्रोन एरिया है। हमें इस पर संवेदनशीलता से भी काम करना है। उस बारे में भी सरकार को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। अब बात रहती है, इंवेस्टर्ज की, जब एन0जी0टी0 का बैन लगा है, मैं चाहूंगा कि जितने बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स की यहां पर बात की जा रही है, चाहे टूटीकण्डी से रोपवे की बात है, इसका कौन सा पी0पी0पी0 मोड पर कार्य हो रहा है? कितने इंवेस्टर्ज ने इसमें अपनी अच्छा जाहिर की है? ये जो बाधा एन0जी0टी0 की है, इसके बाद कितने लोगों ने इसमें विद्ड्रा किया है। इस बारे में भी सरकार स्थिति स्पष्ट करे। यह सबसे बड़ा प्रोजैक्ट शिमला शहर के लिए है। अगर इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है तो यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। दूसरा , the funding of oversize project of Rs. 300 crores is not viable and the State Government is constantly struggling

to cope with the financial crisis. अब इसमें इनके ही एक फोर्मर एडवाइजर है, मैं यहां पर उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, this is what he has stated. जो स्मार्ट सिटी के लिए बोझ है, उसे आप यूजर के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो ठीक बात नहीं है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में the Centre is committed to provide Rs. 500 crores with the State, having required to raise the balance amount, it has released only Rs. 64 crores. यह मैं केवल वर्ष 2019-20 की बात कर रहा हूं। जिसमें 500 करोड़ रुपए में से केवल 60 करोड़ रुपए अभी तक इस वित्तीय वर्ष में दिया गया है। This gives Municipal Corporation a corpus of only hundred crores to get the project started. जैसा मैंने कहा कि 65 हजार करोड़ रुपए का ऋण है तो कहां से यह पैसा आएगा, क्यों यह पैसा आएगा? यह ख्याली पुलाव नहीं बनाया जा रहा है तो और क्या है? इस चीज को लाने के लिए हमने सदन में प्रयास किया है। Special Purpose Vehicle, हालांकि यह मैंडिड में आया है कि Special Purpose Vehicle बनाया जाना चाहिए। मगर कहीं-न-कहीं मेरा यह मानना है कि हमारे जो इलेक्टिड कौंसिल्ज हैं और जो हमारी नगर निगम की पावर्ज हैं, हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनकी आवाज को Special Purpose Vehicle दवाने की कोशिश कर रहा है because it is the responsibility and accountability of the elected people to deliver projects in a stipulated time frame. एस0पी0वी0 में जो लोग आए हैं, इनमें उसका क्या योगदान है,

02.03.2022/1440/बी.एस./डी0सी0/-2

क्या इसमें इनकी जवाबदेही है, this also has to be taken into consideration. On 5th January,2021 the Smart City Mission has dropped projects worth Rs. 300 crores from its list. The funding coming down from Rs. 1000 crores to Rs. 700 crores. यह पिछले साल 05 जनवरी की मैं बात कर रहा हूं। परंतु इसकी जो डैड लाइन है वह जून, 2023 तक है अगर उस समय तक आपको फोरेस्ट कलीयरेंस नहीं मिली, तो आपके ये प्रोजैक्ट्स लैप्स हो जाएंगे। आपके शिमला जल प्रबन्धन लिमिटिड से फडिंग होती थी, वह भी अब बाहर हो चुकी है। दूसरा Ridge restoration की बात कहूंगा। रिज के बारे में आप जानते हैं कि it is a historical place. यह एक ऐसी जगह जिसकी अंग्रेजों के काल से ही मान्यता है और इसका स्टेटस पूरे प्रदेश और देश में है, सारा पर्यटक जो आता है, वह रिज के ऊपर घूमने जाता है और रिज का एक हिस्सा धंसता जा रहा है, यह गेयटी

थियेटर के साथ वाला एरिया है। इसमें पहले आपने 15 करोड़ रुपए का restoration के लिए प्रपोजल रखा था और बाद में जब आई0आई0टी0 रुड़की की टीम यहां पर आई, तो यह price escalation हो करके 27 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। उसे भी आपको ultimately shelf करना पड़ा। क्योंकि आपके पास इसे पूरा करने के लिए पैसा नहीं था। जैसा मैंने कहा कि फोरेस्ट की कलीयरेंस का मामला इसमें फिर से आ जाएगा।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

02-03-2022/1445/एच.के.-ए.जी. /1

श्री विक्रमादित्य सिंह..... जारी

तो इसे भी गम्भीरता से लेना चाहिए। शिमला शहर के सबसे बड़े प्रोजैक्ट को गम्भीरता से करने में सरकार नाकाम हुई है। जो सरकार अपने नगर निगम का कार्यालय ही न बना पा रही हो या उसके लिए फंडिंग न करवा पा रही हो तो अन्य चीजों के लिए फंडिंग हेतु उसकी गम्भीरता को हम कैसे समझ सकते हैं? जब हमारी सरकार प्रदेश में थी तब हमने विश्व बैंक से पैसा लेकर नगर निगम के erstwhile office को रिस्टोर करवाया था। तब हमने उस पर लगभग 8-10 करोड़ रुपये खर्च किए थे। उसके बाद नगर निगम का जो अपना कार्यालय बनना चाहिए था आज उसका क्या हाल है? आज नगर निगम की बैठक डी.सी. ऑफिस के बचत भवन में आयोजित होती है क्योंकि निगम के पार्षदों के पास बैठने के लिए कोई भी उचित स्थान नहीं है। नगर निगम का कमीशनर भी आज धक्के खा रहा है और वह कभी कहीं बैठता है तो कभी कहीं। सरकार से अभी तक नगर निगम का कार्यालय नहीं बन रहा है। इसके लिए जो पैसा envisage किया गया था वह नहीं हुआ है। नगर निगम के भवन के लिए एन.जी.टी. का अप्रूवल होना था वह भी नहीं हुआ। इसके अलावा कार्ट रोड से Bantony Castle तक जो लिफ्ट बननी थी उसमें भी कुछ नहीं हुआ। Bantony Castle के इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूं कि यह कब अप्रूव हुआ लेकिन हमारे समय में उसकी acquisition हुई थी और the idea behind was that there should be a place in Shimla जहां पर recreational activities हो सके। जहां पर हमारे टूरिस्ट्स के लिए कोई साउंड शो हो सके, उनके लिए कोई रीडिंग हो सके या recreational activities के लिए कोई जगह हो और इसके लिए 30 करोड़ रुपये लागत से

Bantony Castle को हमारी सरकार के समय एक्वायर किया गया था। उसमें कार्ट रोड से ऊपर एक लिफ्ट बननी थी जो अभी तक shelve हो चुकी है। उसके लिए 5 करोड़ रुपये का allocation किया गया था और वह भी अभी तक नहीं हुआ। इसके अलावा सैक्टर-3 में न्यू शिमला से टूटीकंडी बस स्टैंड तक एक बाईपास envisage किया गया था। वह भी इसकी वजह से shelve हो गया। मैं पार्किंग की बात करना चाहता हूं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शिमला की जनसंख्या 2.5 से 3 लाख के बीच है और बहुत फ्लोटिंग जनसंख्या है।

02-03-2022/1445/एच.के.-ए.जी. /2

सरकार कहती है कि 2,000 गाड़ियों के लिए, 32 करोड़ रुपये का एक आई.जी.एम.सी. में व उसके नीचे 15 करोड़ रुपये का और एक विकास नगर में 13 करोड़ रुपये की लागत से पार्किंग बनाने का प्रपोज़ल रखा है। इन सबके लिए भी अभी तक जमीनी स्तर पर कोई कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। जिस गम्भीरता के साथ इस विषय पर कार्य होना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है और सरकार को और अधिक गम्भीरता से इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और मैं उसे दोहरा रहा हूं कि यदि हम इस स्मार्ट सिटी को फैडरल तरीके से देखें या constitutional provision or constitutional mandate से देखें तो it is nothing but a unconstitutional body. Because the schemes of things that we have मैं फिर से इस बात को repeat इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ultimately accountability या responsibility तो that is of the Municipal Corporation of the City and it is not only about Shimla. जहां पर भी यह इम्पलीमेंट किया जाता है, हिमाचल प्रदेश में तो केवल धर्मशाला और शिमला में ही है but you cannot outsource completely your responsibilities to some company. जहां पर आपका एक सी.ई.ओ. है और जहां पर उनकी कोई accountability नहीं है। बेशक उसमें सरकार के अधिकारी हैं but they are not directly accountable to the people of the State or the people of their wards. जैसा मैंने कहा कि इसकी एक पी.आई.एल. माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक में दायर की गई और उसमें इसी तर्क के ऊपर चैलेंज किया गया है। हमारे संविधान के 74वें संशोधन में हमने लिया है कि we should empower the people with the ward committees. लेकिन स्मार्ट सिटी में हम इससे दूसरे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि हम इसके ख़िलाफ हैं मगर इसमें जिस तरह की

accountability हमको एक सीमित समय में दिखनी चाहिए थी वह देखने को नहीं मिल रही है। जैसा मैंने कहा कि The Smart City like a company owned by the civic body plus State Government where it is outsourcing of its statutory functions. जैसा मैंने कहा कि by the 74th Amendment of the Constitution we sought more power in the hands of local people through the ward committees but with the Smart City the entire structure is being corporatized.

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

02.03.2022/1450/JK/HK/1

श्री विक्रमादित्य सिंहः-----जारी--------

यानि उसका वह हो रहा है। Non-participation और जो अकाउंटेबिलिटी है वह इसमें नहीं बन पा रही है। यहां पर एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जो शिमला के की-प्रोजैक्ट्स हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक तो lift an escalator at Lakkar Bazaar, दूसरा है, escalator to Jakhu top, तीसरा है, Smart City from Sanjauli to Shimla,जो आपका एक पाथ बनना था। चौथा है vending zone in Khalini, पांचवां है कृष्णा नगर से कॉम्बरमेयर नाला की वाइडनिंग और जो ढली एरिया है, उसके एरियाज़ की वाइडनिंग। इनमें से चार-पांच चीजें जो मैंने कही हैं इसमें मैं सरकार की ओर से ज़वाब चाहूंगा कि कितना काम इसमें हुआ है, कितना पैसा अभी तक इसमें केन्द्र सरकार की तरफ से , प्रदेश सरकार की तरफ से और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से दिया गया? जो स्मार्ट सिटी की डैड लाइन है, इसमें यदि हम उन प्रोजैक्ट्स को स्टैपुलेटिड टाइम में मीट नहीं करते हैं तो इसमें से कितने प्रोजैक्ट्स जबरन हमको ड्रॉप करने पड़ेंगे? सभापति महोदय, मैं इसमें ज्यादा कुछ न कहते हुए, जो फंडिंग हमारे समय में जे.एन.एन.यू.आर.एम. के माध्यम से 90:10 रेशो में हुआ करती थी, वह हमें इसमें देखने को मिल नहीं रही है। जैसे कि मैंने कहा कि संजौली से आई.जी.एम.सी. तक पैदल चलने वाला रास्ता है, उसको इतना हैवी बना दिया गया है, उसमें बहुत ज्यादा लोहा लगा दिया

गया है। जितने उसमें लोग चलने चाहिए थे और जिस परपज़ के लिए उसे बनाया गया था, वह परपज़ हल नहीं हो पा रहा है। एक्सलेरेटर आज तक एक नहीं लगा। एक भी रोप-वे शिमला के अन्दर नहीं लगा। नई डम्पिंग गारबेज साइट एक भी नहीं बनी। आप लोग जो दो-चार साल का ढिंढोरा पिटते हैं कि हमने स्मार्ट सिटी में ये कर दिया, वो कर दिया, मैं जानना चाहूंगा कि सरकार तथ्यों के आधार पर बताएं कि पिछले चार साल के कार्यकाल में जबसे यह स्मार्ट सिटी शिमला के अन्दर लांच हुई है, इसमें सरकार की ओर से और अर्बन मिनिस्टरी की ओर से कौन से कान्क्रीट कार्य किए गए हैं? I want to know from the Hon'ble Government. Thank you.

02.03.2022/1450/JK/HK/2

सभापतिः मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि बोलने वाले काफी हैं और समय का ध्यान रखें। अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खु जी भाग लेंगे।

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खु (नदौन)ः माननीय सभापति महोदय, हमारी पिछली कांग्रेस सरकार ने दो स्मार्ट सिटी केन्द्र सरकार से घोषित करवाई, जिसमें एक धर्मशाला और दूसरी शिमला थी। पिछले तीन सालों में तो उन स्मार्ट सिटीज़ में कोई कार्य नहीं हुआ। अच्छा हुआ हमारे शिमला के विधायक, श्री सुरेश भारद्वाज जी मंत्री बन गए तो कुछ कार्य स्पीड अप हुआ है। शिमला में रोड़ज की जरूरत थी। काफी तंग रोड़ थे। चाहे वह सर्कुलर रोड़ है, चाहे कोई अन्य रोड़ है, सब जगह कार्य हुआ है। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपके बनने के बाद यह कार्य थोड़ा अच्छा हुआ है। एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो कि सर्कुलर रोड़ में रिटेनिंग वॉल्ज़ लगाई हैं, उनका अगर आप रेट देखेंगे , ठीक है कई जगह टाइट रोड़ होते हैं, कई जगह रोड़ की पोजिशन अच्छी होती है, उसमें थोड़ा ज्यादा पैसा देना होता है क्योंकि उनका काम रात को होता है। लेकिन कई जगह जितनी भी रिटेनिंग व ब्रेस्ट वॉल्ज़ लगी हैं, वे एक हजार गुना ज्यादा पैसे से लगी है। मेरा आपसे यह अनुरोध रहेगा कि शिमला के आप विधायक हैं कम-से-कम इसकी इन्क्वायरी करवाई जाए कि स्मार्ट सिटी में जितनी भी रिटेनिंग वॉल्ज लगी हैं।

दूसरी बात शहर स्मार्ट हो, वहां पर क्या सुविधाएं हों, उन सुविधाओं के लिए कई सालों से शिमला में कार्य नहीं हुए हैं। अब स्मार्ट सिटी तो नाम दे दिया गया लेकिन शिमला तो पहले से ही स्मार्ट था। लेकिन जिस टैक्नोलॉजी का प्रयोग यहां पर होना चाहिए था उस टैक्नोलॉजी का प्रयोग यहां पर नहीं हुआ। यह ब्रिटिश काल से हमारी समर कैपिटल हुआ करती थी इसलिए यह शहर पहले से ही स्मार्ट था। इसमें फैसला हुआ था 90 परसेंट केन्द्र की ग्रांट होगी और 10 परसेंट स्टेट की ग्रांट होगी। 90:10 के हिसाब से अब 50:50 हो गया।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

02.03.2022/1455/SS-yk/1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु क्रमागत :

और 50 परसैंट होने बाद भी चाहे धर्मशाला की बात ले लीजिए, चाहे शिमला शहर की बात ले लीजिए, अभी कार्य में और तेजी लाने की ज़रूरत है। आपने धर्मशाला, जिसमें कार्य शुरू हुआ हो, वहां से आप इंटेग्रेटिड कंट्रोल सेंटर जो है उसको आप शिमला से होल्ड करना चाह रहे हैं। जो इंटेग्रेटिड कंट्रोल सेंटर है जिसमें सर्वेलैंस होगा, ट्रांसपोर्टेशन का पूरा ख्याल रखा जाएगा, स्ट्रीट लाइट कितने बजे जलेगी, कितने बजे बंद होगी, इस कंट्रोल सिस्टम में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। पूरा टेक्नोलॉजी बेसड होगा। अगर आप शिमला से धर्मशाला की स्मार्ट लाइट को बंद करने का प्रावधान रखेंगे तो वह ठीक नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो हमारे सी0सी0टी0वी0 कैमरे की जो फुटेज होगी वह शिमला से मंगवाएंगे जबकि एक्सीडेंट धर्मशाला में हुआ है। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि प्रत्येक स्मार्ट सिटी का अपना इंटेग्रेटिड कमांड कंट्रोल सेंटर है और जो आप धर्मशाला को भी शिमला से करने की कोशिश कर रहे हैं तो वह ठीक नहीं है। कृपा करके शिमला का इंटेग्रेटिड कमांड सेंटर अलग किया जाए और धर्मशाला का अलग किया जाए।

अब मैं दूसरी बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं क्योंकि अब काम शुरू हुआ है। स्मार्ट सिटी में जो आपकी डक्ट डलनी है चाहे वह पानी की पाइप डलनी है, चाहे आपकी अंडरग्राउंट बिजली की तार डलनी है या चाहे टेलीकॉम की तार डलनी है क्या आपने ऐसा प्रोविजन शिमला और धर्मशाला दोनों जगह किया है? रेन शैल्टर तो आप बना रहे हैं लेकिन वे भी बड़े कॉस्टली बन रहे हैं। इतना लोहा लगाया जा रहा है जैसे विक्रमादित्य जी ने ठीक कहा कि जो आपका स्नोडन से लेकर संजौली का बाईपास बना उसमें 25-30 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। इतना हैवी लोहा वहां लगाने की जरूरत नहीं थी। ट्रांसपेरेंट सीट्स भी लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है वह आप लगाते लेकिन इस पैसे की बर्बादी को रोकने का दायित्व भी आपका है। जो डक्ट लगनी है क्योंकि सर्दियों में चाहे शिमला या धर्मशाला है और ये दो ही हमारे

02.03.2022/1455/SS-yk/2

महत्वपूर्ण शहर हैं, सर्दियों में जो बिजली चली जाती है अभी भी बिजली का जो ओवरहैड कंडक्टर है; पानी की बड़ी-बड़ी पाइपें व पूरा रिज मैदान खोद देते हैं। तो कहां-कहां पर आपके डक्ट स्टोरेज रहेंगे जहां से आदमी जाकर उसे ठीक कर सकता है, कहां-कहां पर आपकी पानी की पाइपें जाएंगी और कहां-कहां पर आप इन चीज़ों का ओपन स्पेस रखेंगे, इन सब चीज़ों का स्मार्ट सिटी बनाते समय ध्यान रखना। स्मार्ट सिटी का मतलब पूरा स्मार्ट होना चाहिए। पूरा डिजीडाइजेशन से काम होना चाहिए। आपके जो इलैक्ट्रिकल टॉयलैट्स हैं वे भी बिल्कुल स्मार्ट होने चाहिएं। लेकिन कई जगह आपके टॉयलैट्स ऐसे हैं कि बिल्कुल गंदे हैं। आप लक्कड़ बाजार का टॉयलैट्स देख लीजिए और बस-स्टैंड कहां शिफ्ट करना है इन बातों को देखने का यह समय है। अभी तो आपने 40 साल बाद शिमला डवलपमैंट प्लान बनाया है, मैं आपकी स्टेटमैंट पढ़ रहा था यह अच्छी बात है। लेकिन शिमला डवलपमैंट प्लान में आपको परमिशन्ज़ मिलेंगी या नहीं। यह बात मैं इसलिए लाना चाहता हूं क्योंकि हमारा जो विल्ली पार्क है तकरीबन इसमें हमने एशियन डवलपमैंट बैंक का टूरिज्म से 80 या 90 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। आपकी टूटीकंडी के पास एक

बिल्डिंग बनाई, जिसमें कम-से-कम 110 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर पीटरहॉफ में एक भी कंस्ट्रक्शन करनी हो तो वहां आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। जो कंस्ट्रक्ट हो चुका है, रेस्ट हाउस तो चल रहा है, उसके नीचे होटल जो है उसको चलाने की परमिशन आपके पास नहीं है। आपने टूटीकंडी में जो पार्किंग बनाई, उसमें 100 करोड़ रुपया आपने खर्च किया, उसको चलाने की परमिशन आपके पास नहीं है। स्मार्ट सिटी में आप कैसे विकास करेंगे जब तक शिमला में एन0जी0टी0 ने स्टे ऑर्डर लगा रखे हैं। अगर आपने लद्दाखी महल्ले को भी स्मार्ट करना है जोकि आपके विधान सभा क्षेत्र का है, उसमें एक कोने से चलिए, चाहे शोघी से चलिए और ढली तक पहुंच जाइए तो सब जगह हॉरिजैंटल रूम्स में कंस्ट्रक्शन हुई है। वर्टिकल कंस्ट्रक्शन कहीं नहीं हुई है। अगर आप शिमला को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो हमें वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर लद्दाखी मुहल्ले में 500 परिवार हैं तो आप पांच टावर

02.03.2022/1455/SS-yk/3

बनाकर उन परिवारों को वहां घर दे सकते हैं। लेकिन बस-स्टैंड व लिफ्ट के नीचे से लेकर टूटीकंडी तक पूरा लद्दाखी मुहल्ला हो गया। पूरा स्लम एरिया बन चुका है और न ही किसी के नाम पर जगह है। सारी जगह सरकार की है। आपको कम-से-कम एन0जी0टी0 के जो स्टे ऑर्डर हैं उनके खिलाफ आगे कैसे हाई कोर्ट में लड़ना है या कोई कानून बनाकर हमने उसको रेगुलराइज करना है

जारी श्रीमती के0एस0

02.03.2022/1500/केएस/एजी/1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जारी----

किस तरह करेंगे क्योंकि शिमला में आपको वर्टिकल जाना पड़ेगा। 1903 में हिमाचल सचिवालय की बिल्डिंग बनी, सिसिल होटल बना। कोई भी स्टोरी ले लीजिए। 8-8 स्टोरी

वर्टिकल में बनी हुई हैं। यह शिमला में चार स्टोरी और ढाई स्टोरी का नया ही रिवाज़ आया है। आजादी से पहले की बात देखिए, हमारा स्टेटा हार्ड है। सचिवालय का भवन, रेलवे बोर्ड की बिल्डिंग और ए.जी. ऑफिर 8 मंजिला हैं। यह उस समय की बात थी जब टैक्नोलॉजी नहीं थी जबकि आज तो टैक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है। हाई कोर्ट की बिल्डिंग, जो कोर्ट हमें स्टे देता है, उसकी बिल्डिंग 11 मंजिल की बनी हुई है। शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आपको कानूनी रूप से एन.जी.टी. को हटाना पड़ेगा। शिमला में आप क्यों रोक लगा देते हैं? शिमला में आप 6 बिस्वे का प्लॉट देते हो। उसके बाद बोल देते हो कि आपको सिर्फ ढाई स्टोरी बनानी है। यह कोर एरिया है, यह ग्रीन एरिया है। जहां कोई पेड़ नहीं वह भी ग्रीन एरिया होता है और कोर एरिया क्या है? किसी बेचारे सरकारी कर्मचारी ने, आप उनको बोलिए कि अगर आपकी उस स्वॉयल की लोड बीयरिंग केपेसिटी अच्छी है और स्टेटा अच्छा है, हम आपको उस आधार पर अनुमति देंगे कि आपने कितनी स्टोनी बनानी है। कितने होटल बन गए जहां स्टेटा लूज़ है, वहां आप रोक दीजिए कि यहां स्टेटा लूज़ है, आपका साइट इंजीनियर जा कर उसको रोके। शहरी विकास मंत्री जी, मेरा यह मानना है कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, खासकर शिमला को जो कि स्मार्ट था, वह कुछ जगह स्लम के रूप में विकसित हो चुका है। चाहे स्मिट्री ले लीजिए। वहां डैड बॉडी निकालने के लिए भी एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर जाना पड़ता है। कभी भगवान न करें, भूकम्प आ गया तो आप खुद अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि सूरंग के साथ से ले कर निचले नेशनल हाईवे तक कितने घर बसे हुए हैं। तो यह समय है आपके पास, आपको मंत्रालय मिला हुआ है और आप मंत्रालय में अच्छा कर भी रहे हैं लेकिन और अच्छा करने की ज़रूरत है। इसमें

02.03.2022/1500/केएस/एजी/2

कानूनी रूप से भी लड़ने की जरूरत है। या तो आप दिल्ली की तरह एक एक्ट ले आएं। एन.जी.टी. को बाईपास करना है तो वही एक्ट लाइए कि हम स्टेटा देखकर, स्वॉयल देखकर पर्मिशन देंगे कि कितने मंजिल होगी। आप एन.जी.टी. को रहने दीजिए कि दो

स्टोरी होगी या ढाई स्टोरी है। यह कहां से रूल आया? आजादी से पहले के रूल आप देख लीजिए। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में ये बातें लाना चाह रहा था। इसके अलावा जो सीवरेज के नाले शिमला में हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकली जो नाले हैं, चाहे वह जाखू से शुरू होते हैं या ऊपर पहाड़ से शुरू होते हैं, पानी तो नीचे ही जाएगा। आपने देखा होगा कि नालों के पास बहुत ज्यादा इरोजन होता है। आप एक ही नाले की बात कर लीजिए जो छोटा शिमला, पोस्ट ऑफिस से नीचे बाईपास तक जाता है, नीचे फिर बाईपास के बाद आपने एक पार्क बना दिया। किसी पार्षद ने आपको बोला कि वहां पार्क बना दो, आपने बना दिया। उसके बाद वह नाला बंद हो गया और उधर सारा मलबा आ जाता है। हर बरसात में आएगा। उस नाले को, जो ट्रीटमैंट करना है, वह उसके एंड टू एंड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो बीच रास्ते में कहीं न कहीं वे इरोजन पैदा करते ही हैं। बरसात में शिमला में बहुत ज्यादा बारीश होती है तो इन नालों की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। लद्दाखी मोहल्ला जो स्लम बन चुका है, जहां तकरीबन 300 बीघा सरकार की जमीन पर लोगों ने घर बना रखे हैं, उसमें आप कोई नया काम करें। इस स्मार्ट सिटी के तहत उन गरीब आदमियों को भी अगर लद्दाखी मोहल्ले में मकान देना है तो कम से कम 5-7 टावर 50 बीघा में बनाकर ढाई सौ बीघा में ग्रीनरी लाएं तब शिमला शहर स्मार्ट होगा। अंडर ग्राउंड डक्टिंग अभी तक आपकी नहीं हुई है। हम पांच-पांच साल से बोल रहे हैं और जब हमारा नम्बर आता है, स्मार्ट सिटी में कि हमने कितना कार्य किया तो हम 87वें और 88वें नम्बर पर होते हैं। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि आपका शहर, जहां से आप विधायक भी हैं, इसको कांग्रेस पार्टी ने स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाया है और धर्मशाला

02.03.2022/1500/केएस/एजी/3

को भी कांग्रेस ने ही स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाया है। इसमें आपके आने से, ठीक है कि तीन साल आपकी सरकार सोयी रही, पहले वाले मंत्री जी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन आपने आकर थोड़ा रास्तों का ध्यान दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद

करते हैं लेकिन अभी उसको और स्मार्ट बनाना है। आपका विधान सभा क्षेत्र है और इसमें लेटैस्ट टैक्नोलॉजी आनी चाहिए। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। कॉर्पोरेशन के एरिये को आप अभी तक स्मार्ट नहीं कर सके। आपका पानी का बिल तो अभी ऑन लाइन आ रहा है लेकिन जो आपके नक्शे सबमिट होते हैं, वह सिर्फ यह है कि सबमिट करने हैं। वह कहां गया, किसको ऑब्जैक्शन है, वह अभी तक नहीं होते।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

02.03.2022/1505/av/ag/1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु---------- जारी

आपका जो कॉर्पोरेशन का सॉफ्टवेयर है उसका नाम भी अब 'कर परेशान' पड़ गया है यानी आपकी कॉर्पोरेशन केवल परेशान करने का काम कर रही है। आप उसमें भी थोड़ी टैक्नोलॉजी लाएं ताकि लोग जो नक्शे इत्यादि सब्मिट करना चाहते हैं उसमें उन्हें कोई दिक्कत न हो। मुझे उम्मीद है कि आप उस दृष्टि से भी इस कार्य को देखेंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

02.03.2022/1505/av/ag/2

श्री नरेन्द्र ठाकुर, सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी भाग लेंगे।

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) : सभापति महोदय, यहां पर जो नियम-130 के अंतर्गत शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत हो रहे विकासात्मक कार्यों पर प्रस्ताव लाया गया है, मैं भी इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

मुझसे पूर्व सभी माननीय सदस्यों ने और खासकर हमारे युवा माननीय सदस्य श्री विक्रमादित्य सिंह ने स्मार्ट सिटी के कंसैप्ट के बारे में काफी विस्तार से कह दिया है कि यह स्मार्ट सिटी क्या है तथा कैसे इंप्लीमैंट होना है; अतः मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं

मंत्री महोदय से केवल यही जानना चाहता हूं कि आप केवल एक काम गिनाएं जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हुआ है। स्मार्ट सिटी क्या है? मंत्री जी तो स्मार्ट है नहीं, आपके अधिकारी भी स्मार्ट नहीं है। फिर स्मार्ट है क्या? केवल स्मार्ट सिटी नाम देने से शहर स्मार्ट नहीं बनता। ...व्यवधान....नहीं, मैं इनको जोश दे रहा हूं ताकि ये और ज्यादा स्मार्ट दिखें। यहां शिमला के लोग स्मार्ट और खूबसूरत भी हैं। आपने जो कंसलटैंट हायर कर रखा है जिसको शायद आप करोड़ो रुपये दे रहे होंगे; उनमें कोई स्मार्ट नहीं है। आपने इसमें जो सिविल इंजीनियर्ज या दूसरे कर्मचारी रखे हैं वे पता नहीं सारे-के-सारे आउटसोर्स पर है या कैसे रखे हैं; उनको शायद आप ठीक से तनख्वाह नहीं दे रहे होंगे इसलिए वे कोई भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अभी माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु ने आपकी बड़ी तारीफ की कि सड़कें काफी चौड़ी कर दी हैं। आप दोनों शिमला से है तो ऐसा लगता है कि कुछ मैच फिक्सिंग जरूर है। ...व्यवधान... आपकी जो सड़कें हैं ये एम0सी0 की नहीं बल्कि लोक निर्माण विभाग की हैं। पहले इसके लिए एन0एच0 था और अब पता नहीं आपने इसके लिए क्या स्टेटस बना रखा है। जब एन0एच0 था तो इसको चौड़ा करने के लिए एन0एच0 का पैसा खर्च होना चाहिए था और जो सड़क चौड़ा करने का काम हो रहा है उसमें भी पिक एण्ड चूज का काम चला हुआ है। आप कार्ट रोड पर एम0एल0ए0 होस्टल और रेलवे स्टेशन के बीच के पोर्शन को देखिए,

02.03.2022/1505/av/ag/3

आप शायद उस रास्ते से कभी आए नहीं होंगे? यह पोर्शन सबसे तंग है और सुबह 09.00 बजे के बाद इस पर जाम लगना शुरू हो जाता है। आपने उसके बारे में कभी ध्यान नहीं दिया; इस प्रकार से पिक एण्ड चूज वाले काम हो रहे हैं। आपकी एम0सी0 जब एक एक्ट के तहत यहां पर है तो आपने स्मार्ट सिटी को एक ऑथोरिटी टाइप क्यों बना दिया? उन्होंने अपना धंधा शुरू कर दिया और एक डंगा जो एम0सी0 ने लगाया होता है उसी डंगे को बाद में आप द्वारा तोड़ कर लगा दिया जाता है। इधर का पत्थर निकालकर उधर डाल देते हैं और ठेकेदारों तथा अधिकारियों के मजे लगे हुए हैं। आपका इस बारे में कोई विज़न प्लान नहीं है। आप जो शिमला डवलपमैंट प्लान के बारे में कह रहे हैं, जिसके बारे में आपने बहुत चर्चा की है कि पिछले 40 वर्षों में जो शिमला डवलपमैंट प्लान नहीं बना; वह आपने

बनाया है। अब पता नहीं उसके लिए तीसरी ऑथोरिटी आएगी। आप मुझे यह बताइए कि इस तरह से ओवरलैपिंग ऑफ ऑथोरिटीज के द्वारा किस तरह से काम किया जाएगा? जहां पर शौचालय की जरूरत नहीं होती वहां पर एम0सी0 वाले भी बना लेते हैं और अगर किसी ठेकेदार को वह जगह प्रोफिटेबल लगे यानी जहां पर उसको कैरेज कम पड़े तो वहां तीन-तीन शौचालय बन जाते हैं। कहने को तो शिमला को 'क्वीन ऑफ हिल्ज' कहा जाता है परंतु मेरे हिसाब से तो इसका केवल नाम ही क्वीन ऑफ हिल्ज रह गया है बाकी सारी शक्ल-सूरत खराब हो गई है।

टी सी द्वारा जारी

02/03/2022/1510/टी0सी0वी0/ए0एस0/1

श्री जगत सिंह नेगी... जारी ।

रिज के ऊपर एक डंगा चला गया, छह महीने तक आप उस डंगे को नहीं लगा सके। कभी आप कहते हैं कि रुड़की से इंजीनियर आ रहा है और बाद में पता नहीं आप यूक्रेन से इंजीनियर लेकर आए होंगे। जबकि नगर निगम यहां पर है, प्रदेश सरकार यहां पर है और स्मार्ट सिटी के स्मार्ट इंजीनियर्ज आपके पास हैं। जो लोग शिमला आते हैं वे लोग रिज पर चलने के लिए बड़े खुश होकर आते हैं लेकिन सड़कों का हाल यह है जैसे हम फटे हुए कपड़ों पर टाली लगाते हैं। जब इतना पैसा आ रहा है तो इन सड़कों पर तो रबड़ बिछाया जाना चाहिए था। आप एक एस्केलेटर नहीं लगा पाए। आपने रोपवे का होटल बना दिया लेकिन वह खाली पड़ा हुआ है। केन्द्रीय सरकार की एक बिल्डिंग के लिए एन0ओ0सी0 लेने में डबल इंजन की सरकार को 5 साल लग गए। अगर कोई बिल्डिंग इसमें बाधा आ रही है तो उस बिल्डिंग को एक्वायर किया जा सकता है। आपको उस पुरानी बिल्डिंग को एक्वायर करने से कौन रोक रहा है? आप उसको एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से सारा प्रोजैक्ट बंद पड़ा हुआ है। रोपवे की जो कॉस्ट आज से 5 साल पहले थी, वह आज डबल हो गई है। इतना पैसा कहां से आएगा? आप कैसे शिमला को स्मार्ट बनाएंगे यह हमारी सोच से बाहर है। कुछ दिनों पहले विधान सभा की एस्टिमेट कमेटी जिसके

चेयरमैन श्री रमेश चंद ध्वाला जी है, हमने पूरे शिमला का विजिट किया परंतु हमें एक भी स्मार्ट कार्य नहीं दिखाई दिया। आपका जो भी कार्य हो रहा है, उस तरह के कार्य यहां पहले भी हुए हैं। आपने उसमें कोई नई सोच पैदा नहीं की। आपने शिमला के अंदर कोई स्काई-वे या नई ट्रैफिक टनल नहीं बनाई है। यहां पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। टनल खोद कर भी पार्किंग बनाई जा सकती थी। आपके पास कोई नई सोच नहीं है। आपकी वही वर्ष 1957 की सोच है और उसी को लेकर आप चले हुए हैं। अब तो आपका समय खत्म हो गया है। अब तो हमें आना है और हमें ही इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हमें ही स्मार्ट बनना पड़ेगा तभी शिमला सिटी स्मार्ट बन पाएगा। आप कह रहे हैं कि 50 प्रतिशत फंडिंग हमने

02/03/2022/1510/टी0सी0वी0/ए0एस0/2

करनी है लेकिन आप खुद कर्ज ले रहे हैं तो फिर 50 प्रतिशत फंडिंग कहां से करोगे? शिमला स्मार्ट सिटी एक धोखा है इसमें कोई काम होने वाला नहीं है। आपने प्रस्ताव को इसलिए बदल दिया क्योंकि इसमें अनियमितताएं हो रहीं हैं। एक डंगा जो 20 लाख रुपये में लगना है वह 40 लाख रुपये का लग रहा है। आपके ठेकेदारों के मजे लगे हुए हैं। कम्युनिटी भवन जो एक करोड़ का बनना था, उसमें देरी होने के कारण वह अब डेढ़-दो करोड़ रुपये का बनेगा। स्मार्ट सिटी में धांधली के सिवाय कोई काम मौके पर ठीक से नहीं हो रहा है। इसकी आपको चिंता करनी चाहिए। आपके पास जो पैसा है उसको नगर निगम को दे दें। आप नगर निगम को पूछ सकते हैं कि हमने इतना पैसा दिया है, वह कहां खर्च हुआ? आप उनको विजिन बनाकर दें। आप उनको कह सकते हैं कि यहां पर टॉयलेट हो, बढ़िया सड़कें हो, एस्केलेटर हो या पार्क हों। आप उनको इस तरह का प्लॉन बनाकर दें और उसमें यदि कोई गड़बड़ हों तो आप उनको पकड़ सकते हैं। आपको कौन पकड़ सकता है। इसलिए आप प्रस्ताव बदल रहे हैं। एक ही काम पर 2-2 बार पैसा लगा रहे हैं या तो फिर वहां पर बोर्ड लगा लो। इसमें आफत यह है कि आप बोर्ड पर भी करोड़ों रुपया

लगा देंगे। आप एक छोटा-सा बोर्ड भी लगा सकते हैं जिसमें यह लिखा हो कि यह कार्य स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हुआ है ताकि उसमें पैसे की बर्बादी न हों। धन्यवाद।

अगला वक्ता एन0एस0 द्वारा ... शुरू ।

02-03-2022/1515/NS/AS/1

सभापति : अब चर्चा में श्री संजय अवस्थी जी भाग लेंगे।

श्री संजय अवस्थी, अर्की : सभापति महोदय, धन्यवाद। नियम-130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव लाया गया है कि "शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत हो रहे विकासात्मक कार्यों पर यह सदन विचार करे।" पर मैं चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि अक्सर कहा जाता है कि 'कल्पनाओं की उड़ान बहुत ऊंची होती है मगर यथार्थ के कदम अक्सर छोटे रह जाते हैं।' मैं आज शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना का यह स्वरूप देखता हूं। वर्ष 2015 केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जिसमें भारत वर्ष के 30 शहरों का चयन किया गया और हिमाचल प्रदेश के भी दो शहर इसमें शामिल किए गए। दूसरे नम्बर पर शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला लिया गया और सूची में शामिल किया गया। इसके लिए 2905 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई और इसका प्रारूप बना। इस विषय में चर्चा करने के लिए मैंने भी अपने आपको इसलिए शामिल किया क्योंकि जब विधान सभा का सत्र शुरू हुआ तो 2905 करोड़ रुपये की परियोजना शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए शुरू की गई। यह बात मेरे संज्ञान में भी थी। मैं कार्ट रोड से यह देखने के लिए पैदल चला कि शायद कुछ बदलाव आया होगा। मेरे छात्र जीवन का अधिकांश समय यहां व्यतीत हुआ है। मैं सब्जी मंडी, लोअर बाजार और मिडल बाजार से होते हुए माल रोड पहुंचा। मैंने कल्पना की थी कि शायद एस्केलेटर का काम शुरू हो गया होगा लेकिन मुझे कहीं पर भी एस्केलेटर नहीं दिखा। पूर्व में जो एक तरह का मिस मैच था रिज और माल रोड को छोड़ कर यदि हम मिडल बाजार व लोअर बाजार को देखें तो आज भी वही मिस मैच है। आज भी इसका स्वरूप शिमला के स्लम एरिया की तरह ही है। माल रोड पर दो-तीन जगहों पर जहां कूड़ादान पड़े हुए थे उसमें से भंयकर कुत्तों के झुंड निकल रहे थे। आपकी स्मार्ट सिटी की क्या परिभाषा रही होगी, मैंने इसको भी जानने की कोशिश की। इसलिए मैंने इस चर्चा में भाग लेने का निश्चय किया।

सभापति महोदय, शिमला सिटी को पहले ही हेरिटेज सिटी का दर्ज़ा प्राप्त है और अंतरराष्ट्रीय मानचित्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे ही पर्यटक शिमला में एंटर करते हैं तो सबसे पहले भंयकर जाम से रूबरू होते हैं। जब शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने की कल्पना की तो सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए था

02-03-2022/1515/NS/AS/2

और आज इसका अभाव है। मंत्री जी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन कमियां रह जाती हैं। मैं आपके ध्यान में उन विषयों को लाना चाहता हूं जिनकी मैंने कमियां महसूस की हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूर्णतया फेल है। मुझे सत्र के बीच में घूमने का मौका मिला तो मैंने शिमला के अलग-अलग क्षेत्रों का दौरा किया और देखा कि कुछेक स्थानों को छोड़ कर कहीं पर भी पार्किंग नहीं बनी हुई है। हमें हर क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसके अलावा कई स्थानों पर बिजली की तारों को मैं छात्र जीवन से वैसे ही देख रहा था और

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी

02.03.2022/1520/RKS/एएस-1

श्री संजय अवस्थी...जारी

आज उन बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करने की जरूरत है। शिमला एक ऐतिहासिक शहर है। यहां पर जिस तरह से हैवी आयरन का प्रयोग किया गया है, यह ठीक नहीं है। अगर हम संजौली की तरफ जाएं तो वहां पर जितने भी ऑवर फुट ब्रिजिज बने हैं उनमें बहुत ज्यादा लोहे का इस्तेमाल किया गया है। सड़कों को चौड़ा करने के लिए बड़े-बड़े डंगे लगाए जा रहे हैं जिन्हें लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारा विजन सही होता तो इस शहर के स्वरूप को और बेहतर किया जा सकता था। माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने ठीक कहा कि जो कार्य एक लाख रुपये में किया जाना था उसे 10 लाख रुपये में पूर्ण किया जा रहा है। मेरा आग्रह है कि इसकी जांच करवाई जाए। रोपवे भी एक प्रकार से 'means of transportation' है। अगर रोपवे बनाने का कार्य पहले फेज़ पर शुरू किया होता तो इसके निर्माण कार्य की लागत भी कम रहती और लोगों को समय पर

इसकी सुविधा भी मिलती। लेकिन रापवे का कार्य अभी तक कहां पहुंचा है यह आप अच्छी तरह जानते हैं। बच्चों व वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा मुहैया करवाने के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। मेरा आग्रह है कि बच्चों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। मेरे साथियों ने अधिकतर बिन्दुओं पर चर्चा कर ली है लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो पब्लिक मनी है उसका सदुपयोग होना चाहिए। शिमला एक ऐतिहासिक नगरी है और इसे हम टूरिस्ट प्लेस ही रहने दें तो अच्छा रहेगा। यहां पर जो ऑफिसिज और कंकरीट एवं आयरन का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, इसको बदलने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव रहेगा कि आप इस योजना पर भी कार्य करे। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल इस चर्चा में भाग लेंगे।

02.03.2022/1520/RKS/एएस-2

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : सभापति महोदय, जो नियम-130 के अंतर्गत "शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत हो रहे विकासात्मक कार्यों पर यह सदन विचार करे।" प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, इसमें साथी विधायकों ने बड़े विस्तार से अपनी बात रखी है। मैं नगर निगम, शिमला में कई बार पार्षद रहा हूं इसलिए मेरे ज़हन में आया कि मैं भी इस चर्चा में भाग लूं। वर्ष 1986 में नगर निगम, शिमला की स्थापना हुई। परिस्थितियों के हिसाब से उस समय शिमला की भव्यता बहुत सुंदर थी। शिमला शहर को देखने के लिए बहुत दूर-दूर से सैलानी आते हैं। लेकिन समय के साथ-साथ धन की उपलब्धता होने के बावजूद भी हम शिमला शहर का स्वरूप नहीं बदल पाए। चाहे हमारी सरकार हो या वर्तमान सरकार, आज भी शिमला शहर को विकसित करने के लिए बहुत जरूरत है। पूर्व में शिमला शहर में बहुत विरोध के बाद एक डोग हट का निर्माण किया गया था। इसके लिए एक जगह चिन्हित की गई जहां शहर के आवारा कुत्तों को रखा जाता था। उस जगह के नीचे एक बाग गांव है।

श्री बी.एस.द्वारा.. जारी

02.03.2022/1525/बी.एस./डी0सी0/-1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जारी...

हमारी भी वहां पर जमींने और घर हैं, काफी विरोध भी लोंगों ने किया लेकिन सरकार और माननीय उच्च न्यायाल की भी मंशा थी कि वहां पर डॉग्ज हट बनाया जाए, लेकिन आज वह खंडहर बना पड़ा है। इतना पैसा लगाने के बावजूद क्या कारण है कि वह डॉग्ज हट बंद पड़ा है और शहर में आज भी कुत्ते घूम रहे हैं और लोगों को परेशन कर रहे हैं। उसके बारे में सरकार कुछ नहीं कहती है और न ही कुछ कर रही है। सरकार को इस बारे में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। नगर निगर के अंदर सबसे बड़ी समस्या है कि वहां पर स्टाफ की कमी है। आपके पास फंक्शनल स्टाफ ही नहीं है, आपके पास टैक्स पे कर्मचारी ही नहीं है और इंस्पेक्टर्ज नहीं हैं। पुराने लोगों या आउटसोर्स के सहारे आपने काम चला रखा है। आपको यही पता नहीं है कि हमारा रेवेन्यू कितना है, और हमारी स्टेट कितनी है। कई बार इसके ऊपर नगर निगम हाउस में चर्चा हुई, पूर्व में पार्षद रहे, अशोक सूद जी इस मुद्दे को काफी उठाते थे। आज हमारी आई0डी0पी0 प्लान नहीं बनी, डवलपमैंट प्लान नहीं बनी। आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं परंतु आपके पास प्लान ही नहीं है कि शहर को कैसे बसाना है और इसका विस्तारीकरण किन मुद्दों के आधार पर करना है। आप विस्तारीकरण को ले करके नए बार्ड बना रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने किस क्षेत्र से कौन-कौन सी चीजें बाहर ले जानी है? बड़े लम्बे समय से हम सुनते आ रहे हैं कि अनाज मण्डी को बदला जाएगा, परंतु आज दिन तक यह नहीं बदली गई, इसके क्या कारण है? जब शिमला के लिए 18 इंच की पाइप बिछाई गई थी उस समय स्वर्गीय नरेन्द्र ब्रागटा जी बागवानी मंत्री थे और आदरणीय रूप दास कश्यप जी शहरी विकास मंत्री थे। उस समय वे नगर निगम की बैठक में भी आए थे और वहां पर उनके साथ हमारी बहुत लम्बी चर्चा भी हुई थीं कि यह जो 18 इंच की पानी की पाइप बिछाई जा रही है, यह शहर के लिए ठीक नहीं है। इसके बिछाने का जो तरीका है वह ठीक नहीं है। उस समय सरकार और अधिकारियों ने यह कहा कि यह तो नई तकनीक की लाइन बिछाई जा रही

है और यह लंबे समय तक काम करेगी। जब उस लाइन की टैस्टिंग होनी थी, तो स्केंडल प्वाइंट में वह फट गई। उसके साथ ही आकाशवाणी के पास पाइप फट गई। यह तो शुक्र है कि उस समय उसमें

पानी ज्यादा नहीं था नहीं तो शिमला का एक भाग, लोअर बाजार उसमें बह जाता। आकाशवाणी के साथ तो काफी इसका नुकसान भी हो गया था। कहने का तात्पर्य है कि पैसा तो केन्द्र सरकार या वल्ड बैंक से ले आते हैं। पहले जे0एन0यू0आर0एम0 से पैसा आया, फिर स्मार्ट सिटी से पैसा आया। यदि केवल डंगे लगाने के लिए ठेकेदारों को यह पैसा देना है, तो उससे शिमला का स्परूप बदने वाला नहीं है। आपने नगर निगम के साथ लगते गांवों की सड़कों में स्मार्ट सिटी का पैसा लगा दिया है। आपने डी-पार्क होटल से ले करके घोड़ाचौकी के पास से जो लोअर घोड़ाचौकी को नाला जाता है उसके चेनेलाइजेशन के लिए लोगों ने पता नहीं कितनी बार आग्रह किया, परंतु आज तक वह कार्य नहीं हो पाया है। वहां जो नाले से पानी आता है, उस पानी का रिसाव कुछ घरों में जाता है। उन लोगों ने कमीशनर महोदय को कई बार लिख करके दिया, कई बार मंत्री महोदय से भी वे लोग मिले होगें परंतु उनकी समस्या का कोई भी हल नहीं हुआ है। कच्चीघाटी में जो एरिया डवलप हुआ है, वहां पर सड़क में जाम लगा रहता है। लोगों को अपनी गाड़ियां खड़ी करने के लिए जगह नहीं है। कोई पार्किंग प्लेस नगर निगम ने चिन्हित नहीं किया है।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल..... जारी

आप कैसे शिमला को स्मार्ट सिटी बनाएंगे? शिमला में जो तारा देवी का क्षेत्र है वह gateway of Shimla Municipal Corporation है। नगर निगम का क्षेत्र तारा देवी से शुरू

हो जाता है लेकिन तारा देवी में ही कोई भी टॉयलेट ब्लॉक नहीं है। उसके रास्ते में कच्चीघाटी में अभी आपने एक टॉयलेट ब्लॉक बनाया है। मोटर बेरियर पर जो सुलभ शौचालय बना है कभी उसकी कंडीशन देखना, वहां पर कोई जा ही नहीं सकता। मोटर बेरियर में ही बहुत पुराना एक शोपिंग कॉम्पलैक्स है और जब मैं पार्षद था तब हमने नगर निगम में एक प्रस्ताव पास किया था कि शोपिंग कॉम्पलैक्स को दोबारा से बनाया जाए और थोड़ा पीछे हट कर बनाया जाए। जिससे वहां पर जगह भी खुल जाएगी और वह नए तरीके से भी बन जाएगा। आज तक उस पर भी सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। आप स्मार्ट सिटी की प्लांनिग किस प्रकार से कर रहे हैं वह समझ से परे है। आपके पास तो प्लानिंग करने के लिए पूरा विंग है और आपने सभी अधिकारियों को वहां पर बिठा रखा है तो वे वहां बैठ कर क्या प्लानिंग करते हैं? हमने शहर को कैसे बसाना है और कैसे नए मर्जड ऐरियाज़ का विकास करना है, उसके लिए आपके पास कोई नीति ही नहीं है। आपके जो ठेकेदार हैं वे पुराने रास्तों को टेण्डर ले लेते हैं और साल-साल तक काम ही नहीं करते। इसी प्रकार पुरानी रेलिंग्स को भी नहीं बदला जा रहा है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटों की हालत भी खराब है और वे जल नहीं रही हैं। संकट मोचन से नीचे की तरफ का जो ऐरिया है और वहां के बुजुर्ग लोगों ने काफी समय से मांग की हुई है कि वहां से एक टैक्सी चलाई जाए। लेकिन वह टैक्सी भी आज तक नहीं चली, आप कभी चलाते हैं तो कुछ समय बाद उसको बंद कर देते हैं। जहां पर पार्किंग का निर्माण किया गया है उसके पास एक Tourist Information Center है और वहां पर हर रोज़ बहुत जाम लगता है। वहां पर जो एक कॉम्पलैक्स बनाया है उसके साथ बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई है। उस जगह के लिए आपने क्या प्लानिंग की है कि उसका क्या करना है

02-03-2022/1530/डी.सी.-ए.जी. /2

क्योंकि वह तो ऐसे ही पड़ी हुई है और उसमें बिच्छुबुट्टी की झाड़ियां उग गई हैं। टूरिस्ट भी सबसे पहले उन्हीं को देखते हैं और उसकी छत पानी से भरी होती है। आप किस प्रकार की ड्राइंग बनाते हैं जिसमें न पानी की निकासी को देखते हैं और जो सड़क बनी हुई है उसको कैसे खुला करना है न इसके बारे में सोचते हैं? जब आपको कोर्ट से आर्डर आते हैं तब आप

कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा बालुगंज बाजार में केवल 20-30 दुकानें हैं और आज उनका बिजनस खतरे में है। क्या सरकार ने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है? वहां पर कोई पार्किंग नहीं है और यदि कोई व्यक्ति 10 रुपये की चीज खरीदने के लिए अपनी गाड़ी साइड में लगा लेता है तो उसका 1,000 रुपये का चालान कट जाता है। यह छोटी-छोटी चीजें हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है और इसके लिए तो सरकार को ही सोचना होगा। सारे काम तो पार्षद नहीं कर सकता लेकिन पार्षद ने यदि कोई मांग निगम में या सरकार से की है तो अधिकारियों का इतना फर्ज़ तो बनता है कि मौके पर जाकर उस कार्य का सर्वे करें और देखें कि वहां पर क्या-क्या किया जा सकता है। लेकिन आज तक इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई उस क्षेत्र के लिए नहीं हुई। बालुगंज क्षेत्र में आज तक कोई भी सामुदायिक भवन नहीं है और यह बहुत पुराना बाजार है। यह समरहिल और बालुगंज वार्ड का केन्द्र बिन्दु है। अभी बालुगंज चौक का निर्माण किया जा रहा है और यह एक अच्छी शुरूआत हुई है लेकिन बहुत लम्बे समय के बाद हुई है। आप सभी जानते हैं कि जितनी भी वी.आई.पी. मूवमेंट होती है वह सब यहीं से होती हैं। आज सुबह जब मैं हमीरपुर से आ रहा था तब टूटू तक जाम लगा हुआ था। वहां पर इतना ट्रैफिक है और उसे bifurcate कैसे करना है इसके लिए सरकार को कोई प्लान बनाना चाहिए। खासकर जब कोई वी.आई.पी. मूवमेंट हो या विधान सभा का सत्र लगा हुआ हो तब के लिए तो कोई प्लान होना ही चाहिए कि हमने ट्रैफिक को कैसे मैनेज करना है या हमने कोई लिंक रोड निकाल कर ट्रैफिक को बाइपास करना है। मैं नहीं समझता कि स्मार्ट सिटी के तहत आपने इस बारे में कुछ सोचा होगा। शिमला में सबसे बड़ी समस्या तो अवारा कुत्तों और बंदरों की है।

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

02.03.2022/1535/JK/HK/1

श्री इन्द्र दत्त लखनपालः-----**जारी**-----

जो बालूगंज से चक्कर का रूट है, उसके साथ कोई टॉयलेट नहीं है। एक लास्ट में चक्कर में जा करके है जो पहले मिडिल में बना हुआ था लेकिन उसको आपने लोगों की मांग पर तोड़ा और लास्ट में ले कर गए। उसके बीच के रास्ते में न तो रेन शैल्टर है, न ही वहां पर

कोई पब्लिक टॉयलेट है। इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। स्मार्ट सिटी में पैसा आया हुआ है और ये सारी प्लानिंग की बातें होती हैं। अगर लोग दो किलोमीटर बालूगंज से चक्कर की ओर पैदल जा रहे हैं और छोटे बच्चों को जब स्कूल से छुट्टी होती है, जब उनके ऊपर बन्दर झपटते हैं या जब बारिश होती है तो उनको खड़े होने के लिए जगह चाहिए, वहां जगह ही नहीं है जबकि वहां पर पर्याप्त मात्रा में खाली जगह है जहां पर रेन शैल्टर बन सकता है। इसके ऊपर और ध्यान दीजिए। माननीय मुख्य मंत्री जी का ओक ओवर के पास जो रेजिडैंस है, वहां पर चार-पांच बिल्डिंग्ज़ को खतरा हो गया है। उसके बारे में सरकार ने आज तक क्या किया? आपको मालूम होगा कि दो महीने तक न्यू सर्किट हाउस में उन परिवारों को रखा गया। यहां पर एन.जी.टी. और पर्यावरण की बातें होती हैं। वह एन.जी.टी. और फोरैस्ट डिपार्टमैंट कहां चला गया? उसमें किसने कोर एरिया में कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन दे दी? वहां पर बड़े-बड़े डंगे लगाने की परमिशन किसने दे दी? वहां पर पेड़ काटने की परमिशन किसने दे दी? आम आदमी यदि नगर निगम में नक्शा ले करके जाता है तो कई सालों तक उसका नक्शा पास नहीं होता है जब तक उसकी एप्रोच न हो। आप रिकॉर्ड देखिये कि जिस एक आम व्यक्ति ने आपकी कार्पोरेशन में पानी के लिए अप्लाई किया होगा या नक्शा पास करवाने के लिए अप्लाई किया होगा, क्या उसका काम हुआ या नहीं हुआ? वहां पर मेरे जैसा विधायक एप्रोच कर देगा, कोई ब्यूरोक्रेट से एप्रोच करवा देगा। मंत्री जी से एप्रोच करवा देंगे या मुख्य मंत्री जी किसी की एप्रोच कर देंगे,उसका नक्शा तो हाथों-हाथ पास हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो लोग छोटी-छोटी क्वारीज़ को ले करके परेशान हैं, कभी अखबारों में आ जाता है कि सिंगल विंडो के माध्यम से काम होंगे उससे जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। ऑन लाइन नक्शे पास हो जाएंगे। आपने कितने ऑन लाइन नक्शे पास किए? जो हमारा मर्ज़ड एरिया है, जिसमें हजारों भवन नियमिती की बाट जोह रहे हैं, रिटेंशन पोलिसी का आज तक कुछ नहीं हुआ। चार-साढ़े चार साल आपकी सरकार को होने वाले हैं और इतने साल हमारे भी निकल गए।

02.03.2022/1535/JK/HK/2

आपने नगर निगम के चुनावों के समय मैनिफेस्टो में कहा था कि हम इन भवनों को नियमित करेंगे, उसके लिए आपने कौन सी पोलिसी बनाई? बड़ी विचित्र सी बात है कि एन.जी.टी. के लोग, जिनका शिमला से कोई ताल्लुक नहीं है, जिन्होंने यहां पर रहना नहीं

है, जो लोग यहां के वाशिन्दें हैं, जो यहां नौकरी-पेशा करते हैं, उन्होंने भारी-भरकम लोन ले करके भवन बना दिए लेकिन आज वे खंडहर बन चुके हैं। वह भी हमारे देश व प्रदेश की प्रॉपर्टी है। उसके बारे में गम्भीरता से क्यों नहीं सोचा जाता है? क्यों नहीं उनका पक्ष मज़बूती के साथ रखा जाता है? माननीय हाइकोर्ट जहां से आदेश पारित होते हैं, उनकी बिल्डिंग तो 14-15 मंजिल बन जाए और एक आम व्यक्ति अगर 5-6 मंजिल भवन बना देता है तो उसका नक्शा पास न हो, यह कहां का कानून है, यह कौन सा लोकतंत्र है? यह सोचने की जरूरत है। जहां से हम कानून बनाते हैं, जहां से फैसले सुनाए जाते हैं क्या वे फैसले जनता को दबाने को लिए जा रहे हैं? अगर 5-6 मंजिल भवन बनें हैं तो उनको अवैध करार दिया जा रहा है। हमारे प्रदेश के जो ब्यूरोक्रेट/अधिकारी थे वे कहां पर सोये हुए थे? उन्होंने क्यों मौके के ऊपर कार्रवाई नहीं की? उन्होंने वह काम क्यों होने दिया? आप आज न्यू शिमला के हाल देखिए, वहां पर पैदल चलना मुश्किल है। सड़कें बहुत ही संकरी हैं। हर जगह एन्क्रोचमैंट की हुई है। यहां तक की बी.सी.एस. के साथ लगते घरों के लोगों की गाड़ियों को पार्क करने की कोई भी सुविधा स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत मुहैया नहीं करवाई गई है। आप न्यू शिमला में देखिये तो वहां पर आम आदमियों के मकान बहुत कम हैं। वहां पर बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के घर हैं। वहां पर सबसे ज्यादा अफरा-तफरी मचा रखी है। जो ग्रीन पार्क छोड़ा था उसकी लैंडयूज चेंज करवा करके वहां पर मकान बना दिए गए। आप आम पब्लिक को तो बहुत डराते हैं। वहां पर पीने का पानी नहीं है। डोर-टू-डोर गारबेज के बुरे हाल है। डोर-टू-डोर गारबेज वाले कूड़ा उठाने के लिए 15-15 दिन नहीं आते हैं। वे कहां से आएंगे, सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि उनको ठहरने की व्यवस्था नहीं है। जो हमारे घरों का कूड़ा उठाता है, उसके लिए कहीं पर किराए का मकान नहीं मिलता है। नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के तहत क्या प्लानिंग की है कि जो वहां पर हमारा गंद उठाएंगे उनको ठहरने की व्यवस्था कहां पर करनी है? आप पोलिसी तो बना देते हैं। डोर-टू-डोर पोलिसी तो बना दी और फ्लां आदमी को ठेका दे दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है और घरों से 50-50 और 100-100 रुपया लो और कूड़ा इकट्ठा करो।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

02.03.2022/1540/SS-HK/1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल क्रमागत :

वे लोग बेचारे आते हैं, कहीं कोई बिहार से आ रहा है, कोई यू0पी0 से आ रहा है लेकिन उनको यहां पर ठहरने के लिए जगह नहीं मिलती है। क्यों नहीं आप उनके लिए लेबर हट बनाते? उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी अच्छे घर में ठहरने का अधिकार है। तभी तो वे हमारे घरों से कूड़ा उठाएंगे जब उनको प्रोटैक्शन होगी; जब उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए साधन मुहैया होंगे । ये जो आप हवा में तीर चलाए जा रहे हैं इससे लोगों का भला होने वाला नहीं है। शहरों में पेयजल की समस्या रह रही है जबकि आज इतनी बड़ी-बड़ी स्कीमें यहां पर बनी हैं। आप पानी के बिल देखिए। आपके पास स्टाफ नहीं है। पानी का बिल किसी को दो लाख रुपया पहुंच रहा है, किसी को ढाई लाख रुपया पहुंच रहा है और किसी को 50 हजार रुपया पहुंच रहा है तो इन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको जिस ऑफिस को चलाना है उसको संगठित कीजिए। उसमें आप पूरा स्टाफ भरिए ताकि आप लोगों को अच्छी सुविधाएं दे सकें। हर वार्ड में जो आपने ऑफिस खोले हुए हैं वहां पर स्टाफ नहीं होता है तो फिर लोगों की समस्याएं कहां से दूर होंगी? यहां पर ठीक कहा गया कि नगर-निगम का भवन ही नहीं है। जो नगर-निगम का भवन था उसका भी न्यायालय में केस चल रहा है। मैं एक दिन कमिश्नर साहब और मेयर के ऑफिस में गया था तो मैंने देखा कि अभी तक आपने उसमें कारपेट तक नहीं बिछाए हैं। उसमें पानी टप-टप कर रहा है। उसके लिए कोई जिम्मेवारी फिक्स नहीं हुई। अब आप बोलेंगे कि वह आपके समय में बना। वह भले ही हमारे समय में बना लेकिन मंत्री महोदय वर्तमान समय में वह आपकी जिम्मेवारी है। सरकार की जिम्मेवारी है। जब वह भवन बन रहा था, जिसको पूर्व मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने स्वीकृति प्रदान की थी, उसके लिए 8-10 करोड़ रुपया सैंक्शन किया था। वे जब भी शिमला में होते थे तो हमेशा उस भवन की चैकिंग करने जाते थे कि काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। उन नेताओं से सीख लेनी चाहिए कि वे हमेशा भ्रमण करते थे और देखते थे कि कहां क्या हो रहा है, आर्किटैक्चरल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन आज वह छत टपक रही है। अगर आप रिपोर्टिंग रूम की साइड को देखेंगे तो वहां पर घास जमनी शुरू हो गई है। इन चीज़ों को कौन देखेगा? हम हैरीटेज-हैरीटेज बोलते हैं, हैरीटेज के लिए पैसा भी खर्च करते हैं लेकिन बाद में जो उसमें अनियमितताएं होती हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। मंत्री महोदय

शिमला शहर से आपका बहुत गहरा लगाव रहा है। हम तो आपको शिमला का ही मानते हैं। चार बार आप यहां से विधायक भी बन गए हैं और एक बार सांसद भी बन गए हैं इसलिए कृपा करके आप इसका कुछ सुधार करेंगे।

मैं समझता हूं कि टूरिस्टों को कितनी प्रॉब्लम होती है। टूरिस्टों के लिए आपके पास सिर्फ एक प्वाइंट बैरियर के पास है वहां पर भी उनके बैठने के लिए पूरी तरह से जगह नहीं है। बाकी आपके पास कहीं पर टूरिस्ट काउंटर नहीं हैं जहां से टूरिस्ट को पता चल सके कि कहां पर कैसे जाना है। आज भी दलालों के चक्कर में फंस कर उनसे भारी पैसा वसूल किया जाता है। जो so called दलाल बने हुए हैं जो टूरिस्टों को जबरदस्ती खींच-खींचकर होटलों में ले जाते हैं उनकी भी एक समस्या है। जो शिमला शहर के अंदर होटल हैं उनका बिजनेस खत्म हो गया है।

श्री नरेन्द्र ठाकुर, सभापति : लखनपाल जी, आप वाइंड अप करिए, काफी हो गया।

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : सभापति महोदय, बड़ा गम्भीर विषय है इसमें होटलियर्ज को भी प्रॉब्लम है। हमारा जो शिमला शहर है आपको पता है कि उसमें आने-जाने के लिए रेस्ट्रिक्टिड एरियाज हैं। वहां पर गाड़ियां जा नहीं सकतीं और जो हमारे खान हैं या फिर सिरमौरी भाई हैं जो टूरिस्टों को उन होटलों तक पहुंचाते हैं उनको भारी-भरकम कमिशन देनी पड़ती है। कभी आपने इसके बारे में आकलन करना। अब शिमला शहर के होटलियर्ज की जो समस्या है, उनके होटल्ज में टूरिस्ट्स नहीं आ रहे। उनको आप ट्रासंपोर्टेशन में क्या सहायता कर सकते हैं यह देखने वाली बात है ताकि टूरिस्ट्स उनके होटलों में भी पहुंचे। उन्होंने जो वर्षों पुराने होटल्ज बना रखे हैं उनको भी लाभ मिले। इस सारी स्थिति को देखना किसका काम है? वह आपका काम है। आप मंत्री भी हैं और विधायक भी हैं। कारपोरेशन आपकी है तो आपको इन सारे विषयों पर चिन्ता करनी चाहिए और जो नियमितताएं हो रही हैं उन्हें देखने चाहिए। लाखों-करोड़ों रुपया जो डंगों के ऊपर खर्च किया जा रहा है कृपा करके उसको बंद कीजिए। कोई अच्छा काम करिए। उसमें टूरिस्टों के लिए कोई ठहराव प्वाइंट बनाइए ताकि यहां पर ज्यादा-से-ज्यादा टूरिस्ट आएं और पूरे वर्ल्ड में शिमला की जो शान है वह बनी रहे। इसको कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है, इसे देखें।

02.03.2022/1540/SS-HK/3

अभी तक आपकी रोपवे कामयाब नहीं हुई। कब से इसके पीछे लगे हुए हैं कि रोपवे आ रही है और जनता को अब कोई समस्या नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हैं इनके ऊपर आप ध्यान से देखें ताकि हम जनता को एक अच्छा वातावरण दे सकें। इसके लिए आपको प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। माननीय विधायक ने इसमें बहुत अच्छी चर्चा लाई है इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

जारी श्रीमती के0एस0

02.03.2022/1545/केएस/वाईके/1

सभापतिः अब इस चर्चा में श्री राकेश सिंघा जी भाग लेंगे।

श्री राकेश सिंघा (ठियोग): सभापति महोदय, नियम 130 के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री विक्रमादित्य सिंह जी, सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी, जगत सिंह नेगी जी, संजय अवस्थी जी और इन्द्र दत्त लखनपाल जी ने लाया है, उसकी चर्चा में मैं अपने आपको भी शामिल करता हूं। पहली बात है कि the record should be set right correct बहुत संघर्ष के बाद शिमला स्मार्ट सिटी में शामिल हो पाया है। मुझे पक्ष और विपक्ष के लोग और माननीय शहरी विकास मंत्री माफ़ करें। It was by the order of the Himachal Pradesh High Court, जो हमें स्मार्ट सिटी का स्टेटस मिला। ...(व्यवधान)... बेशक रॉंग हो, मैं कोट कर रहा हूं। It is "Sanjay Chauhan versus Union of India & others" उसके तहत आपको यह स्टेटस मिला है। शिमला शहर के 87 प्वाइंट थे, उसको इन्क्लूड करने के लिए Dharamshala had only 37 points. मुझे कोई गिला-शिकवा नहीं है कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी बनी लेकिन यह सच्चाई है। डबल बैंच का ऑर्डर, मैं आपको उसकी डेट भी देता हूं, it's 17th December, 2015 ऑनरेबल हाई कोर्ट के तहत हुआ। क्यों होना चाहिए यह रिकॉर्ड सैट राइट यहां पर after all, all this will go

into the history of Himachal Pradesh और इस बात को नज़र अंदाज़ नहीं करना चाहिए। सुरेश भारद्वाज जी, मुझे माफ़ करें, आप उस समय माननीय विधायक थे और आपकी जिम्मेवारी बनती थी। कोई बात नहीं, गल्तियां ज़िदगी में हो जाती हैं लेकिन ...(व्यवधान)... क्या बात कर रहे हैं आप? वह ऑर्डर है और भारद्वाज जी, मैं उस ऑर्डर को यहां पर प्लेस कर दूंगा। Let us not manipulate facts. Fact is fact. First of all that record should be set right. दूसरे, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा शिमला शहर आज से नहीं बल्कि जब ब्रिटिशर्ज़ का राज था, यह उस समय से जाना जाता है क्योंकि इसकी एक हैरिटेज वैल्यू है और एक बिल्डिंग नहीं, आप मुझे करैक्ट कर सकते हैं, भारद्वाज जी, आप माननीय हैं, मेरे से बड़े हैं, मेरे से अनुभवी हैं, more than 105 buildings इस शहर में ऐसी हैं जिनकी अपनी खूबसूरती है, जो हैरिटेज बिल्डिंग्ज़ की वजह से जानी जाती हैं। विक्रमादित्य जी ने

02.03.2022/1545/केएस/वाईके/2

करैक्ट कोट किया, from your Gorton Castle, टाउन हॉल की बिल्डिंग, वाइसरीगल लॉज़, गेयटी थियेटर, क्राइस्ट चर्चा, रिज पर लाइब्रेरी की बिल्डिंग, बैंटनी कैसल, रेलवे बोर्ड आदि अनगिनत बिल्डिंग्ज़ हैं लेकिन अगर हमने इस शहर को स्मार्ट रखना है, अच्छा रखना है, मेहरबानी करके इन बिल्डिंगों को बेचने का धंधा बंद करिए। हमने टाउन हॉल को जो बीच शहर में है, प्राइवेट पार्टी को बेचने का कार्य कर दिया है और अब लाइब्रेरी की बिल्डिंगको भी बेचने जा रहे हैं। क्या-क्या बेचोगे और क्यों बेचोगे? यह आपका और हमारा शहर है। यह हिमाचल की जनता का शहर है। क्या इसको हम कम्पनियों को बेच देंगे? Should be sale it? क्या बचेगा इस शहर का अगर एक-एक खूबसूरत चीज़ जो यहां इतिहास के साथ बनी है, हम प्राइवेट कम्पनीज़ को बेचते जाएंगे तो उसकी हेरिटेज वैल्यू नहीं रहेगी। भारद्वाज जी, आप सम्माननीय हैं, अनुभवी हैं, मैं हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा कि यह वाला काम बंद कीजिए। टाउन हॉल की कितनी सुन्दर बिल्डिंग थी, कितनी ब्यूटिफुल बिल्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। जिस दिन आप उसको प्राइवेट कम्पनी

को बेच देंगे, उसकी वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। सारी चीजें जिस नज़रिए से उस समय बनी थीं, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, यह मैं आपसे विनती करना चाहता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

02.03.2022/1550/av/yk/1

श्री राकेश सिंघा---------- जारी

हमारे इस शहर की खूबसूरती क्या थी। हां, आपकी (शहरी विकास मंत्री) तारीफ की और मैं भी करना चाहता हूं कि आपका इस शहर के लिए कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन उसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमने जो सड़कें चौड़ी की उसमें जो पहले पत्थर लगा था; उसकी ऐस्थेटिक वैल्यू थी। उसमें जो कट स्टोन लगा हुआ था वह सारा गायब हो गया है। हम उस पत्थर को गायब नहीं कर सकते थे। अगर उस पत्थर को दोबारा भी लगा देते तो आज जो कंकरीट का शहर बनता जा रहा है, हम उससे बच जाने थे। हमारा शहर खूबसूरत और स्मार्ट नहीं रहा, अब तो जगह-जगह अगलीनैस के धब्बे दिखते हैं। आप इस बारे में जांच कीजिए क्योंकि वह पत्थर बिक नहीं सकता। जितने भी ठेकेदार हैं; I am not against anyone but as per law आपका वर्ष 1957 का माइंस एक्ट और 2015 के रूल्स के बारे में हाई कोर्ट ने भी कहा है कि यदि एक्सकेवेशन के टाइम पत्थर या सैंड; जो कुछ भी है उसको इवैल्यूएट करने का एक तौर-तरीका है। उसके लिए एक कमेटी होगी जिसमें एक आफफिसर इंडस्ट्री डिपार्टमैंट से, एक माइनिंग आफिसर, रैवन्यू से तहसीलदार तथा लोक निर्माण विभाग से एस0डी0ओ0 होगा; जो उसको इवैल्यूएट करेगा। मगर all these stones have disappear. एक पत्थर की क्या वैल्यू होगी, क्या हो सकती है जिसकी इतनी डीप ऐस्थैटिक वैल्यू थी। उस समय का लगा हुआ वह पत्थर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था मगर वह सारे-का-सारा गायब कर दिया गया है और इसके बारे में किसी ने पूछा तक नहीं। चेड़ के अंदर जो पंपिग स्टेशन था वह ब्रिटिश टाइम का लगा हुआ था और

उसकी सारी-की-सारी मशीनरी अमेरिका से आई थी। उसको भी बेच दिया गया, मैं पूछता हूं कि उसकी इजाजत किसने दी? Has any enquiry be held? अगर हम अपने शहर के प्रति ईमानदार है और यह अच्छा व खूबसूरत बने तो इस तरीके के गोलमाल के कार्य बंद होने चाहिए। We should be bolden enough and I have to say कि केस कीजिए और जांच कीजिए; मगर ऐसा नहीं होता इसलिए यह एक बहुत बड़ी वीकनैस है। माननीय मंत्री, आप मेरे से सहमत होंगे कि हमारे यहां बिल्डिंग बनाने की परंपराएं धज्जी दीवार की थी और जो हम आज बना रहे हैं वह यहां की

02.03.2022/1550/av/yk/2

टोपोग्राफी के हिसाब से सूट नहीं करती। मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी इसके बारे में बहुत चिंतित रहते थे। He would always point out. वे हर चीज को प्वाईंटआउट करते थे और कई बार कड़ा रुख भी लेते थे। जिस तरह से कच्ची घाटी में बिल्डिंग गिरी थी, स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी वैली साइट में कभी कंस्ट्रक्शन करना नहीं मानते थे। What is happened? क्या शिमला स्मार्ट बन रहा है? मेरे हिसाब से नहीं बन रहा है। मेरा यह मानना है कि शिमला शहर की ब्यूटी पुराने आर्किटैक्ट के साथ रहेगी। उस पुराने आर्किटैक्ट में some new development can be made. उसको जोड़ा जा सकता है और ऐसा होना चाहिए क्योंकि उसमें अर्थ क्वैक रजिस्टैंस की क्षमता भी है। मैं माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल से भी सहमत हूं कि हमने केवल टाऊन हॉल या लाइब्रेरी की बिल्डिंग ही नहीं बेची बल्कि पानी तो बिल्कुल ही बेच दिया। जो बिल आ रहे हैं उनके बारे में आप भी जानते हैं और शहर के सब लोग जानते हैं। बिल क्या आ रहे हैं? They go into lakhs और 10-20 हजार रुपये बिल आना तो साधारण बात हो गई है। उस बिल को जब तक जमा नहीं करवाएंगे तो उनका कहना होता है कि हम इसका हिसाब-किताब ही नहीं करेंगे। कौन कर सकता है? It is becoming a commercial आप लोग अगली कमर्शियल तौर-तरीकों को इख्तियार करते जा रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है और

इसको सुधारना होगा। जब तक सेवादार की रिक्रूटमैंट नहीं होगी we will not be able to make this city smart. It can only be made smart.

टी सी द्वारा जारी

02/03/2022/1555/टी0सी0वी0/ए0जी0/1

श्री राकेश सिंघा----------... जारी ।

अगर हम उसको स्मार्ट बनाना भी चाहें तो भी यह रिक्रूटमेंट के बगैर नहीं बन सकता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब यह शहर बना था तो उस समय अनगिनत लेबर हॉस्टल बनें थे लेकिन जो ढह गए उनको हम नये सिरे से नहीं बना पाए। जिन पर कब्जा हो गया था, उनको भी हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से मजदूरों को देना पड़ा। यह शहर कुछ लोगों का नहीं है, जो भी इस शहर में आएगा चाहे वह कश्मीर, सिरमौर,बिलासपुर या पहाड़ से आएगा यह उसका शहर है और उसको इस शहर के अंदर जगह भी देनी पड़ेगी। नियम-130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव श्री विक्रमादित्य सिंह व अन्य माननीय सदस्यों ने इस सदन में लाया गया है, मैं इसका जोरदार समर्थन करता हूं। मैं इच्छा करता हूं कि हमारा शहर स्मार्ट रहे और यह स्मार्ट तब रहेगा जब हम इसके तौर-तरीके अख्तियार करेंगे। हमने स्मार्ट सिटी बनाने के सिलसिले में कुछ ऐसी मशीनें खरीद दी जिनकी कीमत 3-4 करोड़ रुपये हैं। वे रिज पर घूमती रहती है लेकिन सफाई नहीं कर पाती। We are only wasting money in the name of the Smart City. जो पैसा आ रहा है उसको बर्बाद किया जा रहा है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

02/03/2022/1555/टी0सी0वी0/ए0जी0/2

सभापति : अब इस चर्चा में श्री बलबीर सिंह वर्मा जी भाग लेंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्मा, चौपाल : सभापति महोदय, श्री विक्रमादित्य सिंह, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, श्री जगत सिंह नेगी, श्री संजय अवस्थी, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी द्वारा जो प्रस्ताव नियम-130 के अंतर्गत "शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत हो रहे विकासात्मक कार्यों पर यह सदन विचार करे।" सदन में प्रस्तुत किया है इस पर चर्चा

करने के लिए आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद। विपक्ष के माननीय सदस्यों को इसके लिए आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए था। उन्होंने वर्ष 2015 में देश के अंदर 'स्मार्ट सिटी नाम से एक नई योजना लाई। जिन्होंने 60 साल राज किया उन्होंने ऐसी योजना क्यों नहीं लाई? मैं जब उधर था तो वर्ष 2015 से यह स्मार्ट सिटी का प्रोजैक्ट शुरू हो रहा था लेकिन शिमला शहर में स्मार्ट सिटी का काम तभी से दिखा, जब से श्री सुरेश भारद्वाज जी ने चार्ज संभाला। उसके बाद ही सड़कें चौड़ी हुई और यह लगा कि शिमला स्मार्ट बन रहा है। ब्रिटिश सरकार ने 1815 में एक छोटा-सा टाउन शिमला को बनाया था जिसकी आबादी 30 हजार थी लेकिन जिन्होंने आजादी के बाद 60 साल राज किया उन्होंने शिमला की तरफ नहीं देखा। इन्होंने अभी जितनी भी बिल्डिंग्ज गिनी है वे अंग्रेजों ने बनाई हैं। मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। ...व्यवधान...

एन0एस0 द्वारा ... जारी

02-03-2022/1600/NS/AG/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा .....जारी

डवलपमैंट प्लान बनाने के लिए मैं 25 सालों से सुन रहा हूं कि डवलपमैंट प्लान आ रहा है। आज तक पिछली सरकार ने नहीं लाया। मैं मुख्य मंत्री जी और शहरी विकास मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर दी और आने वाले समय में शिमला सिटी में यह इंप्लीमैंट होगा। 40 सालों से जो कार्य नहीं हुआ उसे मंत्री जी ने कर दिखाया। इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। स्मार्ट सिटी में देश के प्रधान मंत्री जी ने 2905 करोड़ रुपये शिमला सिटी की डवलपमैंट के लिए दिए हैं। आप आजादी से आज तक देखो कि शिमला सिटी के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट कब मिला और किस सरकार ने दिया? ...व्यवधान...

सभापति : श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी इनको बोलने दें। आप जब बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था। आपने भी आंकड़े दिए हैं तो इन्होंने बीच में कुछ नहीं बोला। आप इनको बोलने दो।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि इसकी फंडिंग 50:50 है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि इसकी फंडिंग 90:10 होनी चाहिए। आने

वाले समय में 90:10 होगी। एक बात देखने वाली है कि उस शहर के लिए जिसे अंग्रेजों ने बना के छोड़ा था और जिन्होंने 60 साल प्रदेश में राज किया उन्होंने इस शहर के लिए कुछ नहीं किया और नरेन्द्र मोदी जी ने एकमुश्त पैसा दिया तो उसकी इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। सभापति महोदय, एक साल के अंदर ही शिमला शहर की काया पलट हो गई। अंग्रेजों ने शिमला शहर की सुंदरता को देखते हुए इसे छः महीने के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था तथा सुरेश भारद्वाज जी इसकी भव्यता को बनाए रखने के लिए इंप्लीमैंट कर रहे हैं। मैं आज देख रहा हूं कि शिमला शहर में जिस तरह से सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है और रोड में ओवर ब्रिज बने रहे हैं, रिटेनिंग वाल और ब्रेस्ट वाल लग रहीं हैं। मैं भी 25 सालों से देख रहा हूं कि यहां पर डेली ट्रेफिक जाम लगता था लेकिन शहरी विकास मंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि आने वाले समय में शिमला शहर में कभी ट्रेफिक जाम नहीं लगेगा।

सभापति महोदय, शिमला शहर में पहले पार्किंग सुविधा नहीं थी। टूरिस्ट बाहर से आते थे तो उनके लिए पार्किंग की सुविधा नहीं थी। स्मार्ट सिटी में अब 12 बड़ी

02-03-2022/1600/NS/AG/2

पार्किंग्ज़ बन रही हैं और छोटी पार्किंग्ज़ भी बन रही हैं तथा सब-वे भी बन रहे हैं। क्या किसी ने सोचा था कि संजौली से ले करके आई.जी.एम.सी. तक रास्ते के लिए टोप रूफ होगा। ऐसे यू.एस.ए. में भी बहुत कम बने हुए हैं। ऐसा कार्य शिमला शहर के अंदर भारद्वाज जी करवा रहे हैं। हिल एरिया में इस तरह से रोपवे, ओवर ब्रिजिज़, पार्किंग और टनल के कार्य हो रहे हैं। जिन्होंने 60 साल राज किया उन्होंने आज तक एक ही टनल रखी हुई थी वह भी अंग्रेजों की बनाई हुई थी। अरे भाई, उस सयम एक गैंती तो दूसरी टनल में लगवा लेते। मैं, इसके लिए श्री सुरेश भारद्वाज जी का धन्यवाद करता हूं। संजौली में एक टनल की वजह से दो घंटें तक ट्रेफिक जाम रहता था लेकिन आने वाले समय में उस जाम से निजात मिलेगी। मैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी और शहरी विकास मंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस योजना को इस तरह से शुरू किया कि ऐसे लगता है कि सुरेश भारद्वाज जी के आशीर्वाद से ही शिमला चौड़ा होना था और इसका विकास होना था। इस प्रोजेक्ट में सीवरेज, सोलिड बेस्ड मेनेजमैंट का प्रोवीजन है। सभापति महोदय, इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी दिक्कतें आईं। इसमें एन.जी.टी. की वजह से

भी बहुत सारी दिक्कतें आईं फिर भी मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी इसमें व्यक्तिगत रूचि लेकर हर चीज़ को इंप्लीमैंट कर रहे हैं

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी

02.03.2022/1605/RKS/एएस-1

श्री बलबीर सिंह वर्मा... जारी

और हर चीज़ में ध्यान दे रहे हैं। शिमला शहर की दो तरह से अहमियत है। हिन्दुस्तान में शिमला को सेब बैल्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा गर्मी में सर्दी का मजा लेने और सर्दी में बर्फ देखने के लिए विश्वभर से पर्यटक यहां घूमने आते हैं। वैसे सालभर यहां पर्यटक घूमने आते रहते हैं। पहले जब शिमला में एक हजार गाड़ियां एक साथ आ जाती थी तो पूरे शिमला में ट्रैफिक जाम हो जाता था। लेकिन जब से शिमला शहर की सड़कें चौड़ी हो रही हैं तब से ट्रैफिक जाम से काफी निज़ात मिल रही है। पूर्व में मेरे विपक्ष के साथी जो कह रहे थे उससे ऐसा लगता है जैसे इनकी सरकार ने कभी शासन ही नहीं किया हो। आप सुबह-शाम इन्हीं सड़कों से आते-जाते हैं। आपको एक बार इन सड़कों में जरूर नज़र डालनी चाहिए कि जो 70-72 वर्षों से नहीं हुआ, वह अब हो रहा है। इन विकासात्मक कार्यों के पीछे जिस सरकार का आशीर्वाद है, उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। हर चीज़ की बुराई करना ठीक नहीं है। कुछ मित्रों ने कहा कि इनकी नीयत और नीति दोनों ही खराब है। माननीय सुरेश भारद्वाज जी को पूरे देश में जाना जाता है। इनकी नीति और नीयत बिल्कुल साफ है और जिस भाव और कर्म से यह काम करते हैं उस भाव से बहुत कम लोग राजनीतिक सैट-अप में काम करते हैं। जिस तरह से शिमला शहर का विकास हुआ है उससे हताश होकर अब ये छींटाकशी कर रहे हैं। इस विकास को यह सहन नहीं कर पा रहे हैं और इससे इनके अंदर यह बौखलाहट पैदा हुई है। सभापति महोदय, आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

02.03.2022/1605/RKS/एएस-2

सभापति : अब माननीय शहरी विकास मंत्री इस चर्चा का उत्तर देंगे।

शहरी विकास मंत्री : सभापति महोदय, नियम-130 के अंतर्गत श्री विक्रमादित्य सिंह, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, श्री जगत सिंह नेगी, श्री संजय अवस्थी, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, श्री बलबीर सिंह वर्मा और श्री राकेश सिंघा जी ने जो "शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत हो रहे विकासात्मक कार्यों पर अपने विचार रखे, उस पर आपने मुझे उत्तर देने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद। शिमला के बारे में बात करने वाले तीन माननीय सदस्य, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल और श्री राकेश सिंघा नगर निगम, शिमला के पार्षद रह चुके हैं। पार्षद होने के नाते ये शिमला शहर से जुड़े हैं और यहां की सभी प्रकार की समस्याओं के बारे में अच्छी तरह जानते हैं।

श्री बी.एस.द्वारा.. जारी

02.03.2022/1610/बी.एस./ए0एस0/-1

शहरी विकास मंत्री जारी...

उसके लिए आप के सुझाव जो मान्य सदन में और सदन के बाहर दिए जाते हैं, वे बहुत ही बहुमूल्य होते हैं उनका लाभ उठा करके हम सरकार में या नगर निगम के किसी भी प्रोजैक्ट में शहरी की बेहतरी के लिए लाते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज भी बहुत से मूल्यावान सुझाव दिए गए हैं। बोलने में भाषा अपनी-अपनी हो सकती है, क्योंकि माननीय जगत सिंह नेगी जी मेरी तरह ऐसे प्रोफैशन से जुड़े हैं जिसमें हम सीधा-सीधा सर्मथन किसी का नहीं कर सकते हैं। माननीय सभपति जी, आदरणीय ब्राक्टा जी, आदरणीय नरेन्द्र ठाकुर जी भी यहां पर बैठे हैं, इन्होंने भी काफी समय तक वकालत की है। मैं समझता हूं कि माननीय नेगी जी ने भी अपने शब्दों में कहा और ये विरोधी पक्ष में हैं तो अच्छी बात को भी वे अपने तरीके से कहेंगे। शिमला शहर को जितना पुराना कहा जाता है,

यह उतना पुराना नहीं है, इसका इतिहास डेढ़-दो सौ साल पुराना है। शामला नाम की देवी थी, उसके नाम से गांव था, अंग्रेज फोर्ट विलियम में अपनी राजधानी चलाते थे, वहां पर गर्मी होती थी लंदन के रहने वाले गर्मी शहन नहीं कर पाते थे, इसलिए सारे देश में उन्होंने ठण्डे स्थानों को ढूंढना शुरू किया। वे नैनीताल, डलहौजी गए और बाद में शिमला में आए और शिमला को उन्होंने आपनी राजधानी के रूप में चयनित कर लिया। उस वक्त उन्होंने बहुत सारे भवन बनाए, उनमें कनेडी हाउस भी था, वह जलकर राख हो गया और यहां पर हमने जवाहर सदन बना दिया। जहां पर आज आई0जी0एम0सी0 है, वहां पर स्नोडेन अस्पताल हुआ करता था, उसे जंगी लाट का भवन कहा जाता था। कमांडर-इन- चीफ गर्मियों में वहां आ करके रहता था, वह भवन भी जल गया। उसकी जगह बहुत बड़ा अस्पताल बन गया है। सभी सरकारों ने इसमें अपने समय में काम किया है। उसमें एक सरकार ने ही काम नहीं किया है। शिमला शहर 1966 तक पंजाब राज्य के अन्तर्गत आता था, यह तो पंजाब का एक जिला हुआ करता था। उसमें जब हिमाचल प्रदेश में रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बाकी हिस्से मिले तो शिमला भी

02.03.2022/1610/बी.एस./ए0एस0/-2

उसमें मिल गया और इसे राजधानी बना दिया गया। हम बहुत सारे लोग जानते हैं, शायद विक्रमादित्य सिंह जी को तो नहीं देखना पड़ा होगा, क्योंकि ये राजवंश से आते हैं। इनके पास हॉली लॉज कोठी नजदीक थी। परंतु जो हमारे जैसा असामान्य वर्ग का व्यक्ति है, उन्हें तो माल रोड पर जाने ही नहीं दिया जाता था। वहां पर पेजामा पहनकर कोई जा ही नहीं सकता था। वहां पर राय साहब और राय बहादुर ही घुमा करते थे। इसलिए लोअर बाजार बस गया, राम बाजार बस गया और रिपन अस्पताल भी नया बन गया, जिसे आज दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल कहा जाता है। उन्हें काम करने के लिए लोग चाहिए थे, नीचे लद्दाखी मोहल्ला बन गया। वहां लद्दाखी मस्जिद भी है और वहां पर बाल्मिकी समाज के लोग जो सफाई किया करते थे उन्हें वहां रहने की जगह दे दी। शिमला बहुत छोटा सा

शहर था, इसलिए अंग्रेजों ने जो सुविधाएं प्रदान की वह 35 हजार की आबादी के लिए प्रादान की थीं, चाहे बिजली का प्रोजैक्ट

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी..

02-03-2022/1615/डी.सी.-ए.जी. /1

शहरी विकास मंत्री..... जारी

चाबा में बनाया, चाहे पानी की स्कीम बनाई। लेकिन यह ठीक है कि उस समय उन्होंने अनुमान लगाया होगा कि शिमला की जनसंख्या 35,000 भी हो सकती है और उसके अनुसार उन्होंने अपने रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था यहां पर की थी। उस समय गाड़ियां नहीं चलती थी और रिक्शा चलते थे, हो सकता है कि शायद कोई अंग्रेज घोड़ा गाड़ी में चलता हो, लेकिन रिक्शा चलते हुए तो हमने भी देखे हैं। वर्ष 1965-66 के समय तक रिक्शा को दो आदमी आगे व दो आदमी पीछे से धक्का देकर चलाते थे। अभी भी एक रिक्शा हैरिटेज़ के रूप में शिमला में रखा हुआ है। वर्ष 1966 के बाद जब रिऑग्रेनाइजेशन हुआ और शिमला हिमाचल प्रदेश में मिला तो इसका विकास व एक्सपैंशन शुरू हो गया। वर्ष 1971 में उस समय के मुख्य मंत्री डॉ0 वाई.एस. परमार जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा प्राप्त हुआ और हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बन गया। तब शिमला को हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनाया गया और यदि उस समय यह सोचा होता कि राजधानी को कहीं सैन्ट्रल प्लेस में ले जाएं तो शायद आज यह टूरिस्ट प्लेस ही रहता। यह एक जिला का हैड क्वाटर होता, टूरिस्ट प्लेस होता और इतनी भीड़-भाड़ भी न होती। उस समय यह राजधानी बन गई और राजनीतिक सैंटर बन गया। उसके बाद पे-कमीशन्ज़ आने लगे, लोगों की सैलरीज़ बढ़ने लगी, लोगों की शिक्षा के प्रति भूख बढ़ने लगी, लोगों की आर्थिकी बढ़ने लगी और शिमला बसना शुरू हो गया। माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी अभी स्मिट्री की बात कर रहे थे और यह बात बिलकुल ठीक है कि वहां पर स्मिट्री होती थी। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तब वहां से जाते हुए डर लगता

था क्योंकि वहां पर कब्रें-ही-कब्रें होती थीं। लेकिन आज वहां पर पूरा-का-पूरा वार्ड बन गया है। यह भी सच है कि वहां पर लाश को उठाने के लिए एक लैंटर से दूसरे लैंटर को पार करना पड़ता है। वहां किसी मृत व्यक्ति को कंधे पर उठा कर नहीं ले जा सकते। माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी अभी कच्चीघाटी का जिक्र कर रहे थे।

02-03-2022/1615/डी.सी.-ए.जी. /2

अब वहां पर भवन कैसे बन गए हैं क्योंकि जब स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे उस समय वहां पर दो बिल्डिंग्स गिरी हुई थीं। वहां पर कोई कोर्ट में चला गया या किसी ने कुछ किया और फिर उसके बाद रिटेंशन्ज़ पॉलिसिज़ बननी शुरू हो गई। अभी भी वहां पर कुछ बिल्डिंग गिर जाती हैं और अभी कुछ समय पहले ही मेरे व माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी के सामने एक बिल्डिंग धराशाही हो गई थी। शिमला इस तेजी के साथ बस गया कि उसकी जरूरतें समय पर पूरी नहीं हो सकी। समय के साथ-साथ यहां पर पानी की कमी होने लगी। पहले शिमला में पानी चैड़ व गुम्मा से आता था। उसके बाद वर्ष 1990 में अश्वनी खड्ड से एक योजना बना कर पानी लिया लेकिन उसके नजदीक एस.टी.पी. बन गया और शिमला में जोंडिस फैल गया। सारा सीवरेज़ का पानी उसमें मिल गया और उस पानी को बंद करना पड़ा। शिमला में गिरी नदी से पानी की स्कीम बनाई गई। इतना सब कुछ बनने के बाद भी शिमला में पानी पूरा नहीं हो रहा है। फिर पानी चाबा से गुम्मा में डालना पड़ा ताकि यदि सोर्स बंद हो जाए तो शिमला में पानी की सप्लाई न रूके। लेकिन अब हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है और हम यहां पर चर्चा करते थे कि चन्द्रनाहन से पानी लेकर आएंगे या पब्बर से पानी लेकर आएंगे, इस बात का माननीय श्री राम लाल ठाकुर जी को ध्यान होगा, फिर दूसरी चर्चा चली की सतलुज से पानी उठाया जाए और अभी तो कोस्टली पड़ेगा लेकिन बाद में यह ठीक रहेगा। हमने कोविड काल में भी प्रयत्न किया कि शिमला में पानी की सप्लाई सतलुज से आए और उसके लिए 180 मिलियन डॉलर, यानि के लगभग 1200 करोड़ रुपये शिमला वाटर सप्लाई के लिए स्वीकृत हो गए हैं जिसका काम आज प्रगति पर है। इस योजना का कुल खर्च लगभग 1813

करोड़ रुपये है। इस योजना को वर्ष 2050 तक का विज़न रखकर बनाया गया है ताकि शिमला को पानी की सप्लाई निरंतर मिलती रहे। क्योंकि नजदीक के छोटे-छोटे सोर्सिज़ से शिमला का पानी पूरा नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से समय-समय पर

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

02.03.2022/1620/JK/DC/1

शहरी विकास मंत्रीः-----जारी-----

शिमला को दुरूस्त करने के लिए, गाड़ियां चलती हैं और किसी ज़माने में जैसे कि मैंने कहा कि रिक्शा चला करता था। मैं जब पैदा हुआ था तो मेरी माँ को भी होलीलॉज से के.एन.एच. तक रिक्शा में ही ले गए थे और वापिस भी उसी में लाए थे। लेकिन आज वहां पर गाड़ी जाती है। यदि गाड़ी जाएगी तो उसके लिए सड़कें चौड़ी होंगी। इसलिए यह सारा देखना पड़ा और जब डॉ0 मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे तब जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना आई थी। वह योजना बेस्ड एक पूरी योजना थी जिसमें यदि आप कोई स्कीम भेजेंगे, उस स्कीम को सैंक्शन हो करके पैसा मिलेगा, आप करेंगे। लेकिन शहर का दुर्भाग्य है, उस वक्त भी पानी की स्कीम सैंक्शन हो करके आ गई थी। 154 करोड़ केन्द्र सरकार से मिल गया था लेकिन दुर्भाग्य से उस समय नगर निगम पर कब्जा माननीय राकेश सिंघा जी का था, वह पैसा वापिस चला गया। वह कहते हैं कि जो उनकी स्कीम है उसमें तो प्राइवेट पार्टी करेगी। कोई कंसल्टैंट आएगा, कुछ और आएगा, बनने ही नहीं दी। वह पैसा वापिस चला गया और वह स्कीम नहीं बन पाई। 3900 करोड़ रूपये के पूरे प्रोजैक्ट्स उसके बनाए थे, उसकी प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाई थी लेकिन पैसे के लिए, जो केन्द्र को स्कीम्ज़ जानी चाहिए थी, वे नहीं गई। अगर वह स्कीम गई होती तो आज स्मार्ट सिटी का प्रोजैक्ट ही नहीं आता। जे.एन.एन.यू.आर.एम. में ही इतना ज्यादा पैसा आ जाता कि शिमला अपने आप में खूबसूरत और स्मार्ट रहने लायक हो जाता। इस कारण से जब वर्ष 2014 में आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने सत्ता सम्भाली तो उन्होंने बाकी योजनाओं के साथ-साथ सारे देश के

100 शहरों को स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत लाया और कहा कि उनको केन्द्र व प्रदेश सरकार मिल करके वित्त पोषित करके उन योजनाओं पर काम करें और शहरों को स्मार्ट सोल्युशन्ज़ दें, स्मार्ट बनाएं और वह स्थान रहने लायक बन सकें। यह कार्य वर्ष 2014 से शुरू हुआ। उसके फर्स्ट फेज़ में, श्री सिंघा जी की बात का मैं समर्थन करता हूं और आपको बताता हूं कि उसमें 37 नम्बर नहीं थे उसमें 87 शिमला के थे और 82 नम्बर धर्मशाला

02.03.2022/1620/JK/DC/2

के थे। लेकिन इतना माइलेज मंत्री को देना ही पड़ेगा कि 4-5 नम्बर ऊपर-नीचे कर दें। इसलिए उस समय मंत्री धर्मशाला से थे और पहला नम्बर धर्मशाला का लग गया। उन्होंने ऊपर-नीचे कर दिया। यह रिकॉर्ड पर है। जब वह धर्मशाला में गया, हमारा धर्मशाला से कोई विरोध नहीं है। धर्मशाला भी होना चाहिए, शिमला भी होना चाहिए, मण्डी भी होना चाहिए, सोलन भी होना चाहिए, इसमें पालमपुर भी हो सकता है और बिलासपुर भी हो सकता है। मैं तो यह चाहता हूं कि श्री जगत सिंह नेगी जी का रिकांगपिओ को भी नगर बना दिया जाए लेकिन ये मानते नहीं है। लेकिन जब वह स्मार्ट सिटी में चला गया तो उसमें हमारे जो वर्तमान उप राष्ट्रपति हैं, आदरणीय वैकैंया नायडू जी, उनसे हम मिले। मैंने कहा कि स्मार्ट सिटी का प्रोजैक्ट हमारे शिमला को मिलना चाहिए था, धर्मशला को मिल गया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी तो कॉंपिटिशन में मिलता है, जिसको मिल गया है उसको अब मिल गया है। हम तुम्हें AMRUT में दे देते हैं। शिमला और कुल्लू AMRUT योजना जो केन्द्र की वित्तपोषित योजना थी, उसमें प्रोजैक्ट यहां से भेजेंगे और हमने नालों की चैनेलाइजेशन का प्रोजैक्ट भेजा, उसका पैसा आ गया। लगभग 232 करोड़ रुपये के काम AMRUT योजना के तहत हुए हैं। सारे काम जो आज दिखाई दे रहे हैं वे सारे-के-सारे स्मार्ट सिटी के नहीं हैं। कुछ उसमें AMRUT के हैं, जो नगर निगम ही कर रहा है। लेकिन उसके बाद नगर निगम ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने और हम सबने मिल कर अपना अभियान चलाया कि स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट मिलना चाहिए, वह हमने जारी रखा। उसके

अन्तर्गत पब्लिक पार्टिसिपेशन किया। पाब्लिक पार्टिसिपेशन डायरैक्ट अंगेजमैंट के द्वारा भी, फेस बुक के द्वारा भी, व्हट्स ऐप के द्वारा भी, बाकी ऐप्स के द्वारा यानि इन सभी चीजों द्वारा शिमला पाब्लिक को कांटैक्ट किया, जिसमें 1,01,561 लोगों ने पार्टिसिपेट किया कि कैसा होना चाहिए, शिमला की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, स्मार्ट सिटी में क्या-क्या हो सकता है, इसमें हमने भी, उस समय मैं एम.एल.ए. था और मैंने भी पब्लिक मैन की तरह पार्टिसिपेट किया,

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

02.03.2022/1625/SS-HK/1

शहरी विकास मंत्री क्रमागत :

शिमला नगर-निगम के सभी पार्षदों ने भी पार्टिसिपेट किया। मेरे ख्याल में उस वक्त राजा साहब चीफ मिनिस्टर थे इसलिए उनसे तो एप्रूवल ही होनी थी। अनिरूद्ध सिंह जी का भी इसमें बहुत सहयोग रहा। सबने मिलकर प्रयत्न किया और उसका परिणाम यह हुआ कि शिमला को थर्ड राउंड में स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट मिल गया। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्ज को शिमला स्मार्ट सिटी की प्रॅपोजल 31.3.2018 को फाइनली सौंपी गई थी कि क्या-क्या इसमें होगा। पब्लिक पार्टिसिपेशन के द्वारा जो बताया गया था उसमें बहुत सारे कम्पोनेंट थे। मैं एक-एक कम्पोनेंट को बताता हूं। Traffic congestion, public transport, parking and pedestrian movement इस पर 27.97 परसैंट था। Availability of potable water supply के लिए 22.07 परसैंट था। Solid waste and sewerage management 13.13 percent. Safety of biddings and citizens 8.53 percent, open and recreational spaces इसके लिए -5.38 परसैंट; ये लोगों ने अपने सुझाव दिए। उसी के अनुरूप आज हम स्मार्ट सिटी में काम कर रहे हैं। नेगी जी ने शायद कहा कि कंसल्टैंट को पैसा देते हैं। Shimla Smart City is the only smart city project where no consultant has been appointed. बाकी सब जगह कंसल्टैंट एप्वाइंट किए

हुए हैं। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजैक्ट के लिए कंसल्टैंट की आवश्यकता हुई तो उसके लिए कंसल्टैंट करते हैं otherwise no consultant, क्योंकि हमने दफ्तर का काम नहीं किया, अपना स्मार्ट सिटी दफ्तर नहीं बनाया। उसमें बहुत ही कम स्टाफ है जो मोनिटरिंग करता है या पेमेंट करनी है, ऊपर से पैसा आना है, स्टेट गवर्नमैंट से आना है; उतने काम के लिए स्टाफ रखा है बाकी कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है। केवल जनरल मैनेजर था, वह भी डपुटेशन पर था और अब वह भी चला गया। स्मार्ट सिटी के बाकी सारे-के-सारे काम हिमाचल प्रदेश सरकार के जो विभिन्न डिपार्टमैंट्स हैं उनको सौंपे हुए हैं। सबको अलग-अलग काम सौंपे हुए हैं। इस काम को सिर्फ एक डिपार्टमैंट नहीं देख रहा है।

02.03.2022/1625/SS-HK/2

मैं आपको बताता हूं कि लोक निर्माण विभाग का जो फोर्थ सर्कल है इसके पास 64 स्कीम्स के डिफरेंट काम सौंपे हुए हैं। लोक निर्माण विभाग का राष्ट्रीय उच्च मार्ग वाला जो डिवीजन है उनके पास 8 काम हैं। लोक निर्माण विभाग का जो यांत्रिक विंग है उसके पास 4 काम हैं। रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डवलमैंट कारपोरेशन के पास 22 काम हैं। आवास और शहरी विकास प्राधिकरण के पास 13 काम हैं। नगर-निगम शिमला के पास भी काम सौंपे हैं कि वे भी काम करके दें। उनके पास 20 काम हैं। शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के पास अभी तक स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 7 काम हैं, आगे से उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सीवरेज और पानी की हमारी अलग स्कीम बन गई है जिसका उनके पास 1813 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट है। अम्रुत मिशन फेस-2 में सीवरेज व पानी का ही काम होगा, वही काम उनको जाएगा। स्मार्ट सिटी से उनके पास आगे के लिए कोई काम नहीं होगा। ऊर्जा विकास एजेंसी है उसके पास तीन काम दिए हुए हैं। राज्य इलैक्ट्रोनिक विकास निगम के पास दो काम हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पास दो काम हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास भी 12 काम हैं क्योंकि शिमला में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। यहां पर बहुत सारी लैंड सी0पी0डब्ल्यू0डी0 की है। जब लोग विधायक निधि से भी छोटा पैडस्ट्रियन पाथ मांगते हैं तो वे वहां पर पाथ नहीं बनाने देते। वे अपनी जमीन पर सुई भी

नहीं चुभोने देते। इसलिए हमने कहा कि जहां इनकी जमीन है वह काम ही हम सी0पी0डब्ल्यू0डी0 को सौंप दें। इसलिए इन्द्र दत्त लखनपाल जी आपने चक्कर जाते हुए देखा होगा कि जितना काम हो रहा है वह सारा सी0पी0डब्ल्यू0डी0 कर रहा है। नीचे खलीनी का काम वह ही कर रहा है। नीचे नाले की चैनेलाइजेशन का अब एफ0सी0ए0 केस हो गया है तो वह भी सी0पी0डब्ल्यू0डी0 को सौंप रखा है। इसलिए हमने सारे काम डिफरेंट डिपार्टमैंट्स को सौंप रखे हैं

जारी श्रीमती के0एस0

02.03.2022/1630/केएस/एचके/1

शहरी विकास मंत्री जारी---

स्वास्थ्य विभाग के पास एक काम है। युवा संवाएं एवं खेल विभाग के पास एक काम है। हिमाचल प्रदेश रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमैंट कॉर्पोरेशन के पास 48 करोड़ रुपये का एक काम है। माननीय बलबीर सिंह वर्मा जी ने ठीक कहा कि शिमला में 170 साल पुरानी संजौली से ढली को मिलाने वाली सूरंग है जो शिमला को पूरे अप्पर शिमला और किन्नौर से जोड़ती है, वहां पानी का रिसाव शुरू हो गया है इसलिए वहां पर पेरलल सुरंग बनाई जा रही है ताकि सारा पहाड़ का एरिया शिमला के साथ जुड़ा रहे और उसका 48 करोड़ रुपये का काम हम शुरू करने वाले हैं जो कि उपरोक्त कॉर्पोरेशन को सौंप रखा है और उसको हम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाएंगे। पहले वाली सुरंग भी रहेगी और नई उसके पैरलल बनेगी। ...(व्यवधान)... मकानों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखते जाइए। भूमि अधिग्रहण का भी एक काम है। पुलिस विभाग को दो काम दे रखे हैं। पथ परिवहन निगम के पास एक काम है, राज्य विद्युत बोर्ड को भी काम दे रखा है। इसलिए शिमला स्मार्ट सिटी का एक न्यूक्लियस ऑफिस सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए है। वह काम स्वयं नहीं कर रहा है जैसे बाकी स्मार्ट सिटीज़ में कन्सल्टैंट अप्वाइंट करके वे कर रहे हैं और सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हमने सारे के सारे जैसे बाकी गवर्नमैंट के काम होते हैं, उसी

तरह से दिए हैं। सवाल सिर्फ यह है कि इनको वहां से पैसा मिल जाता है इसलिए काम जल्दी हो जाता है। मोनिटरिंग सी.ई.ओ. भी करता है, हमारा प्रिंसिपल सैक्रेटरी भी करता है और मैं स्वयं भी, क्योंकि मैं यहां से विधायक हूं, इसलिए मेरा इंट्रस्ट थोड़ा ज्यादा है इसलिए मैं भी इसकी मोनिटरिंग करता हूं। कॉर्पोरेशन के हमारे पार्षद भी अपने-अपने स्थानों पर मोनिटरिंग करते हैं। इसलिए सारे डिफरेंट डिपार्टमैंट्स में स्मार्ट सिटी के काम हो रहे हैं।

सभापति महोदय, जैसे मैंने कहा कि लोगों की ज्यादा कन्जैशन है। शिमला में कन्जैशन सबसे बड़ी समस्या है। नेगी जी ने ठीक कहा, जो इनका प्वाइंट है, मैं वहां 10 साल रहा

02.03.2022/1630/केएस/एचके/2

हूं, मुझे पता है वहां पर अगली और पिछली दोनों साइडों से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आती है, बीच में रहने वाला मुश्किल में होता है लेकिन वहां पर आगे की साइड को रेलवे वालों की बिल्डिंग्ज़ हैं और पीछे की तरफ सी.पी.डब्ल्यू.डी. की बिल्डिंग और विधायक सदन है। आप सोसायटी के अध्यक्ष हैं, अगर आप कहीं नया विधायक सदन बनवा देंगे तो हम उस सदन को तोड़कर वहां पर सड़क को चौड़ा कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि पहले रीहेबिलिटेशन आपकी और मेरी करनी पड़ेगी। जब ऐसा हो जाएगा तभी वह चौड़ा हो पाएगा। बाकी उसके पीछे के लिए भी हमने एक प्रपोज़ल दे रखी है। अगर वह सेंक्शन हो गई तो हम वहां से रेलवे की अगर हमें जमीन मिल गई तो हमने उस पर फ्लाई ओवर की प्रपोज़ल भेज रखी है और हमें एक्सपैक्टेशन्ज़ हैं कि रेलवे मिनिस्ट्री से हमें उसकी अप्रूवल मिल जाएगी तो हम उसको बना देंगे और स्मार्ट सिटी में उसका प्रोविज़न हमने ऑलरेडी किया है। कोशिश है कि कंजैशन को हटाया जाए। पेडेस्ट्रियन पाथ की लोग मांग करते हैं इसलिए हम सर्कुलर रोड में सभी जगह पेडेस्ट्रियन पाथ बना रहे हैं। हमने तो आपके दफ्तर के पास भी सड़क चौड़ी कर दी है। साथ में सबसे पहले पेडेस्ट्रियन पाथ भी हमने वहीं पर बनाया है। कहीं भी पिक एण्ड चूज़ नहीं किया है क्योंकि इसका कोई अर्थ भी नहीं बनता । सब जगह शिमला में जो एक स्थान पर जाएगा तो दूसरे स्थान पर भी जाएगा

और एक स्थान पर अगर उसको जगह चौड़ी मिल गई, दूसरी जगह नहीं मिली तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। इसलिए जहां-जहां सम्भव है, आसानी से हो सकता है लेकिन जहां सम्भव नहीं होता वहां पर थोड़ा मुश्किल आती है। एफ.सी.ए. की एक मुश्किल है क्योंकि शिमला का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है, 74 अमैंडमैंट की बात कर रहे थे तो उसमें अर्बन फोरैस्ट्री नगर निगम के पास आना चाहिए। शिमला का फोरैस्ट नगर निगम के पास था वह कांग्रेस सरकार के समय शायद उस वक्त राम लाल ठाकुर साहब फोरैस्ट मिनिस्टर थे, तब यह नगर निगम से छिनकर सरकार में चला गया फिर दोबारा से अर्बन फोरेस्ट्री

02.03.2022/1630/केएस/एचके/3

को वापिस ले आए थे लेकिन वर्ष 2013 में जब आपकी सरकार बनी तो फिर से वह वापिस चला गया। अब रिज का एरिया गिर रहा है। वहां पर पुराने जमाने की डेब्रिज है। उसके कारण पहले उसे सिंकिंग जोन कहा जाता था । वास्तव में वह सिंकिंग जोन नहीं है लेकिन डैब्रिज उसके नीचे बैठ जाती हैं और उसके कारण वह टिल्ट कर जाता है। हमने कई बार अनेक कोशिश करके देखीं

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

02.03.2022/1635/av/ag/1

शहरी विकास मंत्री ---------- जारी

फिर हमने उसको आई0आई0टी0 रुड़की को स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग के लिए भेजा। वहां से पूरी-की-पूरी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग इत्यादि करके उसका टैंडर कर रहे थे परंतु वन विभाग ने रोक दिया। अब हमारा काम तो रुक गया परंतु वन विभाग की तो एफिशिएंसी है। हालांकि वहां पर रुबिनिया के पेड़ थे और जाहिर सी बात है कि वह एफ0सी0ए0 में नहीं जाता है। मगर वन विभाग ने अपनी कार्रवाई पूरी करनी है इसलिए उनके साथ भी बातचीत

चली हुई है। अगर उसमें कोई नतीजा निकलता है तो ठीक है वरना एफ0सी0ए0 की परमिशन लेनी पड़ेगी। हमने तो फोरैस्ट वालों को भी कहा है कि पैसा ले लो और आप ही बना दो। अगर आपकी जमीन है तो इसको आप ही खड़ा कर दो क्योंकि यदि हमारा पानी का टैंक डैमेज हो गया तो पूरे शिमला का नुकसान हो सकता है। इसलिए जिस भी एजैंसी का है हम कहते हैं कि आप ही कीजिए। हमारा प्रयत्न है कि यह भी हो जाएगा जैसे हमारे यहां से बहुत सारी चीजों के लिए भेजे थे, उसमें हमारे संजौली से आई0जी0एम0सी0 वाले पाथ की भी रोकी थी परंतु अब वह परमिशन आ गई है। इसके अतिरिक्त जाखू में जो एसकेलेटर लगना था, उसकी परमिशन भी आ गई है। इसी प्रकार से लक्कड़ बाजार बस स्टैंड से लिफ्ट बन रही है। उसका काम चला हुआ है और अभी तक केवल 15 प्रतिशत काम ही हो पाया है । वहां पहले जमीन के नीचे खुदाई करने की जरूरत है बाकी ऊपर का काम ज्यादा दिक्कत वाला नहीं होता। इसी प्रकार से विकास नगर में आपने कभी देखा होगा, वहां पर पार्किंग की बहुत पहले एडवर्टाइज की हुई थी। मगर वह काम नहीं हुआ और वह ठप हो गया। मगर अब स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट के अंतर्गत वह पार्किंग भी बन रही है और उसके साथ-साथ वहां पर लिफ्ट भी बन गई है। वहां लिफ्ट और ओवर ब्रिज तथा फिर लिफ्ट व ओवर ब्रिज के साथ वह सीधा ब्रॉकहॉस्ट के पास पहुंचेगा। वहां पर पहले से काम लगा हुआ है और उसको आप लोग जाकर कभी भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से स्थान-स्थान पर स्मार्ट पाथ बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त पूरे शिमला में बुक कैफेज की आवश्यकता है। माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर

02.03.2022/1635/av/ag/2

बिजली बोर्ड में रहे हैं और इनको मालूम है कि छोटा शिमला के बीच बाजार में एक बिल्डिंग थी जिसमें बोर्ड के एक इम्प्लॉई रहते थे। उनसे वह बिल्डिंग खाली करवाकर उसको स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लिया गया है। अब उस बिल्डिंग में शॉपिंग कॉम्पलैक्स के साथ-साथ बुक कैफे भी है। ऐसे बहुत सारे प्रोजैक्ट्स हैं और मुझे लगता है कि मार्च माह के बाद आपको वे सारे काम दिखने शुरू हो जाएंगे। शिमला शहर की ट्रैफिक कंजैशन खत्म

करने के लिए रोड्ज की वाइडनिंग बहुत जरूरी है। यहां पर सड़कों के किनारे पहले से लगे हुए पत्थरों की बात कही गई। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि पत्थर का जिस-जिस डिपार्टमैंट को काम दिया गया है उन्होंने उसकी पहले से प्रोविजनिंग की है। उन्होंने ठेकेदारों से 500रुपये प्रति स्कवेयर मीट्रिक टन के हिसाब से पेमैंट ली हुई है तथा जिनसे नहीं ली गई है उनसे पत्थर रिकवर करते हैं। यह तो जिसका काम है उसको पता है। अब जितने भी प्रोजैक्ट्स बन रहे हैं उनकी टैंडरिंग ऑनलाइन हुई है और कोई भी काम ऑफलाइन नहीं दिया गया है। किसी एक भी ठेकेदार को ऑफलाइन काम नहीं दिया गया है बल्कि विभाग ही डिफ्रेंट हैं। इसलिए सारे काम ऑनलाइन प्रोसैस से दिए जाते हैं और मेरी जानकारी के मुताबिक आजकल के रेट्स से कम पर दिए हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सारे-के-सारे कार्य कंपीटैंट ऑथोरिटी द्वारा सैंक्शन किए जाते हैं। यहां पर माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल और श्री राकेश सिंघा जी ने नगर निगम की वर्किंग के बारे में बातें कही हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा आई0जी0एम0सी0 से संजौली का जो स्मार्ट पाथ है उसका एक्सपैंडिचर केवल 8.62 करोड़ रुपये है जबकि यहां पर 25-30 करोड़ रुपये कहा गया है। वह रास्ता 50 प्रतिशत से ज्यादा बन गया है और वह प्रोजैक्ट टोटल 15-16 करोड़ रुपये का है। पहले मैं भी यही सोचता था कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया है। इसके लिए एफ0सी0ए0 की परमिशन भी आ गई है।

टी सी द्वारा जारी

02/03/2022/1640/टी0सी0वी0/वाई0के0/1

शहरी विकास मंत्री .. जारी

आई0जी0एम0सी0 की पार्किंग 18.90 करोड़ रुपये में अवार्ड हुई है। यह ऑनलाइन प्रोसैस से अवार्ड हुई है और शिमला के एक प्रमुख ठेकेदार को मिली है। इसमें अभी तक 20 प्रतिशत कार्य ही हुआ है क्योंकि इसके साथ ही ट्रॉमा सेंटर का काम भी चल रहा था। अब इसकी गति तेज हो जाएगी। अभी तक इसका जो मलबा है उसको फेंकने के लिए डंपिंग साइट नहीं मिल रही थी। इसी तरह से Combermere और कृष्णा नगर के नाले का

चेनलाइजेशन भी की जा रही है। इसमें ऊपर से जो कूड़ा-कचरा आता है, वह कृष्णा नगर के पास इकट्ठा हो जाता है। इन नालों की चेनलाइजेशन का कार्य 10 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। शिमला शहर की जो सड़कें पहले से बनीं हुईं हैं वे रिक्शा चलाने या पैदल चलने के लिए बनीं थीं। यदि हम जोधा निवास से हॉली लॉज के लिए मोटरेबल रोड बनाएंगे तो उसमें पीछे की दीवारों को तोड़ना पड़ेगा वरना सड़क चौड़ी नहीं हो पाएगी। हम सड़कें चौड़ी करते जा रहे हैं लेकिन वहां पर गाड़ियां पार्क कर देते हैं और उनको रोकने में बहुत दिक्कत आ रही है। पुराने काम को दोबारा से करने में मुश्किल आती है जबकि नया कार्य करना आसान होता है। यहां सदन में कमांड सेंटर की जो बात की गई है, यह बहुत महत्वपूर्ण मांग है। इन्होंने सुझाव दिया है कि शिमला और धर्मशाला कमांड सेंटर को एक ही बनाया जाए। हालांकि, सचिवालय में जो बिल्डिंग बन रही है उसमें एक फ्लोर शिमला स्मार्ट सिटी सेंटर के लिए हैं जिसमें सारे स्मार्ट सोल्यूशनज होंगे। इसके तहत स्मार्ट ट्रैफिक की व्यवस्था भी होगी और इसके लिए हमने पुलिस विभाग को भी धनराशि दे दी है। सारे शहर में कैमरे लगाए जाएंगे और सारे शहर की ट्रैफिक को एक जगह बैठकर देखा जा सकेगा। ये सारी चीजें उस कमांड सेंटर से होंगी। धर्मशाला में अलग से बिल्डिंग बन रही है। इनके अंदर ट्रिपल आई0टी0 का सोल्यूशन अलग-अलग या इकट्ठा हो इस पर आपने सुझाव दिया है। मैं इस बारे में बोर्ड

02/03/2022/1640/टी0सी0वी0/वाई0के0/2

से बात करुंगा। Special Purpose Vehicle बनाया है वह भारत सरकार के प्रोजैक्ट के अंतर्गत ही आया है इसमें Special Purpose Vehicle बनेगी। इसमें उन्होंने इतना बदलाव किया है कि Special Purpose Vehicle डिविजनल कमीशनर की अध्यक्षता में न बनाकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाया है। दोनों जगह की जो एस0पी0वी0 है उसका बोर्ड मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बना है। उसमें हमारी नगर निगम के महापौर, उप महापौर

और कमीशनर मैंबर हैं। मैं, श्री अनिरुद्ध सिंह और श्री विक्रमादित्य सिंह जी भी जनरल बॉडी के मैंबर हैं। ये सारे-के-सारे असैटस जिस-जिस के लिए भी होंगे, उनको मिलेंगे।

एन0एस0 द्वारा ... जारी ।

02-03-2022/1645/NS/AG/1

शहरी विकास मंत्री .....जारी

ज्यादातर असैट्स नगर निगम को प्राप्त होंगे क्योंकि ये बनाने के बाद स्मार्ट सिटी में नहीं रहेंगे। ये बनाने के बाद नगर निगम के अधिकार में आ जाएगा और उसके बाद की मेंटेनैंस इनकी है और असैट भी इनका है। जो कुछ भी बन रहा है जैसे बुक कैफे आदि उसको नगर निगम चलाएगा। सारा काम बड़ी पारदर्शिता के साथ हो रहा है। आप सबका महत्वपूर्ण योगदान इसमें मिलता रहे क्योंकि शिमला किसी एक आदमी का नहीं बल्कि सबका है। मेरा यहां पर एक छोटा-सा फ्लैट है पर आप सब लोगों के बड़े-बड़े भवन हैं। इसलिए आप सबका भी इसमें उतना ही योगदान होना चाहिए जितना शिमला के बाकी नागरिकों का होता है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबने इस महत्वपूर्ण विषय पर जहां कमियां हैं उनको इंगित किया और हमारे अधिकारी उन कमियों को नोट कर रहे हैं तथा इस पर विचार करेंगे। हम भी इस पर कार्रवाई करेंगे। **अगर कहीं पर कोई गलत पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी इन्कवायरी नहीं होगी बल्कि उस पर कार्रवाई होगी और सजा होगी।** मैं आपको यह categorically बता रहा हूं लेकिन इसके लिए अगर हम off hand बात करके कह दें कि यह हो गया तो वह संभव नहीं है। यहां पर माननीय सदस्यों द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं। श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी, श्री जगत सिंह नेगी जी ने अच्छे सुझाव दिए हैं क्योंकि इनको वास्तव में शहर की जानकारी है। इनके सुझावों को नोट कर लिया है और उनके ऊपर हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। सभापति महोदय, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी ऐसा कोई प्रोवीजन नहीं है। इसमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। यह तो खत्म हो गया है। इसके लिए न तो को रूल है और न ही कोई प्रोवीजन है। हम ऐसे कैसे अलौ कर दें? अब आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। चलो बोल लो, आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। मंत्री महोदय ने डॉग हट के बारे में कुछ नहीं बोला और यह नगर निगम का हिस्सा है। सर, कच्ची घाटी से नीचे सीवरेज लाइन जा रही है और यह हर जगह से टूट जाती है तथा इससे ग्रामीण क्षेत्र के पेयजल स्रोत खराब हो रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा विचार करें।

02-03-2022/1645/NS/AG/2

शहरी विकास मंत्री : अब जो ठेकेदारी करते रहे हैं उनको ही इसके बारे में मालूम होगा। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कैसे पुल्लिंग होती है? आप लोगों को जानकारी होगी कि कैसे करते हैं? इसका कोई तरीका होगा कि कैसे रोकथाम की जा सकती है? इसके लिए आप मुझे अलग से सुझाव दे दें तो मैं विभाग से करवाने की कोशिश करूंगा । मैंने पहले भी कहा कि इससे संबंधित सारे-के-सारे डिपार्टमैंट्स मेरे पास नहीं हैं। ये अलग-अलग विभाग हैं जिनको हमने काम सौंप रखा है। डॉग हट, टूटीकंडी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय और बहुत सारे उच्च न्यायालयों के जजमैंट्स आए हैं और वे मोनिटरिंग भी करते हैं। किसी भी स्ट्रे डॉग को आप जबरदस्ती नहीं उठा सकते हैं। पहले इनको उठाने के लिए गाड़ी जाती थी। मैं नगर निगम से इस डॉग हट के बारे में जानकारी लूंगा कि यह फंक्शनल है या नहीं? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है और क्या इसको दोबारा बनाया जा सकता है? आपने सुझाव दिया है तो निश्चित रूप से नगर निगम से बात करके हल जरूर निकालेंगे। सीवरेज़ अगर कहीं पर लेफ्ट आउट है तो इसके लिए आप मुझे अलग से बता दें तो हम इसको कर देंगे क्योंकि सीवरेज लाइन कंपलीट हुई है और जहां पर लेफ्ट आउट पोर्शन्ज़ हैं वहां पर अगर रहती है तो एस.जे.पी.एन.एल. को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ही काम करने के लिए पैसा दिया गया है और उसको हम करवा देंगे। आप इसके लिए मुझे अलग से लिख कर दें तो हम नगर निगम के अंतर्गत इसकी व्यवस्था कर देंगे।

सभापति : शहरी विकास मंत्री जी धन्यवाद।

अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, 03 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला- 171004 **यशपाल शर्मा**

दिनांक : 02.03.2022 **सचिव।**